हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

31 अगस्त, 1993

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 31 अगस्त, 1993

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)20
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)24
वि ोशाधिकार प्रस्तावों/ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचनाएं देना	(2)27
वैयक्तिक स्पश्टीकरण– चौधरी ओम प्रका ा चौटाला द्वारा	(2)29
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– (1) पलवल क्षेत्र के आसपाल के गांवों में टिडडी दल के प्रकोप संबंधी	(2)33
वक्तव्य– कृशि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(2)34

(2) 10 अगस्त 1993 को नहरी जल की समस्या पर नारनौल के आई0टी0आई0 के प्रांगण में एक जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने संबंधी	
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(2)38
वाक आउट	(2)58
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा (पुनरारम्भ)	(2)59
स्थगन प्रस्ताव को नियम 84 के अधीन प्रस्ताव में परिर्वतन करना– राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी	(2)60
वर्श 1987–88 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)62
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा	(2)65
बैठक का समय बढ़ाना	(2)81
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84	(2)81

के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	
बैठक का समय बढ़ाना	(2)89
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)90
वाक आउट	(2)91
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)92
बैठक का समय बढ़ाना	(2)98
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)99
बैठक का समय बढ़ाना	(2)101
राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)101
एनैक्स चर 'ए'	(2)104

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 31 अगस्त, 1993

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Loss Suffered by Haryana Roadways

***557. Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Transport Department suffered any financial loss due to the pruchase/plying of Mini Buses during the year 1987 to 1990 in the State; if so, the total amount of loss suffered by the department; and

(b) whether the Government inteds to dispose off the said Mini Buses to avoid the further loss ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल भााह):

(क) जी हां। 31 मार्च, 1993 तक आठ करोड रूपये लगभग।

(ख) जी हां।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन मिनी बसों को खरीदने के लिए कोई ऐक्सपर्ट कमेटी बनायी गयी थी; अगर हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट थी ? क्या इस ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह बसिज खरीदी गयी थी या इस कमेटी की ओपीनियन के खिलाफ खरीदी गयी थी तथा उस दौरान कौन मन्त्री था ? क्या गवर्नमैंट यह महसूस करती है कि उस कमेटी की ओपिनियन के खिलाफ यह बसिज खरीदी गयी; अगर हां, तो गवर्नमैंट ने उस आदमी उस आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है और यह सबको पता भी है कि उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वे आजकल मुख्य मंत्री जी की पार्टी मे हैं, भाायद इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और वह फाईल आज तक पडी हुई है। कृपया मंत्री महोदय इस बारे में बताएं कि उनका क्या कहना है ?

श्री बलबीर पाल भााहः स्पीकर सर, इन्होंने कई प्र न पूछ लिए हैं ऐसा लगता है जैसे कोई भाशण दे रहे हों। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जून 1987 में जब चौधरी देवी लाल का राज था, एक मिनी बस ट्रायल के लिए खरीदी गयी थी। इस बस के 6 महीने चलने के बाद डिपार्टमैंट ने यह निर्णय दिया कि मिनी बस की रनिंग कास्ट 3 रूपये पर किलोमीअर है जबकि 100 परसैंट ऐक्यूपैंसी की रसीट 2.45 पेसे

है। डिपार्टमैंट ने बाकायदा यह साफ कर दिया कि यह घाटे का सौदा है लेकिन इसके बावजूद भी दिसम्बर 1987 में 60 मिनी बसिज खरीदने का आर्डर तीन कम्पनियों को दे दिया था। ये तीन कम्पनियां हैं– स्वराज माजदा, डी0सी0एम0 और ऐ ार। इन तीनों कम्पनियों से बीस बीस बसिज खरीदी गयी थीं। उसके बाद फिर जुलाई 88 में बसें खरीदीं गयी। स्पीकर साहब अगस्त 1989 में यह घाटा 58.49 लाख रूपये का था जो एक लाख रूपये फी बस प्रति वर्श बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगस्त 1989 में 500 बसिज खरीदने का निर्णय लिया गया तथा 40 बसिज दिसम्बर 1989 में खरीदी गयीं। इसके अलावा, 460 बसिज खरीदने का फरवरी 1990 में तीन फर्मों को आर्डर दिया गया, लेकिन केवल 174 बसें ही खरीदी। स्पीकर साहब जो बसिज खरीदते हैं, वे उनके लिए आई0डी0बी0आई0 से लोन लेते हैं लेकिन उस वक्त फाईनैंस डिपार्टमैंट ने भी मिनी बसों को खरीदने का विरोध किया था, फिर भी खरीदने के लिए पैसा दिया गया और 174 बसिज खरीदी गयीं। इस तरह से कुल 235 बसिज खरीदी गयीं। इन 235 बसिज से मार्च 1993 तक लगभग आठ करोड रूपये का घाटा हो चुका है। स्पीकरसाहब, पहले यह घाटा कम था क्योंकि ये बसें नयी थीं। लेकिन उसके बाद इसकी रिपेयर और मैंटीनैंस पर ज्यादा खर्चा आता गया इसलिए इनके लिए इनवैन्ट्री ज्यादा रखनी पडी। इन बसों के स्पयेर पार्टस, मैकेनिकस नहीं मिलते थे, साथ ही ये बसिज रोड कंडी ान के मुताबिक भी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से अब यह घाटा बढतार ही जा रहा है और आज की

तारीख में यह घाटा दो रूपये पर किलोमीटर है। इन बसों में से दस बसें मंडल कमी ान एजीटे ान मे ंजल गई। 8 बसें सोनीपत में और 2 रोहतक में जलीं। अब 225 बसें बकाया रह गई। उस समय सरकार ने निर्णय लिया कि इस घाटे के सौदे को खत्म कर दिया जाए और बसों को बेच दिया जाए, लेकिन बेचा बुक वैल्यू पर जाए ताकि आगे कोई व्यक्ति हम पर उंगली न उठा सके। लेकिन इन बसों को बेचने की हमारी कोि ा ा नाकाम रही, केवल 23 बसें ही बिक सकीं। बाकी की 202 बसें अभी भी डिपार्टमैंट के पास हैं, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये जो सामने क्रिकेट की टीम बैठी हुई है, अगली बार तो इन्होंनेा आना नहीं है, ये लोग ही इन बसों को बुक वैल्यू पर खरीद लें तो अच्छा है। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर सर, ये अपने भविश्य के बारे में कह रहे हैं अगली बार तो इन्होंने नहीं आना है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर पाल भााहः स्पीकर सर, मैं तो ट्रांसपोर्टर हूं, नहीं आऊंगा, तब भी मुझे वही काम करना है, मुण्े इस बात से कोई फर्क नहीं पडता। स्पीकर सर, इसके बाद मुख्य मंत्री जी ने सदन में आ वासन दिया कि इस बात की इंक्वायरी कराई जाएगी। इंक्वायरी की रिपोर्ट में पाया गया कि यह मसला हाई पावर कमेटी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि परचेज की इजाजत वही कमेटी देती है। यह ज्वाइंट एण्ड कलैक्टिव रिसपौंसिबिलिटी है

और यह रिसपौंसिबिलिटी एक ही परिवार की थी, बाकी तो सब अंगूठा छाप थे। यह बात बिल्कुल साफ है। इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता इससे ज्यादा तो मुख्य मंत्री जी ही बता सकते हैं क्योंकि होम डिपार्टमैंट उनके पास है।

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जैसा मंत्री महोदय ने अभी बताया कि बुक वैल्यु पर बसों को डिसपोज आफ करने का गवर्नमैंट ने फैसला लिया लेकिन बहुत थोडी बसें बिक सकीं। आगे घाटा न हो, इसके लिए थ्रू आउट कंट्री, कोई टैंडर फ्लौट करके या एडवरटाइजमैंट के माध्यम से यह बताएंगें कि ये बसें बिकाऊ हैं और गवर्नमैंट इनको बेचने को तैयार है ? क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई कदम उठाएंगे ताकि स्टेट को आगे घाटा न हो ?

श्री बलबीर पाल भााहः स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कोई निर्णय लेने से पहले यह मामला कैबिनेट में जाएगा। अगर हम इनको कम वैल्यू पर बेचना चाहते हैं और हमारी मं ाा रैकरिंग लौस को कम करने की है तो इसके लिए जरूरी है कि इनको बेचा जाए चाहे कम रेट पर भी बिकें हम इनको बेचने के लिए तैयार हैं इसके लिए एडवरटाइजमैंट के जो भी माध्यम होंगे, हम उनको इस्तेमाल करेंगे।

श्री अमर सिंहः क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने का कश्ठ करेंगे कि जैसे पहले मिनी बस का ट्रायल किया गया उसमें

3 रूपये पर किलोमीटर ऐक्सपैंस बताया है और 2 रूपये 45 पैसे पर किलोमीटर रिटर्न बताई है। फिर ये 60 बसें और खरीदकर ये घाटा जान बूझकर क्यों मोल ले लिया ? इसके बाद 174 बसें और खरीदकर ये घाटा जान बूझकर क्यों मोल ले लिया ? इसके बाद 174 बसें और खरीदी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 225 बसें इनके पास हैं जिसमें से 23 बसें डिस्पोज आफ कर दी हैं क्योंकि उन पर 2 रूपये पर किलोमीटर लौस है। क्या ये 202 बसें जो अब तक आन रोड हैं यदि घाटे में चल रही हैं तो इनको डिस्पोज आफ क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बलबीर पाल भााहः स्पीकर सर, ये 202 बसें आन रोड हैं और घाटे में चल रही हैं। इसका कारण यह है कि स्टेट के लगभग 300 ड्राइवर और 300 कंडक्टर्स का हित इनसे जुडा हुआ है। इन बसों का डिस्पोज आफ करने के साथ साथ इन कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं नौकरी का प्रबन्ध करना पडेगा। पीछे हमने भर्ती करी है लेकिन यह कंट्रक्चुअल बेसिज पर करी हैं सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन बसों को डिस्पोज आफ किया जाना है। उन लोगों को हटा कर जो पुराने ड्राईवर हैं उनको लिया जाए उनको नौकरी दी जाए। इसके लिए हम भीघ्र उचित कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं हाउस को आ वासन दिलाता हूं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि दो साल से घाटा हो रहा है और 8 करोड के लगभग घाटा हो गया होगा। क्या इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति

पर जिम्मेवारी फिक्स की गयी है ? मेरा एक तो सवाल यह है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर एक बस की उम्र अपनी सडकों के हिसाब को देखते हुए कितनी हैं ? जब बसें चलती हैं तो उनमें स्टपनी और दूसरे इम्पलीमैंटस वगैरह भी होते हैं ?

श्री बलबीर पाल भााहः बहिन जी, इस सवाल का इस विशय से कोई संबंध नहीं है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस मामले में बहुत चिन्तित है। मामला बहुत ही गंभीर है इसमें कोई दो राय नही ंहै। आप जानते हैं कि यह जो बसें ली गयी हैं वह डिपार्टमैंट की मर्जी के बगैर ली गयी थीं। डिपार्टमैंट ने यह लिखा कि यह बसें कामयाब नहीं है। हमने एक बस तजुर्बे के तौर पर लगा कर देख ली है, यह घाटे में चल रही है। कामयाब नहीं है इसलिये ये बसैं नहीं लेनी चाहिये। फाईनांस डिपार्टमैंट ने लिखा है कि बसें नहीं लेनी चाहियें कायेंकि यह वायेबल नहीं हैं। न ही इन बसों के लिये हमारे पास पैसा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर भी यह बसें खरीदी गयीं। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, आज के एम0एल0एज0 थे जो मेरे सामने बैठे हैं चौधरी ओम प्रका ा चौटाला उस समय मुख्य मंत्री थे। चौधरी ओम प्रका ा चौटाला की अध्यक्षता में मीटिंग हुई आप जानते हैं कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी की अध्यक्षता स्टेट का मुख्य मंत्री करता है। जब भी कोई परचेज करनी हो तो हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग होती है और उसकी अध्यक्षता बाकायदा स्टेट का मुख्य

मंत्री करता है जैसे आजकल मैं करता हूं। इनकी अध्यक्षता में यह फैसला किया गया, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने यह कहा था कि ये बसें कामयाब नहीं हैं। फाइनांस डिपार्टमैंट ने यह कहा कि नहीं लेनी चाहिये। छत्तर सिंह चौहान जी ने यह कह दिया कि आजकल चौधरी धर्मबीर हमारी तरफ आ गये हैं। हमारी तरफ आ गये हैं तो क्या हुआ, कोई इधर बैठे या उधर बैठे कोई भी काम किसी आदमी ने अगर गलत किया है तो वह गलत ही रहेगा। मैंने इस बारे में पिछले सै ान में भी कहा था कि हम मामले की जांच करायेंगे। हमने मई 1992 में विजिलैंस डिपार्टमैंट को इन्क्वायरी करने के लिये कहा और जनवरी में हमारे पास उनकी रिपोर्ट आ गयीं डायरैक्टर विजिलैंस अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं ? वह यह लिखते हैं कि निर्णय लिया गया कि मिनी बसें खरीदी जाए यह फैसला दिनांक 30–1–1990 की मीटिंगब में हुए निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया क्योंकि उस समय मुख्य मंत्री ओम प्रका ा चौटाला थे। मिनी बसें घाटे में चल रही थीं और खरीदे जाने की जिम्मेवारी भी श्री ओम प्रका ा चौटाला, तत्कालीन मुख्य मंत्री तथा श्री धर्मबीर, तत्तकालीन परिवहन मंत्री की बनती है। यह एक सरकारी रिपोर्ट है जो डायरैक्टर जनरल, विजिलैंस की तरफ से हमारे पास आयी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अभी एग्जामिन हो रही है। इसके बाद इसपर उचित कार्यवाही करेंगे।

Rupana Pump House of Sewani Minor

***567. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state-

(a) the total number of pums at Rupana Pump House of Sewani minor, together with the number of pumps are in working order amongst them at present; and

(b) whether it is a fact that the water of Sewani minor does not reach beyond RD 26, if so, the steps so far taken, or proposed to be taken for providing the water beyond RD 26 ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) 4 Pumps. Out of 4 installed pumps, 3 are working.

(b) Water is running upto RD 47 minor.

श्री अमर सिंहः स्पीकरसाहब, पिछले महीने सिवानी माइनर में जब पानी चल रहा था तो एक ही पम्प चल रहा था जबकि वहां पर चार पम्पस लगे हुए हैं। मैंने खुद जाकर देखा है। वहां 26 आर0डी0 से आगे पानी नहीं जाता। मैं मनत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वहां पर निरीक्षण करेंगे ताकि जो 3 पम्पस नहीं चल रहे हं, उनको चलाया जा सके ? मेरी जानकारी के मुताबिक, जैसे ही इनको पता लगा इन्होंने वहां पर जो मोटर थी, जिससे पहले चारों पम्पस चलते थे वह मोटर चूंकि खराब हो गयी थी, इसलिए उसे ि ाफ्ट कराकर दूसरी मोटर रख दी गयीं लेकिन वह मोटर एक पम्प से ज्यादा चला नहीं सकती

और तीन पम्पस अभी भी बंद पडे हुए हैं। जो एक पम्प चल रहा है उसकी कैपेसिटी भी कम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिवानी माईनर कुल कितनी आर0डी0 की है। इन्होंने जो कहा कि यह 47 आर0डी0 तक चलती है, यह गलत है। मेरी जानकारी के मुताबिक तो यह केवल 26 आर0डी0 तक ही चलती है। उससे बीऔंड नहीं चलती, क्या यह हकीकत है ?

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 47 बुर्जो तक पानी जाता है। यह माइनर ओरिजनली 63 बुर्जी की थी। 63 के बाद यह माइनर की चकबन्दी बीच में ही है लेकिन आखिरी जो हिस्सा है वह देवसर माइनर में ट्रांसफर हो गया जिससे इसकी कैपेसिटी 54500 तक है और यह आर0डी0 माइनर जो सिवानी गांव है वहां का आखिरी एरिया पडता है। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि यह माइनर 26 आर0डी0 तक चलती है, यह बात गलत है। स्पीकर साहब, 47 आर0डी0 तक पानी चलता है और जब चारों पम्प चलते हैं तो 54 आर0डी0 तक जाता है। जो पम्प हाउस हैं वह 23 आर0डी0 पर है और जब इन्होंने देखा होगा तो हो सकता 26 आर0डी0 तक पानी जा रहा हो। इस वक्त तीन पम्प चल रहे हैं और इनमें से एक पम्प की वर्किंग कैपेसिटी बीस क्यूसिक पानी की है तथा दो पम्पों की कैपेसिटी दस दस क्यूसिक की है। इस तरह से इस समय चालीस क्यूसिक की लिफ्ट करने की कैपेसिटी है। लेकिन यह एरिया

ट्रांसफर होने की वजह से इसकी कैपेसिटी 23.4 क्यूसिक रह गई है।

स्पीकर साहब, इस समय तीन पम्प वर्किंग आर्डर में हैं और एक पम्प की रिपेयर होनी है। उसके चारों तरफ का लोहा गल गया है। इसको ठीक करने के लिए एम0आई0टी0सी0 को आर्डर दे रखा है।

Crops Insurance Scheme

***552. Sh. Jai Parkash:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether thee is any proposal under consideration of the Govt. to introduce crops insurance sheme in the State; and

(b) if so, the details thereof together with the time by which the aforesaid scheme is likely to be introduced ?

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh): (a) & (b) The matter regarding introduction of Crop Insurance Scheme in the State is under consideration of the Govt. of India. After the Scheme is received from Govt. of India, it will be considered for implementation in the State.

श्री जय प्रका ः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि राज्य में फसल बीमा योजना आरम्भ करने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि अभी जो बाढ आई थी उस फ्लड से किसान का

बहुत भारी नुकसान हुआ है। मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूं कि उसने किसान की तकलीफ को दूर करेने के लिए पूरे पग उठाए और प्र ाासन ने पूरा सहयोग देकर किसान की मदद की है। मैं मन्त्री महोदय से कौरसपौंडैंस की है या कोई बैठक की है ताकि भारत सरकार इस योजना को जल्दी क्लीयर करे ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं श्री जय प्रका ा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्हौंने एक बडा ही रेलेवैन्ट क्वै चन किया है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि अपोजी ान के जो नेता हैं और लीडर हैं वे किसान की बात तो करते हैं लेकिन इं योरैंस की जो जरूरी बात थी, उसका कोई जिक्र नहीं किया। स्पीकर साहब यह इं योरैंस स्कीम किसान के लिए बहुत जरूरी है। और यही विचार स्टेट गवर्नमैंट का है। पिछली दफा यह स्कीम लागू की गई थी। यह स्कीम 1981 में आई थी और 1981 से 1985 तक रही। 1985 में जो सरकार थी उस वक्त उसने यह स्कीम ड्रोप कर दी थी। क्या कारण थे यह तो सरकार को मालूम होगा लेकिन उसमें यह बात थी कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की जो स्कीम थी,उसमें ब्लौक लैवल यूनिट रखा था और स्टेट गवर्नमैंट चाहती थी कि विलेज यूनिट रखा जाए। वह स्कीम सिर्फ क्लौक को कवर करती थी विलेज को नहीं करती थी। इसलिए सैंट्रल गवर्नमै।ट की तरफ से उस स्कीम को ऐडौप्ट करना कम्पलसरी नहीं था। स्टेट गवर्नमैंट का औप ान था और स्टेट गवर्नमैंट ने इसको रिव्यू करने के लिये सैंटर गवर्नमैंट को लिखा

है। अभी रीसैंटली इसके लिये एक मीटिंग केन्द्र सरकार ने बुलाई थी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी उस मीटिंग में गये थे। प्रधान मंत्री भी वहां पर थे। मीटिंग में किसानों के बारे में कुछ प्वायंटस भी उठाये गये थे। जिनमें एक प्वायंट क्राप इं ाोरैंस का भी था। इस संबंध में कुछ प्रपोजल्ज उनकी ऐसी थी जिनके मुताबिक हमें किससानों पर कुछ बोझ सा लगा और हमने यह सोचा कि किसान ऐसी पोजी ान में नहीं हैं कि वह इतना प्रिमीयम दे सकें। इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वहां यह कहा कि एक तो यह स्कीम सिफ बैंकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये, दूसरे यह स्कीम से सभी फार्मर्ज को क्राप इं ाोरैंस करवाने का मौका मिलना चाहिये। तीसरी बात उसमें यह भी थी कि जो क्राप्स का प्रिमीयम चार्ज करने जा रहे थे, उसका जो रेट 6 परसैंट व 4 परसैंट था वह बहुत ज्यादा था। उस संबंध में स्टेट गवर्नमैंट ने यह कहा कि यह रेट हाई है, यह हम नहीं दे सकते। चौथी बात यह थी कि जो रिस्क लायबिलिटी कवर करनी थी, उसमें भी वे यह चाहे रहे थे कि स्टेट गवर्नमैंट इस रिस्क को कवर करने के लिए दो हिस्से दे और एक हिस्सा सैंटर गवर्नमैंट दे। लेकिन स्टेट गवर्नमैंट की सुजै ान इस संबंध में यह थी कि दो हिस्से सैंटर गवर्नमैंट दे और तीसरा हिस्सा स्टेट गवर्नमैंट दे। इन सुजै ान्ज के साथ स्कीम को इम्प्रूव करने के लिये हमने अपने व्यूज दिये हैं। उसके बाद अभी तक यह स्कीम फाइनल होकर राज्य सरकार के पास नहीं पहुंची है। जब फाइनल होकर हमारे पास आएगी, उसको तुरन्त लागू कर दिया जाएगा।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1981 से 1985 तक ब्लाक लैवल यूनिट मानकर इस स्कीम को लागू कर दिया गया था और इसे इंन एण्ड आउटस वगैरा सारे डिफेक्टस को स्टडी करके भारत सरकार के पास भेज दिया गया था। इस संबंध मे मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को भारत सरकार के पास कब भेजा गया था, कब से यह मामला भारत सरकार के अंडर कंसिडरे ान चल रहा है और कब तक टेनटेटिवली इसका फैसला हो जाएगा ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैंने पहले ही जिकर किया है कि एक तो मुख्य मंत्री जी की मीटिंग थी जो प्राईम मिनिस्टर महोदय ने बुला रखी थी। बाद में फालोअप एक ान के लिये जो स्टेटस के ऐग्रीकल्चरल सेक्रेटरीज थे, कमि नर थे, उनकी मीटिंग की है और वह अन्डर प्रोसैस है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा और स्कीम आ जाएगी।

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रति हजार के हिसाब से कितना प्रिमीयम किसान को देना पडेगा ? अब दो सालों से केन्द्र व प्रदेश में इनकी सरकार है इसलिये अब इस स्कीम को कितनी देर के बाद लागू कर पाएंगे ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे विचार में केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें इसके लिये कीन हैं और बहुत जल्द इस स्कीम को चालू करने के चानसिज हैं कि त का जहां तक सवाल है उस बारे में मैं इस वक्त नहीं बता सकता लेकिन मैं समझता हूं कि पहले जो स्कीम थी, उसमें लोनी को कवर करते थे और जो लोनी बैंक से लोन नहीं लेता था वह कवर नहीं होता था लेकिन अब इस स्कीम के तहत सभी फार्मर्ज कवर होंगे चाहे वे बैंक से लोन लें, चाहे बैंक से लोन न लें। अगर किसान अपनी क्राप की इं ाोरैंस करवाना चाहे तो करवा सकता है। लेकिन किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया जायेगा। सभी के लिये जरूरी नहीं होगा जो चाहेगा उसी की इं योरैंस होगी। इससे अगली बात यह थी कि पहले यह इं योरैंस 10 हजार रूपये तक हो सकती थी और अमाउंट भी ज्यादा कर रखा था। जो किसान बैंकस से जितना लोन लेता था, उसी की मिकदार के मुताबिक ही इं येरैंस कर देते थे। इसका मतलब यह होत था कि कर्जे की इं योरैंस होती थी, किसान की क्राप की इं ाोरैंस नहीं होती थी लेकिन अब जो स्कीम आ रही है, उसके तहत 25 हजार से 45 हजार तक एक किसान लोन ले सकता है और उस लोन से डियोढी रा ि ा का किसान क्राप इं ाोरैंस करवा सकता है।

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना स्कीम के तहत कौन कौन सी आपदाएं सम्मलित की गई हैं ?

श्री हरपाल सिंहः यही तो मैंने अभी बताया है कि यह स्कीम फाइनल हो कर नहीं आई। जब आ जाएगी तो उस समय सारी बातें बता देंगे।

श्री धीरपाल सिंहः जो प्रपोजल आपने भेजी है, उसमें आपने जो कुछ लिखा होगा वही बता दें।

श्री हरपाल सिंहः यह प्रपोजल तो सैंट्रल गवर्नमैंट की है और उसे रिव्यू करने के लिए हमने सुजै ान्ज दी हैं। एक तो हमने यह कहा कि यह फार्मर के लिए कम्पलसरी नहीं होनी चाहिये। दूसरे हमने यह कहा है कि जो आप प्रीमियम का रेट 4 प्रति ात से 6 प्रति ात लगा रहे हो, यह ज्यादा है, इसको कम करो। तीसरी बात हमने यह कही है कि स्माल और मार्जिनल फार्मर के प्रीमीयम 50 प्रति ात सबसीडाइज्ड करो। चौथी बात हमने यह कही है कि इसको लागू करने में किसान का जो रिस्क है, लायबिलिटी है, उसके दो हिस्से सैंट्रल गवर्नमैंट दे बजाए स्टेट गवर्नमैंट के। उन्होंने यह कहा था कि दो हिस्से स्टेट गवर्नमैंट देगी और एक हिस्सा वे देंगे। हमने कहा है कि इसको रिव्यू करो यानी दो हिस्से आप दें और एक हिस्सा हम देंगे।

Illegal possession of Panchayat Land of Village Dhani Jatan

***587. Sh. Mani Ram Keharwala:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether the Panchayat land of village Dhani Jatan of District Sirsa is under illegal possession of some one; and

"(b) if so, the total acreage of land thereof ?

Interim Reply

"BANSI SINGH RAO

D.O. No.

_____

Minister,

Development & Panchayat,

Haryana, Chandigarh.

Dated _____

Subject: **Regarding Starred Question No. 587.**

Respected Speaker Sahib,

The above mentioned starred question is stated for 31st August, 1993. As the requisite information has not been received in full detail from the Deputy Commissioner, Sirsa, to which this question pertains so far, it is not feasible to furnish the required information to the House tomorrow. It is, therefore requsted that atleast 10 days' time may please be more given and oblige please.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bansi Singh Rao)

Ch. Ishwar Singh Ji,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Upgradation of Schools in Ratia Constituency

***603. Sh. Pir Chand:** Will the Minister for Education be pleased to state-the number of schools if any, upgrated from Primary to Middle, Middle to High School and High to 10+2 system in Ratia Tehsil during the period from June 1991 todate together with the location thereof ?

ि ाक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अलावलवास नाम का केवल एक राजकीय उच्च विद्यालय प्र न में दी गई अवधि के दौरान मिडल से हाई स्तर तक अपग्रेड हुआ था। अलावलवास रतिया कस्बे के उत्तर में 15 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, जाखल का स्कूल एक बार अपग्रेड हुआ था लेकिन उसको फिर डाउन ग्रेड कर दिया गया। क्या 1993–94 में उसको फिर अपग्रेड करने की परपोजल है ? स्पीकर साहब, रतिया एक बहुत बडा भाहर है लेकिन वहां लडकियों का दस जमा दो का स्कूल नहीं है जो बहुत जरूरी है। लडकियों को या तो टोहाना जाना पडता है जो रतिया से 20

किलोमीटर दूर है या फतेहाबाद जाना पडता है। इससे लडकियों के लिए बहुत परे ाानी होती है। रतिया की अब 40 हजार की आबादी हो गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां 10 जमा 2 प्रणाली का स्कूल बनाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

चौधरी फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी सप्लीमैंटरी में जाखल का स्कूल अपग्रेड होने के बारे में पूछा है। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य सवाल पढना भूल गए जो पढा है उसमें जाखल का कोई जिक्र नहीं हौ। जाखल नाम का कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ था। माननीय सदस्य ने रतिया में स्कूल की मांग की है, इससे पहले रतिया के लिए स्कूल की कोई मांग नहीं आई, जब आएगी तो सरकार उस पर विचार कर लेगी। आल इंडिया सर्वे के मुताबिक नार्म्ज के हिसाब से, हमारे यहां जितने स्कूल होने चाहिएं, उससे ज्यादा स्कूल हैं रतिया में 45 प्राइमरी स्कूल हैं, 23 मिडल स्कूल हैं, 14 हाई स्कूल हैं और एक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, जब स्कूल अपग्रेड करने की बात आती है तो सरकार कहती है कि सरकार के पास फण्डज नहीं हैं इसलिए स्कूल अपग्रेड नहीं किए जाएंगे।

Mr. Speaker: This supplementary does not arise out of the main question. It is a specific question and it does not relate to it.

श्री कर्ण सिंह दलाल: सर, इसी से रिलेटिड है।

Mr. Speaker: No, No. Please take your seat.

श्री पीर चन्द: स्पीकर साहब, जाखल का स्कूल अपग्रेड हुआ था। मुलाना साहब नए मंत्री बने हैं, पिछली ि ाक्षा मंत्री ने वह केस गुम कर दिया होगा, लेकिन जाखल का स्कूल अपग्रेड हुआ था। वह चालू नहीं किया गया इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वह जबानी अपग्रेड हुआ होगा, लिखित में नहीं हुआ होगा।

श्री पीर चन्द: स्पीकर साहब, 27–3–1991 को स्कूल अपग्रेड हुआ था। उसके 25 कमरे बने हुए हैं। कर्मचारियों के रहने के लिए मकान बने हुए हैं। उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने पर लाला लोगों ने कम से कम 20 लाख रूपया खर्च किया है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है। उन्होंने वह बिल्डिंग इस वि वास के साथ बनाई थी कि यह स्कूल अपग्रेड होगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस स्कूल को अपग्रेड कर दें ताकि बच्चों को आराम मिल जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, भाायद जाखल का स्कूल कैंसिल किया गया था। पिछली सरकार जाते जाते 350 स्कूल अपग्रेड कर गई जबकि बजट में कोई पैसा नहीं था। जाते जाते कर गई जैसे कोई आदमी कह दे कि विधान सभा मैं आपके नाम करता हूं, चण्डीगढ आपके नाम करता हूं, आगरे का

ताजमहल आपके नाम करता हूं, ऐसे ही श्रीमान जी जाते हुए कर गए, ऐसे ही जाखल के स्कूल का नाम भी उसमें हो सकता है, क्योंकि वे सारे ही स्कूल कैंसिल हुए थे। एक का सवाल नहीं है, चाहे कहीं का स्कूल हो जो चालू हो गया, उसके आर्डर हो गये, उसको कैंसल करने का कोई सवाल ही नहीं है। रतिया का ये बार बार कहते हैं। अलावलवास नाम का गांव भी है जहां का स्कूल 8 से 10 में अपग्रेड किया गया। इनकी बात को मानकर ही अलावलवास के स्कूल को अपग्रेड किया गया था और आगे जब और स्कूल अपग्रेड करेंगें तो जाखल का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

Construction of Stadium at Kalyat

***640. Sh. Bharath Singh:** Will the Minister of State for Sports be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Stadium in Kalyat-Town; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Stadium is likely to be constructed ?

खेल राज्य मन्त्री (श्री राजे ा भार्मा): (क) एवं (ख): नहीं।

श्री भरत सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कलायत

प्रोपर भाहर में कोई खेल स्टेडियम बनाने का विचार है; यदि कोई मामला विचाराधीन है तो इसके कब तक बनने की संभावना है ?

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम या खेल का मैदान उसी गांव, कस्बे या भाहर में बनाया जाता है जहां से कोई प्रपोजल प्राप्त होती है। या कोई डिमाण्ड होती है। अभी तक इनके इलाके से कोई भी परपोजल या डिमांड हमारे पास नहीं आई है। ये अपनी पंचायत या म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से जब परपोजल भिजवा देंगे तो विचार करेंगे। परपोजल पर विचार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस कमेटी बनी हुई है, जब वह परपोजल हमारे पास भेजेगी तो हम आगामी कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्पोर्टस विभाग की तरफ से ग्रामीण स्टेडियम बनाने की कोई स्कीम है, जिसके तहत, कोई भी ग्राम पंचायत अगर 5 एकड जमीन दे तो स्पोर्टस विभाग स्टेडियम बनाने के लिए कुछ पैसा देता है ? इसके लिए पंचायत को रैजोल्यू ान भी पास करना पडता है और कुछ पैसा भी देना होता है। ग्राम के लोगों के लिए 50 हजार रूपये की रा ि ा इकटठी करनी बहुत मु ि कल होता है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी कोई परपोजल या सुझाव हैं कि अगर ग्रामीण पंचायतें लिख कर दे दें कि उनके पास जमीन है, इनमें स्टेडियम बना दिए जाएं, तो क्या उनसे बिना पैसे लिए वहां ग्रामीण स्टेडियम बना देंगे ?

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम राज्य सरकार की नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की है। अगर ग्रामीण पंचायत 5 एकड जमीन और 41 हजार रूपये देती है तो उसके बाद पौने दो लाख रूपये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिल कर लगाते हैं। 4 आने ग्राम पंचायत से इसलिए लिये जाते हैं ताकि गांव वालों को उसमें अपनी इन्वाल्वमैंट महसूस हो। इसके पहले ऐसा हुआ है कि खेल के मैदान डिवैल्प किए गए और ग्राम पंचायतों से कोई पैसा नहीं लिया गया परन्तु ग्राम वासियों ने उन स्टेडियमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामवासी अपनी इन्वाल्वमैंट महसूस करें इसलिए यह टोकन मनी ली जाती है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: स्पीकर साहब, 5 एकड जमीन 20 लाख रूपये की बनती है। जो प्र न मैंने पूछा उसका जवाब नहीं आया। मैंने यह सप्लीमैंटरी पूछा था कि अगर ग्राम पंचायत पैसे देने में असमर्थ रहती है तो सरकार को ग्रामीण स्टेडियम बनाने चाहिएं। हमारी स्टेट में बडा भारी स्पोर्ट पोटैं ाल है, इसलिए अगर ग्राम पंचायत जमीन दे रही है तो क्यों न ऐसी स्कीम बनाई जाए या वर्तमान स्कीम में कोई अमैंडमैंट की जाए ताकि अगर पंचायत जमीन देती है तो उसमैं पौने दो लाख रूपये खर्च करके स्टेडियम बनवाया जाये ?

श्री अध्यक्ष: जमीन किस को दे रहे हैं, जमीन तो वहीं पर ही रहेगी।

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जमीन तो पंचायतें पहले भी देती थीं लेकिन लोग अपनी इन्वाल्वमैंट महसूस नहीं करते थे, इसलिए उनसे टोकन मनी के रूप में यह रा ि ा ली जाती है। यह स्कीम सैंट्रल गवर्नमैंट की है और इसमें ज्यादा योगदान उन्हीं का है।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, हम 5 एकड जमीन डिवैल्प करके इनको देंगे तो क्या ये उस पर स्टेडियम बना कर देंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह स्कीम वायबल है ? एक सामूहिक लैट्रिन बनाने पर एक लाख रूपया खर्च हो जाता है और ये कहते हैं कि 5 एकड में पौने दो लाख में स्टेडियम बना देंगे। स्पीकर साहब, एक लाख रूपया तो एक किल्ले की दीवार पर ही खर्च हो जाता है, इसलिए लोगों को वि वास नहीं होता कि पौने तीन लाख में स्टेडियम बन सकता है, इसलिए वे इसमें पैसा नहीं देते।

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो डिफरैंट स्कीमज चल रही हैं, उनमें पौने दो लाख की एक स्कीम है। इसमें स्टैण्डर्ड साईज का फुटबाल और क्रिकेट ग्राउन्ड होता है। कंकड, पत्थर और रोडों को हटाकर ग्राउन्ड बनाया जाता है। अगर ज्यादा उबड खाबड जमीन हो और कौस्ट आफ लेबर ज्यादा लगती हो तो उसमें चार दिवारी नहीं की जा सकेगी, अदरवाईज चार दिवारी लगाई जाती है और एक कमरा बनाया जाता है। उसके बाद

अगली स्कीम है स्टैण्डर्ड साईज स्कीम, जिसमें फुटबाल और क्रिकेट ग्राउन्ड बनाया जाता है। इसके अन्दर चार लेन, छः लेन और आठ लेन की डिफ्रैंट स्कीमें होती हैं। केन्द्रीय सरकार की स्कीम के तहत, जितने पैसे ग्राम पंचायत जमा करवायेगी, उतने ही पैसे हरियाणा गवर्नमैंट जमा करवाएगी और दोनों को मिला कर जितने पैसे बनेंगे, उतने सैंट्रल मैंचिंग ग्रान्ट के रूप में देगी।

श्री के0एल0 भार्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि स्टेडियम वहीं बनाते हैं जहां से डिमान्ड आती है। अध्यक्ष महोदय, हमने भााहबाद से डिमांड की है और पौने दो साल पहले 9 जनवरी 1992 को मुख्य मंत्री जी ने एक स्टेज से अनाउंस किया था कि यह स्टेडियम जल्द से जल्द बन जाएगा। हमने स्पोर्टस आफिसर को चार साईटस भी दिखाई हैं, परन्तु आज तक वे किसी साईट का चयन नहीं कर पाए हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब तक यह स्टेडियम बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल कमेटी वाले अभी तक यह फैसला नहीं कर पाए कि कौन सी जमीन स्पोर्टस वालों के नाम की जाएगी। जब जमीन स्पोर्टस डिपार्टमैंट के नाम हो जाएगी, तक यह केस सैंटर गवर्नमैंट को भेज देंगे।

श्री अध्यक्षः राजे ा जी, आपको याद होगा कि हमने आपको कौल में स्पोर्टस के फंक ान में बुलाया था परन्तु आप

किसी कारण नहीं आ सके, लेकिन आपने स्पोर्टस के कमि नर श्री के0सी0 भार्मा को भेजा था। उन्होंने वहां पर कुछ ग्रांट अनाउंस की थी। क्या आप उस ग्रांट को भिजवा देंगे ?

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, जो के0सी0 भार्मा जी ने अनाउंस किया था उसे हम जरूर पूरा करेंगे।

Flood Aflected Area

***608. Sh. Satbir Singh Kadian:** Will the Chief Minister be pleased to state-the districtwise total area of land aflected by floods in the month of July, 1993 in the State ?

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह): जुलाई 1993 में आई बाढ से 464747 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। जिलावार विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला		क्षेत्र (हैक्टेयर में
1	हिसार	116938
2	कैथल	158000
3	जीन्द	64780
4	पानीपत	1980
5	नारनौल	92

6	अम्बाला	630
7	रोहतक	32000
8	भिवानी	8600
9	करनाल	19894
10	कुरूक्षेत्र	12249
11	सिरसा	40000
12	सोनीपत	9142
13	रिवाड़ी	442
कुल		464747

श्री सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो नुक्सान दिखाया गया है, वह कैथल जिले में दिखाया गया है। लेकिन कल जो मुख्य मंत्री जी ने बाढ की राहत देने की घोशणा की थी, वह सबसे ज्यादा हिसार में दिखाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो फिगर्ज दिखाए गए हैं, ये कम करके दिखाए गए हैं। क्या सरकार नए सिरे से सर्वे करके जिनका बाढ से नुक्सान हुआ है, उनको पैसे देने का कश्ट करेगी ?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, जो गिरदावरी की गयी है उसके अनुसार लगभग 5 लाख हैक्टेयर जमीन प्रभावित हुई थी लेकिन जब दोबारा गिरदावरी की गयी तो यह जमीन चार लाख और कुछ नजर आयी। अन्तिम गिरदावरी के अनुसार 26 लाख हैक्टेयर जमीन में, 25 परसैंट से ज्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुक्सान सिरसा जिले में हुआ है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, मैं जिलेवार ग्रांट पूछना चाहता हूं कि किस किस जिले को कितनी कितनी ग्रांट दी गयी ?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, टोटल ग्रांट 18 करोड 42 लाख है जो डिप्टी कमि नर को दे दी गयी हैं। इसके साथ ही साथ वेरियस डिपार्टमैंट को जो ग्रांट दी गयी है, वह इससे अलग है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, जिलेवार कितनी कितनी ग्रांट दी गयी है, जो दी गई है क्या वास्तव में दी भी गयी है या नहीं ?

श्री निर्मल सिंहः जी हां, दी गयी है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसके बारे मैं जैसा मैंने कल भी बताया था कि लगभग चालीस करोड रूपया हमने सारी स्टेट में डिप्टी कमि नर को भेज दिया है। इन्होंने कहा कि कैथल में ज्यादा नुक्सान हुआ है और पैसा ज्यादा

हिसार को दिया गया है जबकि वास्तव में कैथल और हिसार में जो नुक्सान हुआ है, उसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है बल्कि मकान तो ज्यादा हिसार और सिरसा में ही खराब हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कैथल को 5 करोड 41 लाख, जीन्द को एक करोड 10 लाख, सिरसा को दो करोड 13 लाख, हिसार को 5 करोड 84 लाख, करनाल को एक करोड 37 लाख, अम्बाला को 3 करोड 79 लाख, कुरूक्षेत्र को 67 लाख 39 हजार, यमुनानगर को दो लाख 40 हजार, पानीपत को 14 लाख 56 हजार, रोहतक को 8 लाख 25 हजार, भिवानी को 32 लाख 15 हजार और सोनीपत को 2 लाख 40 हजार रूपये दिये हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 18 करोड रूपये बनते हैं जो अब तक दिये जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, यह ग्रांट जिन जिन चीजों के लिए दी हैं, वे हैं– भोजन की व्यवस्था के लिए सर्की, टैंट तथा प ाुओं की देखभाल के लिए, मकानों की मुरम्मत के लिए और नलकूपों की मुरम्मत के लिए, सबसिडी के रूप में दी हैं। इसके अलावा, 20 करोड 18 लाख 57 हजार रूपये हमने विभिन्न विभागों को दिये हैं, जैसे सिंचाई के लिए 6 करोड 7 लाख, स्वास्थ्य के लिए 32 लाख, प ाुपालन के लिए 50 लाख, लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग एण्ड रोडज) एवं पुलों की मुरम्मत के लिए 2 करोड 75 लाख 35 हजार, बिजली बोर्ड को तीन लाख 75 हजार, जन स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड 11 लाख, ऐग्रीकल्चर और उसके इनपुटस के लिए 5 करोड 3 लाख रूपये दिये हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 20 करोड 58 लाख, 57 हजार रूपये बनते हैं।

श्री कृश्ण लालः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि करनाल के अंदर लगभग 19 हैक्टेयर भूमि नश्ट हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि असन्ध सब डिवीजन के जो गांव हैं, उनमें कितनी भूमि पानी से नश्ट हुई है ?

श्री निर्मल सिंहः इसके लिए आप अलग से नोटिस दें।

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने अपने लिखित बयान में 464747 हैक्टेयर भूमि को बाढ से प्रभावित बताया है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो 464747 हैक्टेयर भूमि है, इसमें कितने परसैंट खराबा हुआ है और क्या आप 464747 हैक्टेयर भूमि के किसानों को मुआवजा देंगे ? जिस जमीन पर खराबा हुआ है, क्या उसकी संख्या कुछ और है ?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, बाद में जो गिरदावरी की गई उसके मुताबिक खराबा 1 लाख 26 हजार हैक्टेयर भूमि पर है। पहले वाली गिरदावरी हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, इन्होंने अपने लिखित बयान में यह बताया है कि इतनी जमीन बाढ से प्रभावित हुई है, इनकी गिरदावरी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने जुबानी जवाब में यह बताया है कि सारी जमीन को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, केवल 1 लाख 26 हजार हैक्टेयर भूमि को मुआवजा दिया जाएगा। स्पीकर सर, ये मान रहे हैं कि हरियाणा में किसान की 4 लाख 64 हजार 747 हैक्टेयर भूमि बाढ से बुरी तरह प्रभावित हुई

है। स्पीकर सर, आप स्वयं अच्छे किसान हैं, जो जमीन एक बार बाढ से प्रभावित हो जाती है लगभग 100 फीसदी खराब मानी जाती है। क्या मंत्री महोदय इस सारी जमीन के मालिकों को मुआवजा देने पर विचार करेंगे ?

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर सर, ऐसा नहीं है कि 4 लाख 64 हजार 747 हैक्टेयर भूमि पर पानी आया है। सही मायनों में जो भूमि खराब हुई है, वह 1 लाख 26 हजार हैक्टेयर है।

श्री सुरजीत कुमारः अध्यक्ष महोदय, बाढ पीडित लोगों को मुआवजा देने की बात चली है। मैं अभी 2–3 दिन पहले सिरसा के छतरगढ–पटटी गांव में गया था, वहां बहुत से गरीब आदमी हैं, जिनमें से 55 आदमियों की लिस्ट मेरे पास है जिनको अभी तक सहायता नहीं मिली। मैंने इस बारे में डी0सी0 को भी कहा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि गरीब आदमियों को वरीयता दे लेकिन वहां के पंच सरपंच लोग मनमानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह रैलेवेंट क्वै चन नहीं है, इसके लिए आप अलग से मिल लें।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा): स्पीकर सर, छतरगढ पटटी गांव मेरे हल्के में हैं और वहां पर सबको मुआवजा दिया जा रहा है। (ाोर)

Rejected Coal

***609. Sh. Dhirpal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the yearwise total quantity of coal purchased by the Thermal Power Plant Panipat during the last three years;

(b) the total quantity of coal, if any, rejected out of the coal as referred to above; and

(c) whether the coal as referred to in part (b) above is still lying in Thermal Power Plant ?

Power Minister (Sh. A.C. Chaudhary): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

The requisite information is as under :-

(a) The year wise details of coal purchased by the Thermal Power Plant, Panipat during the last three years is given below :-

1990-91 14.15 Lac Tonnes

1991-92 20.62 Lac Tonnes

1992-93 23.58 Lac Tonnes

(b) The year wise quantity of rejected coal is as under :-

1990-91 41826 Tonnes

1991-92 80191 Tonnes

1992-93 97994 Tonnes

(c) Yes, Sir.

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, बिजली मंत्री जी ने द ार्या है कि 1990–91 से 14.15 लाख टन कोयला खरीदा गया और 1992–93 में 23.58 लाख टन खरीदा गया। रिजैक्टिड कोयले की मात्रा 1990–91 में 41826 टन थी और 1991–92 में उसकी मात्रा बढकर 80191 टन, 1992–93 में 97994 टन कोयला हो गया। आप देखेंगे कि रिजैक्टिड कोयले की मात्रा दुगुने से ज्यादा हो गई है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या घटिया किस्म का कोयला खरीदने की वजह से अस्वीकृत कोयेल की मात्रा बढी है, यदि हां तो उस समय कौन मंत्री थे, जिनकी इसके लिए जिम्मेदारी बनती हो ? इसके अतिरिक्त भाग (ख) में इन्होंने जो जवाब दिया है, उसके बारे में जानना चाहता हूं कि जो रिजैक्टिड कोयला वहां पडा हुआ है, उसकी मात्रा व लागत कितनी बनती हैं ?

बिजली मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर सर, मेरे फाजिल दोस्त ने कैलकुले ान में कुछ कमी देख ली है। दरअसल कोयला एक पत्थर है। कोयला हम कोल अथारिटी आफ इंडिया से लेते हैं। कोयले को उपयोग में लाने के लिए पहले उसकी पिसाई करते हैं, पिसाई द्वारा उसके छोटे छोटे टुकडें कर लेते हैं। इस प्रौसेस के हमारे पास दो सिस्टम हैं, जिनमें एक हैमर मिल और एक बौल मिल है। इस प्रौसेस में जो कोयला बाहर आ जाता हैं, उसको रिजैक्टिड कोल कहते हैं। मैं इस अगस्त हाउस को बताना

चाहता हूं कि इसमें 3 से 4 परसैंट कोयले की वेस्टेज होती ही है। जहां तक मिनिस्टर का ताल्लुक है, उसको तो मैं मान ही रहा हूं कि नार्मली आलमोस्ट 4 परसैंट रिजैक ान उसके अंदर है। डबल के हिसाब से अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि 1990–91 में हमारी कोयले की खरीद 14.15 लाख टन थी और अब 23.58 लाख टन है जो डबल के करीब है हमने कोल अथौरिटी आफ इंडिया में अपनी तरफ से एजेन्ट भी लगा दिया है ताकि वह क्वालिटी को मोनीटर कर सके और निगरानी कर सके। (व्यवधान व भाोर) जहां तक इनके सवाल के दूसरे पार्ट का ताल्लुक है, स्पीकर साहब, आलमोस्ट हमारे पास एवरेज जो नौर्मली रही है, वह 7000 टन की रही है। इतना ही कोयला निकलता है जो रिजैक ान में है। इस वक्त हमारे पास 2.54 लाख टन रिजैक्टिड कोयला अवेलेबल हैं।

श्री धीरपालः इसकी कीमत भी बता दो।

श्री ए0सी0 चौधरीः इसकी कीमत अभी नहीं आंकी गयी।

श्री धीरपाल सिंहः मैं बता देता हूं।

श्री ए0सी0 चौधरीः कीमत की कैलकुले ान करने के लिये तो आपको सीखना पडेगा। जो रिजैक ान है, उसको कैसे वर्क आउट किया जाता है, इस बारे में मेरा कहना यह है कि इसको प्रौपर स्टेज पर किया जा सकता है लेकिन इस रिजैक ान की कई क्वालिटीज हैं। जब हम मौके पर टैंडर लेते हैं तो उसके

रेटस भी वैरी करते हैं। हमारे पास एक मात्र साधन है कि जो हाईएस्ट कोट करता है, हम उसको दे देते हैं। जहां तक रेट का ताल्लुक है, मैं बता देता हूं कि 311 रूपये पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लें, पता चल जायेगा कितनी कीमत बनती है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 6 करोड 70 लाख रूपये का कोयला इनके पास रिजैक्टिड पडा हुआ है, यह कितने दिनों से पडा हुआ है। दूसरे यह कि 1990–91 में यह रिजैक् ान 3 परसैंट थी, लेकिन 1992–93 में यह 4 परसैंट क्यों हुई है ? क्या यह सरकार की इनएफी ीयैंसी नहीं है ?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है और यह पाया गया है कि रिजैक्टिड कोयले का क्वांटम घटता बढता रहता है। जब हम कोयला क्र ा करते हैं और म ाीन उसको क्र ा नहीं करती, बाहर फैंक देती है तो ऐसे कोयले का रिजैक्टिड के नाम से जाना जाता है। (व्यवधान व भाोर) मैं यह नहीं कहता कि परसैंटेज नहीं बढी है, कुछ बढी जरूरी है। मैं इसकी जिम्मेवारी ओन करता हूं क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है। (व्यवधान व भाोर)

श्री धीरपाल सिंहः क्या इसकी आप विजीलैंस इन्कवायरी करायेंगे ? (व्यवधान व भाोर)

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, इसका जवाब तो यही है कि अभी तो कोयले की लिफ्टिंग नहीं है। हम कोि ा ा कर रहे हैं कि कोई लोग लेने वाले आ जायें। हमारी कोि ा ा यही है कि इसकी डिस्पोजल के लिये जो रेट हाईएस्ट टैंडर में आया हुआ है, उस रेट पर ओपन मार्किट से कोई भी आदमी इसको ले जाये। हमने इस तरह की बात मार्किट में फ्लोट की है ताकि बोर्ड को जो घाटा हो रहा है, वह न हो और किसी आदमी पर इल्जाम तरा ी भी न हो।

डा0 राम प्रका ाः स्पीकर साहब, रिक्वायरमैंट के मुताबिक जितना कोयला चाहिए उतना मिलने के बावजूद भी पावर जनरे ान पर असर पड रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सोर्स पर क्वालिटी को कन्ट्रोल करने के लिए कोई टैक्नीकल, मैकेनिकल या कोई और ढंग नहीं है जिससे सोर्स पर ही कोयले की क्वालिटी देखी जा सके ? क्या हिन्दुस्तान के दूसरे थर्मल प्लांटस ने इस बारे में कोई ढंग अपनाया हुआ है जिसके तहत क्वालिटी चैकी की जा सके ? थर्मल प्लांट पानीपत में आर0एंड डी0 सैक ान है, क्या उसने सोर्स पर कन्ट्रोल करने का कोई तरीका निकाला है ?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, पानीपत थर्मल प्लांट में दो लाख टन हर महीने कोयले की खपत होती है और कोयला चूंकि कोल रौक्स हैं, उसके लिए कोई कैमीकल हमारी निगाह में नहीं आया जो उसकी क्वालिटी को चैक कर सके। दो लाख टन

मन्थली कंजम्प ान जब कोयले की है तो उसकी चैकिंग के लिए मेन पावर और दूसरे मैयर्ज लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो कोयला हमारे पास बचता है, उसको वापिस करने के लिए जो भी साधन बनते हं उनको अपनाकर उसको वापिस कर देते हैं।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Power Projects in the State

***622. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for Power be pleased to state-the present stages of Construction of Super Thermal Power Project at Yamuna Nagar, Gas based Power Plant at Faridabad and Thermal Power Station at Hisar ?

Power Minister (Sh. A.C. Chaudhari): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

Yamuna Nagar Thermal Power Project:

Yamuna Nagar Thermal Power Project Power Project with an installed capacity of 4x210 MW has been fully cleared from the point of all statutory and non statutory clearance. Its foundation stone was laid by the Hon'ble Prime Minister of India on 28th March, 1993. The project is being taken up as a joint venture among National Thermal Power Corporation,

Haryana State Electricity Board and a foreign investor. (Negotiations are in progress with M/s. Eisenberg Group of Companies for signing a Memorandum of Understanding).

Faridabad Gas Based Power Project:

The project will be executed by the National Thermal Power Corporation (NTPC) with loan assistance from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). Project report for techno economic approval has been submitted by NTPC to Central Electricity Authority (CEA). Gas Authority of India Ltd. (GAIL) has been approvached to provide firm time frame for gas supply for the plant so that OECF loan assistance may begin. As per information received from Ministry of Power (MOP), the OECF loan assistance is likely to be available by March, 1994.

Hisar Thermal Power Project :

Two units each of 250 MW for Hissar Thermal Power Project have been identified by the Central Electricity Authority in 9th Plan and the project has been fully cleared. A Memorandum of Understanding has been signed by the Haryana Govt./Board with M/s. Cogentrix of U.S.A. for setting up the project as a joint venture. Terms and conditions of power purchase and operating agreement are being negotiated.

Misappropriation/Irregularities in Forest Department

***615. Sh. Om Parkash Beri:** Will the Minister for Forests be pleased to state-whether any enquiry was conducted by the Vigilance Department in regard to the misappropriation/irregularities in the forestry plantations in

Mankawas village of Bhiwani district during the year 1984; if so, the results thereof togetherwith the action taken thereon ?

Forest Minister (Rao Inderjit Singh): Yes. An enquiry was conducted by Vigilance Deptt. with regard to the misappropriation of Govt. money and the irregularities committed in the forestry plantation in Mankawas village of Bhiwani district during the year 1982-83 and 1983-84. The Vigilance Deptt. report has indicated the then D.F.O. (T), Bhiwani, two Rangers and four Foresters, for committing irregularities in plantation work conducted at village Mankawas. Based on vigilance report, a charge sheet was served upon the concerned D.F.O. (T) under Rule 8 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969. The other employees were placed under suspension and charge sheeted under Rule 7 of the Civil Services Rules.

An enquiry board consisting of Enquiry Officer, Vigilance Deptt. and Conservator of Forests (HQ) was constitued to enquire into the allegations against D.F.O. (T), Bhiwani. The enquiry board held Sh. K.L. Minhas, I.F.S., D.F.O. (T) responsible for irregularities committed in the forestry plantation in Mankawas village of Bhiwani Distt. Based upon the enquiry report, a tentative decision was taken by the Govt. to award stopped of two grade increments with commulative eflect to the said officer. Under Rule 10(1) (e) of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules, 1969, the matter was referred to the U.P.S.C. for the concurrence. The U.P.S.C. did not agree with the State Govt. and advised the proceddings against the said officer to be dropped. Since a difference of opinion had arisen between the State Govt. and

U.P.S.C. reference was made to Govt of India, Ministry of Environment and Forests under Rules 11 of the All India Services (Discipline and Appeal) Rules for their decision. the Govt. of India also concurred with the view point of the U.P.S.C. In view of the decision of the Govt. of India, the proceedings launched against the said officer were dropped. Proceedings in respect of the Rangers and the Foresters are also likely to be finalised shortly.

Setting up of Police Station

***616. Sh. Rajinder Singh Bisla0:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the criteria fixed for setting up a new Police Station in the State together with the details of staff posted therein; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up new Police Stations in District Faridabad ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में एक सामान्य थाना बनाने के लिए निर्धारित माप दण्ड के अनुसार उस क्षेत्र में औसतन 75 मामले एक वर्श में दर्ज हुए हों, इसके अतिरिक्त कई अन्य तथ्य जैसे कि :–

1. क्षेत्र वि ोश में कानून व्यवस्था में गडबड।

2. असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में तीव्रता।

3. औद्योगिक अ ाान्ति/श्रमिक समस्या।

4. जनसंख्या में वृद्धि व नगर फैलाव।

5. नई कालोनियौं का निर्माण तथा अन्य विकास परियोजनाएं भी एक नये थाने के बनाने के मापदण्ड में भाामिल है। एक सामान्य थाना के लिए 1– उप निरीक्षक, 1– सहायक उप निरीक्षक, 1– प्रधान सिपाही और 12– सिपाही का न्यूनतम स्टाफ निगरानी यातायात और नियमित डियुटियों के स्टाफ के अतिरिक्त होना चाहिए। पुलिस थाने की नफरी ग्रामीण/ ाहरी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर बढाई जाती है।

(ख) हां। जिला फरीदाबाद में एक नया पुलिस स्टे ान सुरजकुण्ड में बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Kaithal and Bhuna Sugar Mills

***618. Dr. Ram Parkash:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) the date on which the Kaithal and Bhuna Sugar Mills starred functioning;

(b) the total quantity of sugarcane crushed in these mills during the year 1991-92 and 1992-93 separately; and

(c) the total profit earned or loss suffered by the aforesaid mills during the period as referred to in part (b) above ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया): (क), (ख) और (ग) ब्यौरे का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

		कैथल चीनी मिल	भूना चीनी मिल
1	मिल के कार्य आरम्भ करने की तिथि	2–4–1991	15–1–1992
2	पीड़े गये गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटलों में) 1. 1991–92 वर्श में 2. 1992–93 वर्श में	 23.46 21.17	 4.98 12.09
3	हानि (रूपये लाखों में) 3. 1991–92 वर्श में 4. 1992–93 वर्श में	 780.69 666.75	 557.27 804.08

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Construction of Roads from Village Kutiyana to Jorkia

***99. Sh. Mani Ram Rupawas:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-the time by which the construction work of sanctioned road from village Kutiana to Jorkia in District Sirsa will be compled ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): गांव कुतियाना के जोडकीया (जोरियां) सडक अस्वीकृत की जा चुकी है। अतः इसके पूरा करने के समय को बताने का प्र न ही नहीं उठता।

Construction of Road

***100. Sh. Mani Ram Rupawas:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-the time by which the work on the sanctioned road from Village Rajpur to Kheri will be completed by the Market Committee Sirsa ?

कृशि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह): सडक निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

Construction of Road

***101. Sh. Mani Ram Rupawas:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a road from village Sahuwala to Kairwala and from village Jamal to Naabad Barwali and Panjabu Head in District Sirsa; if so, the time by which these roads are likely to be constructed ?

कृशि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह): गांव साहूवाला से केरावाली तक सडक का निर्माण कार्य हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य 31–12–93 तक पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त गांव जमाल से गांव माधो सिंहाना सडक निर्माण योजना के अधीन गांव जमाल से

नाअबाद बरवाली तथा पंजाबू हैड तक सडक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

Construction of Road from village Raghwana to Darba Alias Rupana Khurd

***102. Sh. Mani Ram Rupawas:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-the time by which the work on the sanction road from village Raghwana to Darba Alias Rupana Khurd will be completed by the Market Committee Sirsa ?

कृशि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह): इस सडक का निर्माण कार्य दिनांक 31–3–94 तक पूरा होने की संभावना है।

Ban on the Sale of Lottery

112. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister for Finance be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to put a ban on the sale of Haryana State Lotteries ?

Finance Minister (Sh. Mange Ram Gupta): At present, there is no proposal under consideration of the Govt. to put a ban on the sale of Haryana State Lotteries. But there is a proposal to ban by legislation all private lotteries, State Lotteries/Lotteries authorised/permitted by the State/Union Territory Administrations, which are run/organised by private persons/Parties/promoters except those as have been organised by the Govt. of a State/by the Govt. of India/Union Territory itself within the territory of State of Haryana.

Distribution of Commodities

***113. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state-the names of the village where Anganwadi Centres are set up in the Palwal Block of District Faridabad together with the details of items/Supplementary Nutrition distributed to the beneficiaries in the above said centres during the year 1992-93 ?

Minister of State for Social Welfare (Capt. Ajay Singh Yadav): The name of villages where Anganwadi Centres have been set up in Palwal block, District Faridabad alongwith the details of the items/Supplementary Nutrition distributed during 1992-93 is enclosed.

The summary of Supplementary Nutrition items supplied during 1992-93 are as follows :-

Sr. No.	Name of items	Quantity in Kgs.	Cost of items Rs. P.
1	Chana	29228.300	250721.35
2	Moong Dal	12898.500	177203.80
3	Ghee	41417.05	133987.70
4	Chana Dal	13632.500	132227.85
5	Gur	23726.325	140201.75
6	Moong	2297.560	29032.20

7	Rice	49616.290	254654.05
8	Moongphali	5995.374	127696.90
9	Namkin	594.000	15304.50
10	Biscuit	1559.750	38748.75
11	Wheat	39816.450	117793.70
12	Salt	2732.600	7416.20
13	Panjiri	5580.000	
			1424989.75

Electricity Connections for Tubewells

***121. Sh. Karan Singh Dalal:** Will the Minister for Power be pleased to state-the total number of Tubewell connections released to the farmers in Palwal constituency during the year 1991 todate; together with the number of application lying pending at present ?

बिजली मन्त्री (श्री ए0सी0 चौधरी): हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में चुनाव क्षेत्र के अनुसार आंकडें नहीं रखे जाते हैं। 1 जनवरी 1991 से लेकर 31 जुलाई, 1993 तक बोर्ड के पलवल डिवीजन में 734 टयूबवैल जारी किए गए थे। 31 जुलाई, 1993 तक टयूबवैलों के 1023 आवेदन पत्र लम्बित पडे थे।

Dhudla P.H.C.

122. Sh. Karan Singh Dalal: Will the Minister for Health be pleased to state-the number of villages attached with the P.H.C. Dhudhla in Palwal Constituency ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती भाान्ति राठी): 50 गांव।

वि ोशाधिकार प्रस्तावों/ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय

अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचनाएं देना

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रिविलिज मो ान है। कल आपने कहा था कि वह अंडर कंसीड्रे ान है।

Mr. Speaker: It is still under consideration.

श्रीमती चन्द्रावती: फिर तो सै ान खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: उसके बारे में गवर्नमैंट से कमैंटस मांगे हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, गवर्नमैंट के कमैन्टस तो आएंगे नहीं और सै ान खत्म हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में मुझसे अलग से बात कर लें।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं अलग से बात कर लूंगी। इसके इलावा, स्पीकर साहब, मेरे दो काल अटैन्ा ान मो ान भी हैं। एक

एडजर्नमैंट मो ान था वह काल अटैन्ा ान मो ान में कन्वर्ट कर दिया है और वह कल के लिए है।

Mr.Speaker: Your call attention motion regarding acute shortage of water and electricity in districts of Bhiwani and Mohindergarh has been sent to the Govt. for comments. Your second call attention motion is regarding serious famine condition in Loharu constitutency. It is under consideration, and the third call attention motion is regarding abduction of Sushila, teacheress. It is disallowed.

Sh. Amar Singh Dhanak: Sir, What about my call attention motions ?

Mr. Speaker: Your calling attention motion regarding acute shortage of irrigation water in Distt. Bhiwani has been admitted for 1st September, 1993. Your calling attention motion regarding acute shortage of drinking water in Bhiwani district and other parts of the State and third regarding shortage of electricity in the Haryana State have been sent to the Govt. for comments.

प्रो0 राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने एक एडजर्नमैंट मो ान दी थी और जिसको काल अटैन्ा ान मो ान में परिवर्तित कर दिया है। मैं इस बारे में गुजारि ा करना चाहता हूं कि आपने भी नारनौल की घटना को बहुत अहमियत दी है और सदन में चर्चा के लिए स्वीकृति दे दी है। मैं चाहता हूं कि काल अटैन्ा ान की बजाए आप इस पर एक घंटा समय सदन में बहस के लिए दे दें। स्पीकर साहब, कल दो एडजर्नमैंट मो ांज आपके

सामने आये। एक पर तो आपने चर्चा करवा ली और दूसरे को जो मेरी ओर से बहन चन्द्रावती जी व श्री ओम प्रका ा बेरी जी की ओर से था। उसको आपने काल अटैन्ा न मो ानमें कंवर्ट कर दिया और हमने आप की बात मान ली। लेकिन हम आपसे गुजारि ा करते हैं कि इस काल अटैन्ा न पर डिस्क ान के लिये कम से कम एक घण्टे का समय तय कर दें ताकि सभी सदस्य इस पर खुल कर डिस्क ान कर सकें। दूसरा स्पीकर साहब, मेरा बिजली की सप्लाई के बारे में भी एक काल अटैं ान मो ान था। आपको सर पता है महेन्द्रगढ का इलाका टेल का इलाका है। वहां पर पीने का पानी भी बिजली से ही मिलता है। वहां पर बिजली की बहुत बुरी हालत है। आप कृपया बताएं उस काल अटैन्ा न की क्या फेट है ?

श्री अध्यक्षः वह अंडर कंसिड्रे ान है।

प्रो0 राम बिलास भार्माः धन्यवाद।

साथी लहरी सिंहः स्पीकर साहब, मेरा भी भूगर मिल के बारे में काल अटैं ान मो ान था .....

श्री अध्यक्षः वह अभी अंडर कंसीड्रे ान है।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला द्वारा –

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला (नरवाना): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेने ान। मुख्यमंत्री ने मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में ट्रांसपोर्ट विभाग के प्र न के उत्तर में कहा कि ओम प्रका ा चौटाला ने मिनी बसें खरीदीं थीं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट विभाग को काफी घाटा हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बसें पब्लिक वेलफेयर के लिये हार्ड पावर्ड कमेटी की सहमति से खरीदने का आदे ा दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, छोटे रूट पर जो बसें चलती हैं नि चत रूप से उनमें घाटा होता है क्योंकि उनमें स्टुडैंटस भी बैठ कर जाते हैं और पास होल्डर्स की संख्या भी उनमें ज्यादा होती है। लम्बे रूट की बसें तो घाटे को कवर कर जाती हैं। लेकिन आज जो प्र न था, वह इस बात को लेकर के था कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। आज मुख्य मंत्री ने इस बात को लेकर हाउस में कहा कि इस मामले में विजीलैंस की इंक्वायरी हुई है और उस विजीलैंस की रिपोर्ट में यह आया है कि इसके लिये ओम प्रका ा चौटाला दोशी हैं। मुझे बहुत खु ाी होगी कि यह हरियाणा सरकार जो पिछले 26 महीनों से चल रही है, अगर इस सरकार में दम हो तो उस विजीलैंस की जांच के आधार पर ओम प्रका ा चौटाला पर मुकदमा दर्ज करे। हमने कई सरकारें देखीं हैं। (थम्पिंग) बडे बडे दिग्गज और आनैस्ट मुख्य मंत्री, उस चेयर पर बैठे हुए लोगों से, हम टकराये हैं। (थम्पिंग) इस प्रकार की चरित्र हनन की राजनीति वे करते हैं, जिन्होंने भ्रश्टाचार को आधार मान कर, ट्रांसपोर्ट विभाग को प्राईवेट सैक्टर में कंवर्ट करने के लिये, मन चाहे लोगों

से पैसे लेकर, उनको बासों के परमिट देने के आधार पर, सारे ट्रांसपोर्ट विभाग की व्यवस्था ही बिगाड दी। स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोग तो सरकारी कारों में घूम रहे हैं, लेकिन आम जनता की बीच जाकर कभी ये बसों की हालत को देखने की कोि ा ा करें तो इनको पता चलेगा। वहां लोगों को बसें उपलब्ध नहीं हैं। कोई बस में बैठ जाए तो उसके कपडे नहीं बचते।

श्री अध्यक्षः ओम प्रका ा जी, आप तो पर्सनल एक्सप्लेने ान देने के लिये खडे हुए थे। आप बैठ जाएं, यह कोई पर्सनल एक्सप्लेने ान नहीं है। (ाोर)

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सरकार में दम हो तो वह हम पर मुकदमा चलाएं। यह कमजोर सरकार की पहचान हुआ करती है। इस प्रकार की चरित्र हनन की कार्यवाही करने वाले ये लोग हैं। क्या हम कोई विजीलैंस से डरने वाले लोग हैं ? अगर इस सरकार में दम है तो हम पर मुकदमा चलाए। आज मैं यह चैलेंज करता हूं। मेरे खिलाफ तो क्या, मेरी पार्टी के दूसरे किसी सम्माननीय सदस्य के खिलाफ भी अगर सरकार में दम हो तो मुकदमा चलाए और अगर हम दोशी पाए जाएं तो इसके लिये हम बडी से बडी सजा भुगतेंगे। स्पीकर साहब, यहां पर ग्रेवाल कमि ान की रिपोर्ट भी धरी की धरी रह गई। सरकार उसको तो इम्पलीमैंट करके देखें। ये लोग इस प्रकार की चरित्र

हनन की राजनीति इसलिये करते हैं ताकि इनके भ्रश्ट कारनामों की तरफ लोगों की तवज्जो न जा सके। ये पैसे कैसे बटोरें, इस बात को ये आधार मान कर चल रहे हैं। स्पीकर साहब, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग चरित्र हनन की राजनीति कर रहे हैं। अगर इनमें दम हो तो मुकदमा करें, हम सामना करने के लिये तैयार हैं।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला: स्पीकर साहब, इनका प्वायंट आफ आर्डर क्या है ? इनकी तो जमनतें जब्त हो गई हैं, इनके तो बोलने का यहां पर कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिये। (ाोर) चार फिगर्ज से ऊपर ये लोग वोटस नहीं ले पाए और आज यहां पर आकर सिर मुंडवा कर बात करने की कोि ा ा करते हैं ? बडी हैरानी हो रही है हमें यह देखकर। (ाोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, इन श्रीमान जी ने यहां पर बडे जोर खरो ा के साथ कहा कि अगर सरकार में दम हो– ऐसी बात नहीं है कि सरकार में दम नहीं। यदि आप दोशी पाए गए तो आप जेल की सरीखें में जाएंगे ही। यह कोई बात नहीं है कि सरकार में दम नहीं है। सरकार ने इंकवायरी करवाई है, विजीलैंस से करवाई है। ओम प्रका ा चौटाला हो, सम्पत सिंह हो या कोई और हो, फिर कोई कांग्रेस

का ही क्यों नह हो, जो दोशी होगा, उसे अव य ही सरीखों के पीछे दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि चार फिगर में भी मैं वोट नहीं ले सका। (ाोर) आप तो उस समय मुख्य मंत्री थे और आपके पिता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। यहां हाउस में आपके 85 सदस्य थे। आपका यहां पर पूरा बहुमत था और केन्द्र में भी आपके पिता सरकार में थे। तब जाकर आप इनती वोटों से जीते थे। अब जो व्यक्ति 62 हजार वोटों से जीता है, वह मुख्य मंत्री नहीं था बल्कि मुख्य मंत्री का पुत्र था। (ाोर) आप यदि इस बात का जिक्र न करते तो मैं भी न करता, कल बात खत्म हो गई थी। (ाोर) जहां तक दडबा कलां की बात है, वहां से आप इतने हजार वोटों से जीते लेकिन उसके 6 महीने बाद आप इलैक ान लडने की हिम्मत नहीं कर सके। पहले इनके भाई रणजीत सिंह रोड़ी से इलैक ान लडने की बात कर रहे थे और ये दडबा कलां से लडने की बात कर रहे थे। (विघ्न)

एक आवाजः रणजीत सिंह तो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं।

चौधरी जगदी ा नेहराः अगर कोई घर में आ जाए तो उसको धक्के मार कर नहीं निकाला जाता। मैं तो यह कहता हूं कि ओम प्रका ा को छोड कर इनका सारा परिवार कांग्रेस की तरफ है। एक बात इन्होंने कही कि 6 महीने के बाद, जब चुनाव हुए तो हमारे बिल्कुल अनजान आदमी श्री मनीराम वहां से 6 हजार वोटों से जीते। स्पीकर साहब, ये खुद वहां से 50 हजार वोटों से

जीते थे तो 6 महीने के बाद इतनी वोटें इनकी कैसे कम हो गई ? इसलिए वे वहां से दोबारा इलैक ान लडने की हिम्मत नहीं कर सके। फिर इन्होंने बसों का जिक्र किया, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। जब ट्रांसपोर्ट और फाइनैंस डिपार्टमैंट, दोनों ने यह कह दिया कि मिनी बसें खरीदना बाएबल नहीं हैं तो फिर इन्होंने वे बसें क्यों खरीदी और वे भी इतनी ज्यादा तादाद में ? आपको पता है कि उसके बाद अखबारों में क्या क्या बातें आई ? इन्होंने मजदा और टयोटा से किस ढंग से कमी ान लिया ? इसके इलावा, जो मिनी बसें हैं, वे चाहे लम्ब रूट की हों, चाहे छोटे रूट की हों, उनकी बाएबिलिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट देखता है, न कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर परचेज कमेटी का हैड होता है, तो क्या उसको डिपार्टमैंट के व्यू को ओवर लुक करना चाहिए ? क्या हर बात में कमि ान खाना चाहिए ? आपने तो गरीब लोागें को सौ रूपए देख कर उसमें से भी दस रूपए खा लिए। इसलिए आपको बोलने की कैसे हिम्मत हुई ? (ाोर) स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि छोटे रूटस के परमिट प्राईवेट लोगों को दिए जा रहे हैं। गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि छोटे रूट अनवाएबल हैं, उनके परमिट प्राइवेट लोगों को दिए जाएं। क्योंकि वहां सवारियों की पूरी सुविधा नही ंहै, वे अपने टैम्पो या मिनी बसें चला कर लोगों को सुविधा दे सकें। इसके साथ साथ ऐसा करने से अन एम्पलायड को भी एम्पलायमैंट मिलेगी। इसमें सिर्फ मिनि बसों के परमिट अनएम्पलायड नौजवानों को देने की बात है। स्पीकर साहब, सबसे बडी बात इनके समय में

जो हुई, वह 1200 बसेां की जलाने की हुई। इन श्रीमान जी के ला एण्ड आर्डर में 1200 बसें सोनीपत और रोहतक में जलाई गई। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के बारे में यह स्थिति थी कि चौधरी देवी लाल चाहते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के बारे में, यदि हमारी पूछ नहीं हुई तो कया होगा ? इसलिए इन्होंने यह तरीका अपनाया और बसें जलाईं। स्टेट गवर्नमैंट का कोई ऐसा औफिस नहीं रहा जिसको इन्होंने नहीं जलाया हो। फिर आज ये कानून व्यवस्था की बात कैसे करते हैं ?

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः स्पीकर साहब, इस हाउस के सम्मानित सदस्य दुर्भाग्य से मंत्री के पद पर विराजमान हैं, इन्होंने बगैर जरूरत के इस प्रकार की बात को उठाने का प्रयास किया, जिसका कोई मतलब नहीं है। केवल इनकी एक सोच है कि ओम प्रका ा चौटाला के खिलाफ कीचड उछाला जाए। इनको इसका भी ज्ञान नहीं कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी की सहमति से जो निर्णय लिये जाते हैं, वे निर्णय सामूहिक होते हैं। अगर मुख्य मंत्री मौजूद हों तो वह चेयर पर होता है। अगर न हो तो उस मीटिंग को कमेटी का दूसरा सदस्य प्रिजाइड करता है, कोई दूसरा नहीं करता। कमेटी की मीटिंग के आधार पर ये निर्णय लिए गए थे और उस निर्णय के खिलाफ अगर मौजूदा सरकार यह समझती है कि कोई बेकायदगी हुई है तो विजिलैंस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्कवायरी कराएं, उसकी सजा भुगतने के लिए हर आदमी पूरी तरह से तैयार है। इस सदन का एक सम्मानित सदस्य

कहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरह से बिगड गई। जो लोग टैरेरीस्टस को प्रोटैक ान दिया करते थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर दिखाते ? अभी रीसैंटली, चार दिन पहले पन्नी वाला मोटा गांव में मंत्री के परिवार के सदस्यों ने किसी के घर पर जा करके उन लोगों की मारपीट की, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए ? ये बात को निराधार बढाने की कोि ा ा करते हैं लेकिन इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस बात को ले करके, इस बेकायदगी के खिलाफ किस ढंग की आवाज उठाई जाती है। ये प्वायंट आफ आर्डर लेकर बैठ जाते हैं, इनको प्वायंट आफ आर्डर की परिभाशा का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार देने के लिए प्राईवेट सैक्टर में बसों के रूट परमिट देने का काम किया है। क्या ट्रेजरी बैंचिज के लोग यह बताएंगे कि अगर प्राईवेट सैक्टर में लोगों को रूट परमिट दिए जाएंगे, तो जो मौजूदा एम्पलाइज हैं, जो बसों पर काम कर रहे हैं क्या उनकी छंटनी हो जाएगी ? अगर वहीं लोग काम करेंगे तो फिर दूसरे लोगों को कैसे रोजगार दिए जाएंगे ? रोजगार देने की बात को ले करके ये अनेक प्रकार की ऊल–जलूल की बातें करने की कोि ा ा करते हैं। चरित्र हनन की राजनीति अपनाने का एक ध्येय अपना कर चलते हैं। ऐसे लोग, इस बात को केवल मुख्य मंत्री कैसे राजी हो सके, इस बात के प्रयास में लगे रहते हैं जनता को राजी करने से काम चलेगा लेकिन मुख्य मंत्री को राजी करने से तो कुछ अर्सा ही बीत सकता

है। इस प्रकार से चरित्र हनन का इल्जाम लगाने की बजाये, जो असलियत हो, वह लोगों के समक्ष पे ा करनी चाहिए।

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। चौधरी ओम प्रका ा चौटाला ने इस ढंग से बात कही कि मुझे हाई पावर्ड परचेज कमेटी के बारे में कुछ पता नही नही है। इन्होंने कह दिया कि उसके चेयरमैन मुख्य मंत्री होते हैं। श्रीमान जी आप तो साढे 6 महीने ही मुख्य मंत्री रहे हैं और आपकी सरकार में सम्पत सिंह और धीरपाल जैसे आदमी थी, इसलिए आपने साढे 6 महीने राज चला लिया, वरना साढे 6 महीने भी नहीं चलता। मेरा एक्सपीरियंस साढे 6 साल का है, साढे 6 महीने का नहीं है। स्पीकर साहब, एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। (विघ्न) (इस समय श्री राम कुमार कटवाल बोलने के लिए खडे हो गये)

श्री अध्यक्षः कटवाल साहब, आप बिना परमि ान के न बोलें, बोलने से पहले आप परमि ान लें। आपको बोलने की परमि ान नहीं है इसलिए आप अभी बैठिये।

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, चौधरी ओम प्रका ा जी ने बडे ही नफीस ढंग से अपनी बात कही परन्तु उनके अपने घर के आदमियों मे ंभी झगडा हुआ। हमारे घर का जो झगडा हुआ उसका बाकायदा पर्चा दर्ज हुआ है। अगर हमारे घर के आदमी गलत काम करेंगे तो सजा होगी। मैं आपके घर की

बात करता हूं। (विघ्न) इनके लडके और उनके भाई प्रताप सिंह के बीच गोलियां चलीं और पर्चा दर्ज हुआ। (विघ्न) अगर आप ऐलिगे ान्ज लगाएंगे तो आप पर भी ऐलिगे ांज लगेंगे। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः स्पीकर साहब, ये बिल्कुल निराधार बोल रहे हैं, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ है।

चौधरी जगदी ा नेहराः आपके भाई चौधरी प्रताप सिंह और उनके साथियों तथा आपके समर्थकों में झगडा हुआ। भाई भाई का झगडा है, हमारा तो इसमें कोई झगडा नहीं है, पर्चा दर्ज है। रवी सिंह सरपंच है, उसने पर्जा दर्ज करवाया है, उस सरपंच की डैथ हो गई है, परन्तु डबवाली सदर में पर्चा दर्ज हुआ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी सरकार होते हुए भी हमारे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही ही न हो। (विघ्न) वह सारी बातें आपकी हैं। यह सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और तीन साल तक आपकी छाती पर हम यूं ही मूंग दलेंगे।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

(1) पलवल क्षेत्र के आसपाल के गांवों में टिडडी दल के प्रकोप संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 4, from Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding fury of locust swarm which is prevailing in the area of Palwal. I admit it. Sh. Karan Singh Dalal may read

his notice and the Minister concerned may make a statement thereafter. (Interruptions).

श्री कर्ण सिंह दलालः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पलवल के इलाके में वि ोशकर गांव दुर्गापुर, रजपुरा, रजोलका, अहरवां, रायपुर, रतीपुर, गेलपुर, कैराका, अल्लीका, कारना, धतीर, घुघेरा, धमाका, दुधौला, अलावलपुर व सभी आसपास के गांवों में टिडडी दल का प्रकोप है। टिडडी दल ने उपरोक्त गांव की खडी फसल को पूरी तरह नश्ट कर दिया है। कृशि विभाग के अधिकारियों को इलाके के किसानों ने कई बात उक्त टिडडी दल के खिलाफ ि ाकायत की है। लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य–

कृशि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker: Now, I will request the Agriculture Minister to make a statement.

Agriculture Minister (Sh. Harpal Singh): Speaker Sir, during the current year some locust swarmshave entered into India through Pakistan and are confined to Jaisalmer, Barmer, Jalaur and Jodhpur districts of Rajasthan and some districts of Gujarat State. On reciept of the inforamation of invasion of locust in Rajasthan all the Divisional

Commissioners, all the Deputy Commissioners and all the Deputy Directors of Agriculture in the State were alerted through wireless regarding lucust activity in Rajasthan State. The officers of Revenue Department, Agriculture Department and Police Department have been imparted training to combat locust in districts adjoining to Rajasthan. Locust control teams have been formed in districts Sirsa and Hisar. The district officials have been oriented to the system of surveillance and monitoring of the movement of locust. At the same time a notification has been issued under the East Punjab Pest and Disease and Noxious Weed Act, 1949 to empower the Deputy Commissioners to mobilise manpower for controlling pest. The press and media has been used to alert the people about the likely locust invasion. The Department has distributed posters, pamphlets and booklets in the districts on the control of locust.

The Government has sanctioned a sum of Rs. 97.70 lakhas for the year 1993-94 to purchase BHC 10 percent dust and hand dusters. Adequate quantity of BHC 10 percent dust has already been stocked in Sirsa, Hisar, Bhiwani, Mahendergarh and Rewari districts to meet the threat of locust. The hand dusters already lying with the Department are kept ready for use as and when the need arises. I personally held a meeting with the Deputy Commissioners, Sirsa and other district officers and reviewed the arrangements made so far to control locust on 18th August, 1993 at Sirsa. The district officers were directed to keep constant vigil about the locust activities in the neighbouring district of Rajasthan.

As far as the invasion of locust swarms in district Faridabad is concerned, it has been verified from Deputy Commissioner, Faridabad Commissioner, Faridabad has obtained a certificate from the Sarpanches of the villages Durgapur, Rajpura, Rajaulka, Aharwan, Raipur, Dudhaula, Alawalpur in this respect. However, the Deputy Commissioner, Faridabad has informed that some scattered grass hoppers have been noticed on fodder crop. There is not significant damage to the crops on this account.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, पूरे पलवल के इलाके में मैं स्वयं गांवों में जाकर देख कर आया हूं और जिस तरह से मंत्री जी ने सदन में मना किया है कि वहां पर टिडडी दल का कोई प्रकोप नही ंहै। वे हाउस की बैठक के बाद मेरे साथ चलें या किसी आफिसर को वहां भेज दें और वे उन गांवों में जाकर देंखे कि कितना नुकसान हुआ है ? मैं यह पक्के तोर पर तो नहीं कह सकता कि कुल कितना नुकसान वहां पर हुआ है ? स्पीकर साहब, हमारे यहां हरे रंग का कीडा होता है जिसे लोग राम जी की गाय बोलते हैं, यह 1–1½ इंच लम्बा होता है। उसने फसल को पूरी तरह से नश्ट कर दिया है। जब इस बारे में अधिकारियों को कहा गया तो वे आज तक खेतों को देखने बिल्कुल नहीं गए। हमने बार बार कहा कि वहां पर नुकसान हो रहा है। आज सरकार ने कहा है लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। इन्होंने जबरदस्ती दस्तखत करवाए होंगें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इन गांवों में एक स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा दें और जिनका नुकसान हुआ, उसे दें। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने

कहा कि टिडडी दल पाकिस्तान से राजस्थान में होती हुई आयी है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान हमारे दे ा हमारे दे ा के लिए बहुत भारी पड रहा है और खास तौर पर इस प्रदे ा के लिए क्योंकि कई नेता भी इस प्रदे ा में पाकिस्तान से आए हुए हैं जो इस प्रदे ा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, कर्ण सिंह दलाल जी ने जो नोटिस दिया है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जब से हरियाणा बना है, तब से इसमें टिडडी दल का हमला नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 1962 में जब ज्वायंट पंजाब था, तब हमला हुआ था। दलाल साहब इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वह कितना बडा होता है, कितना लम्बा होता है और वह कितना भारी नुकसान करता है।

श्री अध्यक्षः हरपाल सिंह जी, अभी पीछे टिडडी दल गुजरात में आया है।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब,मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। जब दलाल साहब ने यह देखा ही नहीं है फिर ये उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वह टिडडा होता है या टिडडी होती है ? ये अभी कह रहे थे कि उसको इनके यहां पर राम जी गाय कहते हैं। स्पीकर साहब, इसको पंजाबी में टिडडी कह देते हैं ओर इनके यहां इसको राम जी गाय भी कह देते हैं। वहां पर अभी कोई टिडडी दल नहीं आया है इसलिए प्रकोप की कोई बात नहीं है।

इसने तो अभी तक राजस्थान मे ंभी एंटर नहीं किया है, फिर भी राजस्थान और हरियाणा के साथ लगते जो जिले हैं, उनसे हम इन टच हैं। उनके सीनियर आफिसर्ज से हमने कंटैक्ट किया है। अभी तक हरियाणा बिल्कुल सेफ है और टिडडी दल का कोई प्रकोप नहीं है। जहां तक फसलों के नुक्सान की बात है, अगर दलाल साहब हमें नुकसान दिखना चाहें तो मैं इनके साथ एग्रीकल्चर डायरैक्टर या किसी दूसरे अफसर को भेज दूंगा और जितनी किसानों की मदद हम कर सकते हैं, वह हर वक्त करने को तैयार हैं।

चौधरी अजमत खांः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से दलाल साहब को बताना चाहूंगा कि टिडडी दल अभी कहीं भी नहीं है। हां, एक टिडडा जरूर है जिसे हमारी भाशा में सरोर कहते हैं जो ज्वार और बाजरे के पत्तों को खा जाता है ओर यह अक्सर हो जाता है। स्पीकर साहब, हमारी फसल टिडडी दल से खराब नहीं हो रही है बल्कि बारि ा और सूखे से खराब हुई है। उनके मुआवजे की बात करें तो ठीक भी है। लेकिन वहां पर टिडडी का कोई प्रभाव नहीं है, वह तो सरोर ही है जो फसल खराब कर रहा है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, चौधरी अजमत खां जी ने सदन में कम से कम इस बात की तो हां की है कि वहां पर कोई रोग फैला हुआ जरूर है जो फसलों को नुक्सान पहुंचा रहा है चाहे वह कोई भी हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना

चाहूंगा कि जब सरकार के नोटिसमें यह बात है कि फसलों का नुकसान हो रहा है, खडी फसलों को वह पूरी तरह से खाता जा रहा है तो अभी तक क्यों नहीं दवाईयों का प्रयोग करते हैं ? स्पीकर साहब, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट जितनी भी दवाईयां किसानों मे ंबांटता है, वे सारी की सारी दवाईयां नकली हैं क्योंकि उन दवाईयों के छिडकने से खडी फसल बर्बाद हो जाती है। चौधरी अजमत खां जी के इलाके के एक गांव गोपाल गढ में जब ईंख में दवाईयों का छिडकाव किया गया तो वह खडी ईंख सूख गयी। अगर मंत्री जी चाहें तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी अधिकारी को हमारे साथ भेज दें ताकि वह हमारे साथ जाकर स्वयं देख लें। स्पीकर साहब, मैं यह चाहता हूं कि ये चण्डीगढ से किसी जिम्मेदार औफिसर को वहां भेज दें हम उनको वह फसलें दिखाएंगे।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी ने इसके लिए पहले ही कह दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, वहां पर जो फसलें खराब हुई हैं, क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में विचार करेगी ? (व्यवधान)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमने भी इसके बार में अपनी मो ान दी है।

श्री अध्यक्षः आप भी इस पर एक सप्लीमैंट्री पूछ लेना।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, हमारी पार्टी के एम0एल0एज0 के एक कालिंग अटैं ान मो ान दी थी कि नारनौल की घटनाओं के बारे में थी कि वहां पर पुलिस फायरिंग से किसान मारे गये हैं आज भी वहां पर मुकदमें बनाये जा रहे हैं और जो दोशी लोग हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है।

(2) 10 अगस्त 1993 को नहरी जल की समस्या पर नारनौल के आई0टी0आई0 के प्रांगण में एक जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have recieved an adjournement motion given notice of by Sh. Om Parkash Beri, M.L.A., Smt. Chandravati, M.L.A. and Sh. Ram Bilas Sharma, M.L.A. regarding the police firing on a peaceful gathering of people at Narnaul. Hon'ble Members, as I had announced in the House yeasterday I have converted this adjournemtn motion into calling attention motion and had admitted it for today. Now Sh. Om Parkash Beri may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, इसी सबजैक्ट पर मेरी भी एक कालिंग अटैं ान मो ान थी उसका क्या बना ?

Mr. Speaker: Dalal Sahab, your call attention motion is also included in this calling attention motion. (Noise & Interruptions).

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, जैसा सदन में विपक्ष के नेता ने कहा है, वैसे ही मैं भी आपसे रिक्वैस्ट कर रहा

हूं। कल आपने बहुत लिबरली हमारे एडजर्नमैंट मो ान को काल अटैं ान मो ान में कन्वर्ट किया। हम आपकी बात को सर आंखों पर रखते हैं। इस सदन के सभी लोग इस बारे में कहना चाहते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, यह बात आपके डिस्क्री ान के अन्तर्गत आती हैं लेकिन अगर आप इस पर बहस की अनुमति दे दें तो सारी बात सामने आ जाएगी। स्पीकर सर, वहां बहुत बडा अन्याय हुआ है। हम सभी आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि आप अपने फैसले को रिव्यू करके इस मसले पर बहस करा दें।

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री राम बिलास जी भार्मा ने कहा कि नारनौल में 10 अगस्त को जो गोली काण्ड हुआ आजादी के बाद भाायद पहला ऐसा गोली कांड हुआ है, उन्होंने यह बात बिल्कुल ठीक कही है। हमने जो एडजर्नमैंट मो ान दी थी, उस पर अगर आप पुनर्विचार करके उसे एडजर्नमैंट मो ान के रूप में एडकिट करके एक घंटे की बहस करा दें तो सारी बात स्पश्ट हो जाएगी। सरकार यह कहती है कि रघु यादव दोशी है। आप जुडीि ायल इंक्वायरी करा लें, इसमें हर्ज की क्या बात है ? सारी बात सामने आ जाएगी।

Mr. Speaker: Beri Sahib, you please read your notice.

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: स्पीकर सर, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लें। अगर डैमोक्रटिक सैट अप को चोट

पहुंचाने की कोि ा ा की गई तो पूरे दे ा की अखंडता को बडा भारी खतरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्षः ओम प्रका ा जी, आप नोटिस पढें।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर सर, यह जो आपने एडजर्नमैंट मो ान को काल अटैं ान मो ान में कन्वर्ट कर दिया है इसके लिए हमारी रिक्वैस्ट है कि आप इस पर एक घण्टे की बहस करा दें। सम्पत सिंह जी ने भी इस बारे में मो ान दिया है। इस पर सभी के विचार आ जाएंगे। वहां जलसा हो रहा था। उस जलसे पर पानी फैंक सकते थे, अश्रु गैस छोडी जा सकती थीं ये क्या करते हैं जब चाहे गोली इस्तेमाल कर ली। उनकी डिमांड यह थी कि जो पानी दूसरे जिलों में जा रहा है महीने में 23–24 दिन वही दूसरी जगह सिर्फ 3 दिन जा रहा है, यह पानी हमको भी मिलना चाहिए। मैं आपसे यही डिमांड करना चाहती हूं कि सभी लोगों की काल अटैं ान मो ान इस बारे में थी। वहां आदमी मरे हैं लोगों के घर उजडे हैं, कुल लोग घायल हुए हैं, इसलिए यह बहुत संगीन मामला है, इस पर बहस का मौका दीजिए।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अंडर प्रोटैस्ट पढ देता हूं वैसे विचार यह था कि इस पर पूरी बहस होनी चाहिए थी ताकि बात साफ हो जाती। Sir, I want to draw the attention of this August 1993 a public meeting was being held in Narnaul protesting against the discrimination by the State Govt. with the ares of South Haryana in the allocation of

Canal Waters and were demanding democratically their legitimate share of Canal Waters which was being denied to them for the last 16 years as revealed by the 25th report of the Estimates Committee of this August House. The gathering was all peaceful and without any provocation the police resorted to firing which was uncalled for leading to the killings of innocent persons. The people of the areas of the South Haryana are agitated over this issue. They, therefore, request the Govt. to make a statement in this regard on the floor of the House.

वक्तव्य–

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सर्वजाति पंचायत के सभापति श्री रघु यादव ने 10 अगस्त 1993 को नहरी जल की समस्या पर नारनौल के आई0टी0आई0 के प्रांगण में एक सभा के लिए आहवान दिया था। उनके संगठन द्वारा दो स्थानीय संस्थाओं, आई0टी0आई0 एवं पोलीटैकनिक का नाम बदलने का भी विचार था। जिला प्राासन/एस0डी0एम0 द्वारा इस संस्था को माईक बजाने के लिए इस भार्त पर अनुमति दी गई थी कि वह इसका उपयोग सरकार प्रांगण के बाहर ही करें। जब इस आवेदन पत्र पर विचार किया गया उस समय तक आईटी0आई0 में 10–8–1993 को दाखिला हेतु साक्षात्कार होना निि चत था। इस साक्षात्कार के लिए उस दिन काफी संख्या में छात्रों को आई0टी0आई0 में आना था। प्रिंसीपल, आई0टी0आई0

ने सलाह दी थी कि प्रस्तावित सभा होने से आई0टी0आई0 के कार्य वि ोशकर दाखिला में काफी बाधा आएगी। इसी कारण प्र ाासन द्वारा आई0टी0आई0 के प्रांगण में सभा करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।

इन्हीं हालातें को देखते हुए मौके पर उचित मात्रा में पुलिस का बन्दोबस्त किया गया था ताकि कोई दुर्घटना न हो जाए। सभा आई0टी0आई0 के प्रांगण के बाहर हुई और लगभग 2. 30 बजे बाद दोपहर तक भाांति पूर्ण रही लेकिन अपने भाशण के अन्त में श्री रघु यादव ने उपस्थित भीड को प्र ाासन के आदे ा तोड कर आई0टी0आई0 के प्रांगण में घुस जाने को ललकारा। इसके फलस्वरूप उपस्थित भीड हिंसा पर उतर आई।

जब सभा चलती रही स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद पुलिस भी संयम बरतती रही लेकिन जब भीड ने काफी पथराव किया और आई0टी0आई0 के प्रांगण में घुस आई तो यह आ ांका हुई कि भाायद इससे जान और सरकार माल को काफी क्षति हो सकती है।

लाऊड स्पीकर पर एस0डी0एम0 ने भीड को चेतावनी दी कि वे जगह छोड कर चले जाएं। जब बार बार दी गई चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोडें। आंसू गैस के गोले हवा के रूख के कारण कामयाब नहीं हुए तो एस0डी0एम0 ने लाठी चार्ज का आदे ा दिया। लेकिन

भीड नहीं हटी। इसी बीच भीड की एक टुकडी नजदीक स्थित अधिकारियों की कालोनी में घुस गई और कुछ घरों में घुस कर उनके सामान की तोड फोड करने लगी। भीड ने हरियाणा परिवहन की लगभग 10 बसों को भी नुकसान पहुंचाया। एस0डी0एम0 ने भीड को तितर बितर करने के लिए हवा में गोली चलाने का आदे ा दिया। जब इससे भी हिंसक भीड पर कोई असर न हुआ तो एस0डी0एम0 ने भीड के ऊपर निचले हिस्सों की तरफ नि ाना करके गोली चलाने के आदे ा दिए। कुल मिला कर 30 गोलियां चलाई गई। गोली लगने से एक आदमी मारा गया, 38 आदमी और 9 पुलिस कर्मचारी घटना में घायल हुए। बाद में पता चला कि मृतक आदमी का नाम सुरेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सिंह राम, गांव मुडलाना, थाना सदर नारनौल था। इस संबंध में पुलिस द्वारा श्री रघु यादव तथा उसके साथियों के खिलाफ हिंसा भडकाने और डयूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोपमें एफ0आई0आर0 नं0 359 एवं 360 दिनांक 10.8.93 भा0द0स0 की धारा 148/149/332/353/397/188/427/435/452 के अन्तर्गत थाना नारनौल में दर्ज की गई।

13.8.93 को सरकार ने इस घटना की आयुक्त, गुडगांव मंडल द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच किए जाने का आदे ा दिया। आयुक्त गुडगांव मण्डल ने एक विस्तृत जांच की और अपनी जांच

रिपोर्ट सरकार को 18.8.93 को दी। इस जांच रिपोर्ट के मुख्य निश्कर्श निम्न प्रकार से हैं :–

(क) सर्व जाति पंचायत को आई0टी0आई0 के मैदान में सभा करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। पंचायत को केवल सरकारी प्रांगण के बाहर लाऊड स्पीकर प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) इस बिन्दु पर कि क्या पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना जरूरी था, जांच रिपोर्ट में यह निश्कर्श निकाला है कि आयोजकों द्वारा गैस जिम्मेदार एवं गैर कानूनी गतिविधियों के कारण ही स्थिति बिगडी। श्री रघु यादव तथा उसके सहयोगियों ने प्र ाासन द्वारा बार बार गैर कानूनी कार्यवाही न करने बारे दी गई चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पडा।

(ग) जांच रिपोर्ट में माना गया है कि इस हालत में बल का जो प्रयोग किया गया वह ज्यादा नहीं था। बल्कि पुलिस ने काफी धीरज से काम लिया।

(घ) रिपोर्ट में माना गया है कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि पुलिस ने कुछ ला ाों को गुम कर दिया और पुलिस की कार्यवाही से हजारों लोग जख्मी हुए। जांच में यह भी पाया गया कि पुलिस द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने का आरोप भी निराधार है।

(ड़) रिपोर्ट में माना गया है कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि पुलिस ने कुछ ला ाों को गुम कर दिया और पुलिस की कार्यवाही से हजारों लोग जख्मी हुए। जांच में यह भी पाया गया कि पुलिस द्वारा असभ्य कार्यवाही किए जाने का आरोप भी निराधार है।

(च) जांच से साबित हुआ है कि हिंसा की घटनाओं में केवल एक आदमी की मृत्यु हुई है।

(छ) जांच रिपोर्ट से साबित होता है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के भारीर में 2–3 धातु के टुकडे मिले हैं। जांच रिपोर्ट में यह निश्कर्श निकाला है कि बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बिना यह सही रूप से नहीं कहा जा सकता कि मृतक की मौत पुलिस की गोली से हुई है। बैलेस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी आनी है।

(ज) आयुक्त ने यह पाया है कि श्री रघु यादव प्र ाासन के साथ झगडा करने पर तुले हुए थे और उसने भीड को हिंसा के लिए भडकाया। जांच रिपोर्ट के अनुसार यदि खून खराबे के लिए कोई जिम्मेवार है तो वह श्री रघु यादव है जिसके विरूद सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकार ने पहले ही मुतक के परिवार को 50000/– रूपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत कर दिया है। हालांकि इस मामले में प्र ाासन की कोई गलती नहीं थी लेकिन इस क्षेत्र के

लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार ने महेन्द्रगढ जिला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक और नारनौल के उप मण्डल अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया है।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा है मार्किटिंग कमेटीज की आमदनी को ज्यादा तौर पर किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इस साल हमने 12 करोड रूपये नई मंडियों के लिए रखा है साढे चार करोड रूपए पुरानी मंडियों को ठीक करने के लिए रखा है 12 करोड रूपये नई सडकें बनाने के लिए रखा है और जो लिंक रोडज हैं उनकी रिपेयर के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 को 7 करोड रूपए दिए गए हैं। यह मेन खर्चा है। बाकी खर्चा आफिस बनाने के लिए या कोई छोटा मोटी बिल्डिंग बनाने के लिए या किसानों के लिए रैस्ट हाउसिज बनाने के लिए प्रोविजन है।

चौधरी अजमत खानः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी बताया कि मार्किटिंग कमेटीज की जो आमदन है उसको ज्यादा तर किसानों को सुविधाएं देने के लिए खर्च किया जाता है। लेकिन मार्किट कमेटीज ज्यादा पैसा म्यूनिसिपल कमेटी के ऐरिया में सडकें बनाने पर खर्च करती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मार्किट कमेटीज में जो आमदन है, वह किसानों का पैसा है। इसलिए क्या उस पैसे को मार्किट कमेटीज के ऐरिया में खर्च करने का प्रावधान करेंगें। किसानों के लिए खास तौर से सडकें या यातायात के साधन बहुत जरूरी हैं लेकिन

रैस्ट हाउसिज के नाम पर पैसा खर्च किया जाता है, उससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता केवल कर्मचारियों को फायदा हो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार रैस्ट हाउसिज बनाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सडकें बनाने पर पेसा खर्च करेगी ताकि किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिल सके ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मार्किटिंग बोर्ड का पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज को रोडज पर ज्यादा खर्च हो रहा है। यह बात दुरूस्त नहीं है। मार्किटिंग बोर्ड की लगभग 100 फीसदी जो खर्च हो रहा है उसमें से केवल मात्र 15 परसैंट पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज की रोडज पर खर्च हो रहा है और वह भी उन रोडज पर जो मण्डी को मिलाती है और जो एप्रोच रोड हैं। जो किसान देहात से आते हैं उनके लिए एप्रोच रोडज पास तो करनी पडती हैं इसलिए किसानों को सहूलियत देने के लिए उन रोडज की टेकअप किया गया है लेकिन इन रोडज पर 15 फीसदी से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता।

श्री सतबीर सिंह कादयानः स्पीकर साहब, चमराडा से पूठर और सीवाहा से जेजडोला तक सडकें मंजूर हो गई थीं और उनके लिए टैंडर भी काल हो गए थे। क्या सरकार उन सडकों को बनाने के लिए काम भाुरू करेगी या उन ट्रैंडर्ज को तोड कर फैंक देगी। कोई भेदभाव न रखते हुए, क्या सरकार उन सडकों को बनाने की कोि ा ा करेगी ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह तो प्रोसैस की बात है। पहले टैंडर काल किए जाते हैं। फिर उसके बाद टैंडर आते हैं और उसके बाद खोले जाते हैं। फिर किसी को काम अलाट होता है और काम भाुरू होता है। इस हिसाब से हर जगह जहां पर काम सैंक ांड है वहां काम चालू है। मैं सदन को बताऊंगा कि पिछले डेढ साल में मार्किटिंग बोर्ड ने 565 किलोमीटर लम्बी सडकें तैयार की हैं इससे पहले के चार सालों में कभी भी इतना काम नहीं किया गया। पिछले चार सालों में कभी 600 किलोमीटर लम्बी सडक नहीं बनी थी लेकिन हमने डेढ साल में 600 किलोमीटर के लगभग सडक तैयार की है, इतना काम इससे पहले कभी नहीं हुआ था।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने एक सप्लीमैंटरी के जवाब में बताया कि 12 करोड रूपया देहातों में नई सडकें बनाने के लिए खर्च किया गया है। मैं उनसे इस बारे में डिस्ट्रिक्टवाइज डिटेल जानना चाहूंगा कि कौन कोन से डिस्ट्रिक्ट में मार्किटिंग बोर्ड ने कितनी कितनी लम्बी सडकें बनाई हैं। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके तहत जितना आमदनी मार्किट फीस से एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को होती है उसमें से कम से कम आधा पैसा अलग से रख करके एक रिवोलविंग फंड क्रिएट किया जाए ताकि किसानों को एग्रीकल्चरल

इम्पलीमैंटस पेस्टीसाईडज फर्टीलाईजर और सीडज पर सबसिडी दी जा सके।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इनके पहले सवाल के जवाब में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये इसके लिए अलग से नोटिस दे दें क्योंकि इस वक्त मैं यह नहीं बता सकता कि सारी स्टेट में किस किस जिले में मार्किट कमेटीज द्वारा सडकें कहां कहां पर कितने कितने किलोमीटर बनाई गई हैं। दूसरा सवाल इनका रिवाल्विंग फण्डज के बारे में हैं। इस बारे में उन्होंने पहले भी एक क्वै चन किसी दिन किया था। रिवाल्विंग फण्ड के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा मौजूदा एक्ट है उसके तहत हम रिवोल्विंग फण्ड नहीं दे सकते, यह हमारी दिक्कत है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक सवाल तो मेरा यह है कि भिवानी जिले में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा कितेन किलोमीटर रोडज बनाई गई हैं और उन पर कितना पैसा खर्च किया गया है। दूसरा मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ज्वायंट पंजाब के वक्त 1963–64 में तकरीबन 8–10 एकड जमीन में लाखों रूपये खर्च करके बवानी खेडा में सबयार्ड बनाया गया था जबकि उस वक्त तो इल्ड भी अधिक नहीं थी। अब वहां पर कुछ इलाके में पानी होने की वजह से ईल्ड भी अधिक होती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये वहां पर मार्किट कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं

श्री अध्यक्षः आपका यह सवाल मेन सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री जिले सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 12 करोड रूपया नई मंडियों पर और साढे चार करोड रूपया पुरानी मंडियों के विकास पर खर्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे ध्यान में 5–7 मण्डियां ऐसी हैं जो 5–7 साल पहले बनाई गई थी जैसी बेरी, घरोण्डा, झज्जर, कोसली आदि। इन मण्डियों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की सुविधा न होने की वजह से हालात बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि सरकार नई मण्डियां बनाने की बजाये जो पुरानी मण्डियां पहले बन चुकी हैं। उनके विकास पर अधिक ध्यान दें ताकि उनमें वाटर सप्लाई सीवरेज आदि की सुविधा हो सके। क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर गौर करके पुरानी मण्डियों को डिवैल्प करने पर विचार करेगी ?

श्री हरपाल सिंहः मैंने पहले भी बताया है कि पुरानी मण्डियों पर जो साढे चार करोड रूपया खर्च किया जा रहा है वह इसलिए खर्च किया जा रहा है कि उन मण्डियों में जो अधूरे काम पडे हैं, वे पूरे हो सकें। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रोहतक जिला, सोनीपत जिला और दिल्ली के आसपास की जो मण्डिया हैं, उनकी सारी फसल इन मंडियों में न जाकर, दिल्ली में बिकती है जिसकी वजह से मार्किटिंग बोर्ड को काफी घाटा उठाना

पड रहा है। अब की बार तो फसल को कहीं पर भी लाने ले जाने पर बैन न होने की वजह से पानीपत और करनाल तक की फसल भी दिल्ली में जा कर बिकी है। इस बारे में मेरा सभी एम0एल0एज0 साहेबान से अनुरोध है कि वे ऐसी कोई सुजै ान सरकार को दें जिससे इन मंडियों का विकास हो सके।

श्री के0एल0 भार्मा: स्पीकर साहब, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मार्किटिंग बोर्ड द्वारा 565 किलोमीटर लम्बी सडकों को बनाया जा चुका है। वर्श 1991–92 में मार्किट कमेटी के पास जितना भी बजट था उसमें से एक किलोमीटर सडक भी नहीं बनाई गई और सारा बजट लैप्स हो गया। मैं इस बारे में मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन से भी मिला था। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे भााहबाद की सडकों का मुहर्त कब होगा

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, भार्मा जी अभी रिसैन्टली हमारे पास आए हैं, इनकी सडकों को मुहर्त भी जल्दी ही कर दिया जाएगा। (हंसी)

श्री रामपाल सिंह कंवर: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा है कि वर्तमान एक्ट के तहत रिवाल्विंग फण्ड बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मार्किटिंग फीस को किसानों के हित के लिए इस्तेमाल करने के बारे में मैं चाहूंगा कि इस ऐक्ट में अमैंडमैंट लाई जाए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस ऐक्ट में अमैंडमैंट

करके मार्किट बोर्ड की फीस से रिवाल्विंग फण्ड किसानों के लिए बनाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, यदि नहीं तो क्या ऐक्ट में अमैंडमैंट करके रिवाल्विंग फण्ड बनाए जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मार्किट कमेटी के फण्डज आल रेडी किसानों के वैल्फेयर के लिए खर्च होते हैं इसलिए मैं इस बात की कोई आव यकता नहीं समझता कि इस ऐक्ट को अमैंड किया जाए।

श्री के0ए0ल भार्माः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि ये रिसैंटली आए हैं, इस वजह से मेरी सडकों का मुहूर्त बाद में निकालेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो सदस्य विपक्ष के हैं, क्या उनकी सडकों को मुहूर्त कभी नहीं निकलेगा

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, वह तो मैंने भार्मा जी को मजाक में कहा था। इनकी सडकों का जो बैकलोग है हम उसको जल्दी ही पूरा कर देंगें।

सरदार जसविन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि मार्किट कमेटीज का पैसा किसानों के भले के लिए खर्च होता है। पेहोवा हल्के में मेरा गांव है जिसकी 6200 एकड जमीन है और सबसे ज्यादा मार्किट फीस मेरे गांव से जाती है। 1970 से पहले वहां पर एक लिंक रोड बना था लेकिन उसके बाद

कोई सडक नहीं बनाई गई। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो गांव सबसे ज्यादा मार्किट फीस दे कया उसी के रकबे और आबादी को देखते हुए ज्यादा पैसा उसी इलाके पर खर्च किया जाए जहां से ज्यादा पैसा फीस के रूप में आता है क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी

श्री हरपाल सिंहः जो बात जसविन्द्र सिंह जी ने पूछी है उसके बारे में भाायद उनके नोटिस में नहीं है। हम स्ट्रिक्टली ज्यादा पैसा वहीं पर खर्च करते हैं जहां से ज्यादा मार्किट फीस आती है। जो कमेटी रैजोल्यू ान पास करके भेजती हैं, मार्किटिंग बोर्ड उसके मुताबिक पैसा बजट में दे देता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः चेयरमैन साहब पिछले साल नकल हुई और पर्चे लीक हुए। मुख्य मंत्री जी ने आ वासन दिया था कि चाहे कोई भी आदमी हो, जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ इन्क्वायरी करवाई जाएगी। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक एस0डी0 स्कूल है, वही आदमी जो एक साल पहले बोर्ड का अध्यक्ष था, उसको सरकार ने हटा दिया। यह तो सरकार की मर्जी है जिसको चाहे हटा सकती है लेकिन उस आदमी ने उस स्कूल को अपने घर की सम्पत्ति बना ली है। उस स्कूल की कोई लीगल मैनेजिंग कमेटी नहीं है और कोर्ट ने भी इल्लीगल करार दे दिया है। स्कूल वालों ने सरकार को यह लिख

कर भेजा है कि उन्हें सरकार से कोई ग्रांट नहीं चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा स्टेट में ऐसा कोई और स्कूल है जो इस तरह का है ? चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि भिवानी में एजूके ान को एक तरह का अखाडा बनाया हुआ है। ऐसे लोगों ने एजूके ान को कमर्ियलाइज्ड कर दिया है। इन लोगौं ने इन संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। मेरी सरकार से अर्ज है कि उसके अगेंस्ट एक ान लिया जाए। इसी डिमांड पर बोलते हुए मैं मैडीकल कालेज के बारे में एक बहुत ही आ चर्यजनक बात बताना चाहूंगा। हरियाणा प्रदे ा में एक ही मैडीकल कालेज है। चेयरमैन साहब, 1992 में मैडीकल कालेज में, जिस तरह से 10 लडकों का दाखिला हुआ, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पहले तो उन 10 लडकों को डाक्टर ने कलरविजन के बेसिज पर अनफिट डिक्लेयर कर दिया लेकिन उन लडकों ने एक अलग से बोर्ड बनवा लिया जिस का वही डाक्टर अध्यक्ष बनाया गया। अब इस बारे में वही डाक्टर जाने या बोर्ड जाने। उस डाक्टर ने उन लडकों से एक एक लाख रूपए रि वत लेकर दोबारा मैडीकल कालेज में एडमिट करवा दिया। चेयरमैन साहब, कलरविजन एक ऐसी बीमारी होती है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। जो लडके पहले रिजैक्ट किए हुए थे, उनसे उस डाक्टर ने एक एक लाख रूपए लेकर दोबारा दाखिला दिला दिया। मैं कहना चाहूंगा कि हैल्थ मिनिस्टर साहिबा इस प्रकार की गडबड जो कमर्ियलाइजे ान ऑफ मैडीकल एजुके ान के आधार पर हुई है, उसको तुरन्त बंद किया जाए।

चेयरमैन साहब, पिछली बार चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जो सडक से न जुडा हो। मेरे हल्के में जो बौन्द खुर्द गांव है, उसकी वोट भी 1691 है, लेकिन उसको आज तक सडक से नहीं जोडा गया है जबकि मुख्य मंत्री ने 31–5–92 तक सडक से जोडने के बारे में कहा था। अब 31–5–93 आने को है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से मांग है कि उस गांव को जल्दी से जल्दी सडक से जोडा जाये।

Mr. Chairman: No repetition please. All these things have already come on record. Please take your seat. Shri Rajinder Singh Bisla, Shri Zakir Hussain and Shri Azmat Khan will speak on the Appropriation Bill. Now Shri Ram Bilas Sharma will speak.

प्रो0 राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): चेयरमैन साहब, हरियाणा और पंजाब के लोगौं आतंकवादियों के साये में काली रातें गुजारी हैं। आतंकवादियों ने न जाने कितने निर्दोश लोगों की जानें लीं। इन उग्रवादियों के खिलाफ न केवल पंजाब की पुलिस लडी, बल्कि हरियाणा की पुलिस भी लडी और अपनी भाहादत दी। चेयरमैन साहब, राजनेता की 'विल' लडती है और नौजवान की छाती लडती है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पडता है कि पिछले दिनों खन्नौरी गांव में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुलिस के चार नौजवान गए, उनके पीछे उनकी सुरक्षा के लिए कोई फालो अप ऐक ान नहीं लिया; उनको बचाने

का कोई प्रबन्ध नहीं किया। आतंकवादी तो अपनी योजनानुसार एक कमरे में थे और उन्होंने उन चारों जवानों को भाहीद कर दिया। वे चारों जवान वहां पर भाहीद हो गए। उनके भाहीद होने पर उनके परिवार वालों से किसी ने जाकर हाल तक नहीं पूछा, जबकि उनके परिवार वालों ने कहा कि वे तो भाहीद हुए हैं। इन चार नौजवानों में मरने वाला एक मेरे नारनौल का रघुनंदन भी था। मैं उसके घर पर गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से उनकी भाहादत के बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं की गई। चेयरमैन साहब, पुलिस में चाहे किसी अधिकारी/कर्मचारी की परमो ान की बात हो, बिरादरी के नाम पर कभी परमो ान नहीं की जाती। यह जाट है, यह ब्राह्मण है या और किसी बिरादरी का है, इस आधार पर उसकी परमो ान की जाए, तो अच्छी बात नहीं है। मेरी मांग है कि सी0एम0 साहब को इन सब बातों की तरफ गौर करना चाहिए और जिसका जो हक बनता है, उसको दिया जाना चाहिए ताकि पुलिस के जवानों की 'विल' न टूटे। चेयरमैन साहब, किसी पुलिस अधिकारी के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हमने कभी मुख्य मंत्री जी से यह नहीं कहा कि इस अफसर को यहां लगाओ या उस अफसर को वहां लगाओ, लेकिन किसी अफसर को सूबेदार बना दिया जाये और जो कुछ वह चाहे करे ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को कम से कम ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उस सिपाही ने स्कूल में पढने वाले बच्चे के बारे में सच्च बोला था। चेयरमैन सर, जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनको काम करने की इजाजत होनी

चाहिए। उनको यूं दबा कर, उनके गले में अंगूठा देकर अगर इस तरह से करेंगे तो प्रजातन्त्र से लोगोंं का वि वास उठ जाएगा।

Chief Parliamentary Secretary (Sh. Subhash Batra): On a point of order, Sir.

Prof. Ram Bilas Sharma: Mr. Chairman Sir, what is his point of order ?

Mr. Chairman: Ram Bilas Ji, he has a right to put a point of order.

Prof. Ram Bilas Sharma: What type of point of order, he wants to raise ? यानि कि जिस जगह की चर्चा मैं करूंगा, वहां के आदमी खडे हो कर प्वायंट आफ आर्डर करने लग जाएंगे ? चेयरमैन सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने रोहतक नगरपालिका की चर्चा की है।

Mr. Chairman: Sharma Ji, let him say, whatever he wants to say.

श्री सुभाश बत्राः चेयरमैन सर, अभी माननीय सदस्य ने रोहतक नगरपालिका की चर्चा की। रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी में हमारे साथ क्या हुआ, मैं इनको बताना चाहता हूं (विघ्न) चेयरमैन साहब, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, यह किस टाईप का प्वायंट आफ आर्डर है ? ये मेरे खिलाफ प्रिविलेज मो ान ला सकते हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाश बत्राः चेयरमैन साहब, हाईकोर्ट में एस0एल0पी0 के अन्दर इन लोगों के साथ क्या हुआ ? डबल बैंच ने इनके खिलाफ फैसला दिया, दोबारा चुनाव हुए और हमारी म्यूनिसिपल कमेटी बाकायदा वोट से बनी।

Prof. Ram Bilas Sharma: Is it the point of order, Sir ?

Mr. Chairman: He has just clarified the position, what you had stated about Rohtak Municipal Committee. Now you speak.

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, यह प्वायंट आर्डर की बात ही नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी हो गई है कि इस इलाके से एम0ए0ए0 बन गए तो खुदा बन गये। यह त्यौहार तो हर तीसरे साल होना है, अब तो यह 6 महीने बाद ही होने वाला है। जिस का जैसा आचरण है, जनता उसको देख रही है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, नगरपालिका का मामला है। एक आदमी जो दारू का ठेकेदार है, उसने नगरपालिका, की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। उसके बारे में डिप्टी कमि ानर ने जो लिखा है, वह मैं आपको बताता हूं :–

"I also direct the MC Mahendergarh to re-verify the dimensions of the plot of Sh. Leela Dhar to ascertain whether the construcdtion is within his own limits or not. In case the construction is found outside his ownership, the Committee

shall be at liberty to demolish the portion of the building which has been encroached by the applicant."

चेयरमैन साहब, कंस्ट्रक ान के बारे में नगरपालिका के सामने गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये हरिजनों के बारे में बडी बडी बातें करते हैं कि उनको सरप्लस की जमीन दी जाएगी। कल कृश्ण लाल जी ने बात कहीं तो कहने लगे कि कुछ फैक्टस की बात होती है। चेयरमैन साहब, यमुना नगर जिले में खदरी गांव है, दादुपुर गांव है। वहां पर दौ सौ एकड जमीन सरप्लस पाई गई है। वह जमीन हरिजनों को अलाट हो गई थी परन्तु वे गरीब हरिजन, उस जमीन का कब्जा लेने की स्थिति में नहीं थे वह जमीन उनको नहीं मिली क्योंकि उस जमीन पर जिस आदमी का कब्जा था, उसका किसी कांग्रेस के आदमी से ताल्लुक है। चेयरमैन साहब, या तो ये कानून न बनाएं या हरिजनों को यह न कहें कि हम आपको जमीन देंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो इन्हें हरिजन भाई याद आएंगे। चैयरमैन साहब, आज हरिजनों की आबादी बढ रही है, पिछडे हुए लोगों की आबादी बढ रही है। उनकी बढती हुई आबादी के अनुसर, उनको कहीं पर भी प्लाट नहीं दिए जा रहे हैं। एक ही कमरे में बेटा है, बाप है, वहीं पर बकरी है और वही पर चूल्हा हैं बारि ा के दिनों में गरीब की झुग्गी चूएगी और सावन में उसकी झुग्गी भी जाएगी। चेयरमैन साहब, मध्यप्रदे ा में हमारी सरकार बनी तो बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर का जन्म दिन मनाया उस समय वहां की हमारी पार्टी की सरकार ने 4 लाख एकड जमीन पिछडे हुए लोगों को दे दी।

उसका इन्तकाल भी उनके नाम करवा दिया। यहां पर जो सरप्लस जमीन है, पंचायत की जमीन है उसके लिए चौ0 भजन लाल जी और इनके मंत्री लोगों का आपस में डुक बज रहा है। चेयरमैन साहब, या तो ये हरिजनों की बात न कहें, अगर कहें तो उनको थोडा बहुत देना चाहिए। कुछ बातों की तरफ इनको देखना चाहिए और कुछ बातों को सिरे चढाना चाहिए वरना जो हरिजन कमजोर हैं, उसको न्याय नहीं मिलेगा। संगरेहेड़ी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु उस हरजिन को दबा कर उनका आपस में राजीनामा करवा लिया। चेयरमैन साहब, इनको याद रखना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतिहास में काला दाग छोड जाती हैं। हरिजनों की बातें, खुद मुख्य मंत्री जी नोट भी करते हैं, परन्तु नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको सीरियसली नहीं लेती। संगरेहेड़ी में संतोश के साथ बलात्कार हुआ। उसका घरवाला गया तो उसको जान से मार दिया गया। बाद में उसका बाप गया तो उसको भी डराया धमकाया कि तेरा जीना दूभर कर देंगे और बाद में उसके साथ राजीनामा करवा दिया। चेयरमैन साहब, यह कैसा इन्साफ है यह कोन सा राज है ? अगर गरीब को न्याय नहीं मिलेगा और केस दबा दिया जाएगा तो उसका क्या होगा ? यह जमीन किसी को माफ नहीं करेगी।

श्री सभापतिः आप जल्दी खत्म करें।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, मैं सामुदायिक विभाग के बारे में भी बोलना चाहता हूं। सरकार के पास कुछ

फण्ड होता है, कुछ पैसा होता है। राव बंसी सिंह जी बहुत ही भोले आदमी हैं। मेरे इलाके के हैं परन्तु ये जहां जाते हैं, वहां पर ये सिक्कों में तोले जाते हैं। कोई प्लीज कह दे तो ये उस पर मेहरबान हो जाते हैं, चाहे वहां पर किसी को जरूरत हो या न हो। चेयरमैन साहब, यह जो सिस्टम है, यह जो पैसा है, यह देख कर इस्तेमाल करना चाहिए। राव बंसी सिंह जी गांव की भूमिका से आए हैं, इन्हें गांव की जरूरत को देख कर पैसा देना चाहिए। यह नहीं है कि एक आदमी को जहां चाहा, वहां लगा दिया और दूसरा आदमी कहीं औंर लगा दिया। यह ठीक है कि ये महेन्द्रगढ में पैर जमाना चाहते हैं किन्तु इनको यह नहीं पता कि मेरे सामने तो चौटाला जैसे भी चले गए। चेयरमैन साहब, ये वहां पर अन्याय न करें जिस गांव में जितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से पैसा दें। यह नहीं होना चाहिए कि जहां जहां इनको सिक्कों से तोला जाये, वहां ये पांच लाख रूपये दे दें। इसके अलावा, चेयरमैन साहब, सरकार कर्मचारी गरीब होता है, उसकी अगर कोई पिटाई करे तो अच्छी बात नहीं है। वहां पर एक डी0ई0टी0सी0 ने नगरपालिका के एक कर्मचारी की पिटाई की। पीटने वाले के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

विकास मंत्री (राव बंसी सिंह): चेयरमैन साहब, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेने ान है। मैं आपके माध्यम से हाऊस को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझ पाया कि पंडित जी को मेरी तरफ से गिला क्यों है इनके पेट में क्यों दर्द है ? मेरा हल्का तो अटेली

पडता है। मेरे दिमाग में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है लेकिन इनको पता नहीं क्यों सिरदर्द हो रहा है? यह दर्द भाायद इनको इसलिए हो रहा है कि जब ये स्वयं मिनिस्टर थे, तो इन्हौंने महेन्द्रगढ मैं तो क्या, अपने हल्के में भी कोई विकास के कार्य नहीं किए थे, लेकिन जब से चौ0 भजन लाल जी की सरकार बनी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ में ही नहीं, बल्कि सारे हरियाणा के जितने भी गांव हैं, उन सभी का कायाकल्प किया है। चेयरमैन साहब, हम सभी गांवों को वास्तव में कायाकल्प करना चाहते हैं। विकास के कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री जी की इजाजत है कि जिन जिन गांवों में अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया, उन सभी गांवों को पैसा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, जहां तक सिक्कों से तोलने की बात का ताल्लुक है मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर मुझे इन्होंने कहीं पर सिक्कों से तुलवाया हो तो बता दें। अगर कोई व्यक्ति मान सम्मान से मुझे सिक्कों से तोलता है तो इससे इनको क्यों दर्द हो रहा है, इसमें मुझे तो कोई लालच नहीं है ? मुझे लगता है कि उस मान सम्मान को देखकर ही इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक दर्द का नतीजा तो यह देख ही चुके हैं। ये वहां पर पंचायत समिति का चेयरमैन बनाना चाहते थे ..... (विघ्न)

श्री सभापतिः यह पर्सनल एक्सप्लेने ान नहीं है। आप कृपया बैठिए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः चेयरमैन साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये चाहे पचास बार सिक्कों से तुले, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। जो मेरा दर्द है वह मैं इन तक नहीं पहुंचा रहा हूं। यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

राव बंसी सिंहः चेयरमैन साहब, मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने चौटाला को देख लिया। अगर इनकी ऐसी ही भावनाएं हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे इनका चैलेंज स्वीकार है। (**इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए**)

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, आप इनसे यह पूछ लें कि यह चुनौती इनको अभी स्वीकार है या जब मौसम आएगा, तभी स्वीकार होगी ? मैं तो इस चैलेंज के लिए आज भी तैयार हूं।

स्पीकर साहब, चीनी के दाम बढा दिये गये हैं। इनके आर्थिक सुधारों के कारण गरीब आदमियों की जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं जबकि ये कहते हैं कि ये दे ा में आर्थिक सुधार करके क्रान्ति लाना चाहते हैं। आज मिटटी का तेल, डीजल सभी चीजें महंगी हो गयी हैं। गांव में रहने वाली आबादी को जो गेहूं और रा ान की जरूरत के हिसाब से गेहूं पैदा कर लेता है लेकिन जब गेहूं का ऐंड का सीजन आता है, उस समय छोटे छोटे किसानों को गेहूं की जरूरत पडती है। इसलिए मेरा कहना है कि

इन दिनों में इनको देखना चाहिए कि रा ान का ठीक प्रकार से वितरण होता है या नहीं। स्पीकर साहब, इसके अलावा, मैंने कल भी एक बात कही थी कि रिवाडी, महेन्द्रगढ, लोहारू, कौसली आदि सब डिवीजन बना दिये थे, लेकिन फिर तोड दिये। महेन्द्रगढ में तीन गांव ऐसे हैं जिनका जिला हैड क्वार्टर कहीं पर कर दिया और तहसील कहीं पर कर दी।

श्री अध्यक्षः राम बिलास जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः भजन लाल जी ने डिस्ट्रिक्ट री–आर्गेनाइजे ान कमेटी बनाई। मेरे हल्के के दौंगडाजाट, कलवाडी, मुडियाखेडा और गुलावला गांव ऐसे हैं, जहां की पंचायतों ने कहा कि उन्हें बडी असुविधा है। स्पीकर सर, इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे इलाके की जो सिंचाई की समस्या है, पानी तो जब उपलब्ध होगा, तब ये देंगे, परन्तु हमारे दो जिले ऐसे हैं जिनको किसी भी रैगुलर स्कीम, पैरिनियल स्कीम से जोड देना चाहिए। जो नियंत्रण योजनाएं हें जैसे अन्टा ग्रुप, भलोट ग्रुप, बुटाना ग्रुप एव सुन्दरवन ग्रुप– इनमें से किसी भी योजना के अन्तर्गत हम नहीं आते। जहां तक पीने के पानी का ताल्लुक है उस इलाके में जमीन के नीचे का पानी बहुत नीचे चला गया है, कहीं चार सौ फुट कहीं साढे तीन सौ फुट और कहीं पांच सौ फुट नीचे चला गया। यह वाटर गांव के लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। अतः मुख्य मंत्री जी इस को देखें और

प्रायरिटी के आधार पर पानी उपलब्ध कराएं क्योंकि हरियाणा में केवल यही इलाके ऐसे हैं जहां पीने के पानी की एक्यूट समस्या है, इसके लिए कोई न कोई पक्की व्यवस्था करें। स्पीकर सर, बातें तो बहुत हैं, दर्द इतने हैं मगर ...

श्री अध्यक्षः इन भाब्दों के रिकार्ड न किया जाए।

प्रो0 राम बिलास भार्माः पानी की जो समस्या है। उसको रैगुलराइज किया जाए। कम से कम पीने के पानी की कोई पक्की स्कीम बना दी जाए और उसे इन चार ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जोडा जाए।

श्री अमर सिंह (एस0सी0– बवानी खेडा): स्पीकर सर, हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज एक मसला है, जैसे बढती आबादी, अनएम्पलायमैंट और महंगाई की प्रोब्लम है वैसे ही चौथी बैकलोग पूराकरने की कोि ाश की है। मेरा यह दावा है कि अगर बैकवर्ड क्लासिज और हरिजन बैकलोग पूरा कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से और आंकडें के मुताबिक कोई भी हरिजन पढा लिखा बेरोजगार नहीं रह सकता। स्पीकर सर, 4218 कांस्टेब्ल्ज में से इन्होंने ि ाडयूल्ड कास्टस 718 भर्ती किए। इन्होंने जो रीजन बताया उस पर मुझे बडी भारी आपत्ति है। इन्होंने कहा है कि ि ाडयूल्ड कास्ट के कम्पीटैंट और सूटेबल कैंडीडेटस नहीं मिले। अगर मुख्य मंत्री जी इस बात का सर्व कराएं तो पाएंगे कि ि ाडयूल्ड कास्ट के दो लाख कैंडीडेटस के नाम एम्पलायमैंट ऐक्सचेंजिज में दर्ज हैं

और वे सब मैट्रिक पास हैं। यह जो रीजन दिया है यह बडा आपत्तिजमन है –

"candidates who were found suitable were enlisted form reserved category. Every effort will be made to fill up the backlog in the reserved category in the next recruitmen drive. Instructions have been issued to the concerned authorities to make good the shortfall in the Commando Force during the next recruitment proposed to be made during March, 1993".

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि पहली नवम्बर 1966 को पुलिस डिपार्टमैंट में भाोर्टफाल क्या थी, यह कैटेगरीवाइज बता दें। स्पीकर साहब, अगर हर डिपार्टमैंट में रोस्टर रजिस्टर मेनटेन कर दिया जाए, इसके बार में एक पौलिसी बना दी जाए कि हर हालत में रोस्टर मैनटेन किया जाए। स्पीकर साहब, ि ाडयूल्ड कास्ट को इग्नोर करने के लिए एडहौक बेसिज पर रिक्रूटमैंट करनी भाुरू कर दी। पिछले दिनों पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर ने बताया कि भाोर्टफल है और हम एस0एस0एस0 बोर्ड का इन्तजार कर रहे हैं। जब उसकी लिस्ट आएगी तो हम भाौर्टफाल पूरा करेंगे। कोई टाईम बाउन्ड पौलिसी बना दी जाए कि इतने समय के अंदर जो भाोर्टफाल है वह पूरी कर दी जायेगी। स्पीकर साहब, एक बार ज्वायंट पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने देखा कि ि ाडयूल्ड कास्टस की भाौर्टुाल पचास परसैंट है तो उन्होंने आदे ा दिए कि भविश्य में पचास परसैंट ि ाडयूल्ड कास्ट की भर्ती होगी और इस

तरह से भाोर्टफाल को पूरा किया। स्पीकर साहब, यहां पर नारनौल की बात आई। मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इस बात की वेरिफिके ान करा लें कि नारनौल में केवल हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती के लिए एलान किया गया था। वहां पर पचार हजार लडके चले गए। वहां पर कई ऐक्सीडैंट हुए। दो चार आदमी वहां पर सीरयसली जख्मी हुए लेकिन यह वजह देना कि सूटेबल कैंडीडेटस नहीं थे, यह ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, सभी डिपार्टमैंटस का यही हाल है। यह तो हुई सर्विसिज की बात। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों को जो दो लाख रिहाय ाी प्लाट दिए गए थे उन पर तो एक दौर ऐसा आया कि दूसरे लोगों ने ही कब्जा कर लिया। उनको वे प्लाट मिले ही नहीं और हरिजनों की पापुले ान बढने के बाद जो उनको नए प्लाट दिए जाने थे वे रूक गए। स्पीकर साहब, तीस परसैंट प्लाटों पर नाजायज कब्जा है। हर जिले में यही हालत है। मुख्यमंत्री जी आप इस बारे में हर जिले के डिप्टी कमि नर से रिपोर्ट मंगवा लें। स्पीकर साहब, सरप्लस जमीन की भी एक कहानी बन गई है। सरदार प्रताप सिंह जब मुख्य मंत्री होते थे तो उस समय मैंने कहा था कि कंसोलिडे ान का सिस्टम गलत है। जब कंसोलिडे ान हो तो सरप्लस जमीन का एक कुर्रा बनाया जाता है। एक कुर्रा अगर बनाया जाए तो उन हरिजन लोगों को एक जगह अलौटमैंट हो सकती है। कहीं दो एकड है, कहीं चार एकड है। अगर वह कब्जा भी ले ले तो कैसे उसको पानी मिलेगा और कैसे रास्ता मिलेगा ? इसलिए सरप्लस की

कहानी बिलकुल गलत है। स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल था जिसकी सरकार ने ऐक्सटैं ान मांगी है। वह सवाल था–

हरिजनों को सरप्लस जमीन देने की बात तो दूर रही आज हालत यह है कि हरिजनों को अपने प ा जगहों पर इनक्रोचमैंट हो रही है। स्पीकर साहब, यह बहुत बडा मामला है और सरकार इस तरफ ध्यान दे और औन दि फलोर आफ दि हाउस यह ऐन ायोर करे कि कस्टोडियन की जमीन से जो रूरल एरिया में हरिजनों को प्लाट दिए गए हैं। वे उनके मिलें और उन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, वह छुडाया जाए। (घंटी)

स्पीकर साहब, मैं बताता हूं कि पिछले दिनों हरिजनों की कितनी तरक्की हुई है।। सरकार बताएगी कि पिछले दिनों कितने असिसटैंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल कितने ि ाडयूल्ड कास्टज के और कितने बैकवर्ड क्लासिज के लगाये गये हैं ? जो 64 कारपोरे ांज के लीगल एडवाईजर्ज बनाए गए, उनमें से कितने बैकवर्ड क्लासिज के और कितने ि ाडयूल्ड कास्टस बनाए गए ? 18 नायब तहसीलदार प्रोमोट किये गये, उनमें से कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड क्लासिज के हैं ? जिस भर्ती का मैंने जिकर किया है उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि आज खेतों के अंदर केवल हरिजन लडके ही तो काम कर रहे हैं वे 6–6 फुट लम्बे कद के तगडे जवान लडके हैं। उनके सिवाये खेतों में और कौन काम करता है ? वही लोग उद्योगों में भी काम करते हैं लेकिन ऐसे

नौजवानों को दूसरी जगहों से यानी भर्ती से क्यों इग्नोर किया जा रहा है ? यह सारा काम हरिजनों के कन्धों पर ही तो है। स्पीकर साहब, ये जो इधर बराबर में एस0जे0पी0 के हमारे भाई बैठे हैं, बार बार यह कहते हैं कि सरकार ने हरिजनों के लिये यह कर दिया, वह कर दिया। स्पीकर साहब, जनता जनार्दन है जनता भाी ाा है। अच्छे काम ये सरकार करेगी तो लोग भााबासी देंगे। अगर यह गलत रास्ते पर चलेगी तो कल को इन्हीं की जगह पर दूसरी सरकार आ जायेगी। इसलिये सब तरह की रिस्पान्सीबिलिटी सरकार को ओन भी करनी चाहिये। इसलिये सब तरह की रिस्पान्सीबिलिटी सरकार को ओन भी करनी चाहिए। किसी की बात को टालना नहीं चाहिये क्योंकि यह सत्ता पक्षा की डयूटी है। जिसकी गलती हो, उसको सजा दे ताकि आगे से अच्छे काम हो।

स्पीकर साहब, कुछ साल पहले रेवेन्यू पास बुक्स किसानों के लिये बनीं। इनके लिये पांच पांच रूपये किसानों से लिये गये। मैं कहता हूं कि करप ान में कम से कम 30 परसैंट राहत मिल सकती है। यदि किसानों की पास बुक्स को बैंक पास बुक्स की तरह बना दिया जाए। ऐसा करने से जमींदारों को किसी वकील के पास नहीं जाना पडेगा। इसके अलावा, एक और मुसीबत की बात किसानों के साथ जुडी हुई है। अगर उसके खेत में हजार मन कपास पैदा हो जाए, उसकी लिमिट नहीं बढेगी ओर अगर वही कपास किसी फैक्टरी में चली जाए तो उसकी 10 लाख, 5 लाख की लिमिट बन जाएगी। मेरा कहना यह है कि होलडिंग के

हिसाब से लिमिट बननी चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर किसान की रेवेन्यू पास बुक को, बैंक पास बुक की तरह से बना दिया जाए तो जो पटवारी किसान की खाल नोचता है, उससे छुटकारा हो सकता है किसान लीगल ऐडवाईजर से भी बच जाएगा और उसे राहत भी मिल जाएगी। अगर रेवन्यू पास बुक, बैंक पास बुक्स की तरह हो जाएगी तो किसान जो चीज बेचेगा, उसमें दर्ज हो जाएगी, जो चीज खरीदेगा उसमें दर्ज हो जाएगी इससे उसे तरह तरह की मुसीबातें से छुटकारा मिल जाएगा और बाकायदा किसान को राहत मिलेगी। इसके इलावा, खेती की जमीन पर बहुत जयादा भार आ गया है, कृशि पर सारा बोझ टिक गया है। अब कृशि की 18 एकड की लिमिट है। पिछले दिनों यह होड लग गई कि कहीं यह लिमिट और न घट जाए। ताऊ के राज में यह नारा लग गया कि केवल 5 एकड जमीन होगी। वकीलों की चांदी बना दी और सबने बेनामी ट्रांजैक ान करवा लिये। दो–दो, तीन तीन एकड की होलडिंग बन गई। अब आप बताओ कि हरिजन काम करने के लिये कहां जाएगा ? हरिजन के रोजगार का तो किसान के कन्धों पर दारोमदार है। अगर किसान सुखी तो हरिजन दुखी। अगर किसान दुखी है तो हरिजन दुखी। दोनों का आपस में बहुत तालमेल है। हरिजन तो किसान के खेतों में ही काम करता है। अगर किसान की औलाद ही उसके अपने खेतों में काम करने की लिये काफी है तो हरिजन कहां समाएगा ? इसलिये मैं कहता हूं कि ऐग्रोबेसड इंडस्ट्रीज जो आप लगाएं, इससे जमीन पर बोझ कम होगा, जमीन की तरफ लोग कम दौडेंगे और दूसरी इंडस्ट्रीज की

तरफ लोगों का आकर्शण हो जाएगा और उद्योग धन्धों में वे अपना मन लगाएंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक लाख रूपया नै ानल ि ाडयूल्ड कास्टस कार्पोरे ान से लोन लेकर, जिसमें 60 प्रति ात लोन कार्पोरे ान देती है, 35 प्रति ात हरिजन कल्याण निगम देती है और 5 प्रति ात मार्जिन मनी होती है। स्पीकर साहब, मेरे हिसाब से हमारे पास सैंटर का भोयर आ जाता है लेकिन स्टेट का भोयर कन्ट्रीब्यूट नहीं होता। मुख्य मंत्री जी ने क्वै चन आवर में स्वयं माना कि जमीन के भाव बहुत बढ गए हैं, एक लाख या डेढ लाख रूपए किल्ले से कम भाव नहीं है। 70000 रूपए किल्ला तो टिब्बों की जमीन का रेट हो गया है। तो कार्पोरे ान से कह कर यह भोयर ज्यादा बढाएं। आप कार्पोरे ान से ज्यादा पैसा लें। हरिजनों को आपने का तकारी करने के लिए जमीन जोतने के लिए और पानी देने के लिए तथा भैंस पालने के लिए 27000 रूपया दिया है। स्पीकर साहब, 27000 रूपए में दो तीन भैंसें तो आ जाएंगी लेकिन उनका रख रखाव कहां से होगा। मैं चाहता हूं कि इसको वाएबल यूनिट बनाएं ताकि ि ाडयूल्ड कास्टस जमीन पर टिक सकें। एजूके ान के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि नकल रूकी है लेकिन उस हद तक नहीं रूकी जितनी रूकनी चाहिए थी। मैं यह कहता हूं कि ऐसा होने से जो हार्ड वर्किंगे स्टूडैंटस हैं वे क्या करेंगे। नकल करने वालों को तो बाहर से पर्ची भेज दी जाती है और वे अंदर नकल कर लेते हैं तथा 98 प्रति ात मार्कस उनको मिल जाते हैं। ऐसा होने से हार्ड

वर्किंग स्टूडैंअस को आपत्ति है। मैं मानता हूं कि एजूके ान कन्क्रैंट सब्जैक्ट है लेकिन फिर भी हमें इस बारे में कार्यवाही करने के लिए राश्ट्रपति जी से इजाजत लेनी चाहिए। वैसे ऐसा बिल इस सै ान में आना चाहिए था जैसा यू0पी0 सरकार ने पास किया है। इस सै ान में अगर किसी वजह से नहीं लाया जा सकता तो अगले सै ान में लाना चाहिए। इसलिए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कंसोलीडे ान जल्दी करवानी चाहिए। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे बहुत अफसोस के साथ कहनी पडी है कि सजपा के भाई जान बूझ कर हाउस में नहीं बैठते हैं। इसलिए नहीं बैठते हैं कि उनके कारनामें ही ऐसे हैं जिनको अपने सामने वे सुन नहीं सकते। हम उनको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि उनके राज में क्या हालात थे, किस तरह का माहौल था और क्या तरीका था उनके काम करने का। जो बात वे खुद करते थे, वे समझते हैं कि यह सरकार भी वैसे ही करती होगी। अध्यक्ष महोदय, जो इन्सान जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही समझता है। यहां पर दूसरी पार्टियां हैं, हरियाणा विकास पार्टी है, जनता दल है, बी0जे0पी0 है, सभी हैं।

श्री धर्मपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का टाईम भी नहीं दिया

गया। जब मैं बोलने के लिए खडा हुआ तो आपने कह दिया कि बैठ जाओ।

श्री अध्यक्षः कल आपको बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि बाकी सभी पार्टियों के माननीय सदस्य यहां हाउस में बैठे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि क्रिटिसिजम होना चाहिए लेकिन वह क्रिटिसिजम हैल्दी होना चाहिए। सरकार में यदि कोई कमी है तो उसके बारे में कहना चाहिए और यदि कहीं पर कोई नुक्स हो तो वह बताना चाहिए। उन्होंने अपने इलाके की कोई बात नहीं कही। न उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर पे ा हुए धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए अपने इलाके की कोई बात कही और न बजट पर बोलते हुए कोई बात कही। उनको लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। लोगों को उनसे बडी भारी उम्मीद हैं लेकिन उन्होंने अपने इलाके के लोगों की कोई बात यहां नहीं रखी। सिवाय उन्होंने बेबुनियाद और गलत बातें कहने के कोई दूसरी बात नहीं कही। यदि उनकी कोई बात ठोस होती तो वह समझ में आ सकती थी लेकिन बडे दुःख के साथ कहना पडता है और मैं परम पिता परमात्मा से कहना चाहूंगा कि परमात्मा उनको सदबुद्धि दे नहीं तो उनको आगे के लिए बडी मु कल हो जाएगी। इस समय जितने चुनकर आए हैं उतने भी नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने कुछ बातें

कहीं। इन्होंने एक बात तो यह कही कि फाइनैंि ायल कमि नर्ज ओर कमि ानर्ज बहुज ज्याद बैठाए हुए हैं और उनके काम का वितरण ठीक नहीं। उनसे जो काम लिया जाता है उसका बंटवारा ठीक नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी डयूटी यहां भी लगा रखी है और दिल्ली में भी लगा रखी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बडा भाानदार ला एण्ड आर्डर हरियाणा का रहा है। एक बात इन्होंने यह कही कि डी0जी0पी0 पर पुलिस का वि वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे डी0जी0पी0 बडे भाानदार अधिकारी हैं। वे निहायत ईमानदार और मजबूत आदमी हैं। हमारी पुलिस फोर्स ने डट कर काम किया है। जब चौधरी बंसी लाल जी ने उनको हिसार में एस0पी0 लगा रखा था तो उस समय इनकी बडी तारीफ किया करते थे।

श्री बंसी लालः आप क्या करते थे, वह भी बता दें ?

चौधरी भजन लालः मेरे जिले में लगा रखा था आपको भी याद होगा और मैं उस समय भी बहुत तारीफ किया करता था कि इससे बढिया कोई आदमी नहीं है। ये भी बडी तारीफ किया करते थे। पता नहीं इनकी थोडी से कोई नाराजगी हो जाये तो उसका ये पूरा ईलाज करते हैं। (विघ्न) मैं भी कहता था कि बढिया आदमी हैं, मैंने कभी बुरा नहीं कहा। मेरे जिले में लगा हुआ था। अगर ये बुरे होते तो वह दोनों के लिए एक ही बात हुआ करती थी। (हंसी) फिर उनको वहां रखते कैसे, अगर बुरे होते ? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने कभी बुरा नहीं कहा।

(विघ्न) सारी ऐडमिनिस्ट्रे ान और सारी पुलिस फोर्स का पूरा फेथ डी0जी0पी0 पर है और अगर फेथ न हो तो कोई कैसे कमान्ड कर सकता है और अगर कमांड ठीक नहीं हो तो प्रदे ा में कैसे अमन हो सकता है ? इन्होंने बहुत भाानदार कमांड की है। हमारी सारी पुलिस फोर्स बडी भाानदार है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी एक बात दोहरा देते हैं कि पुलिस की ऐसोसिए ान बननी चाहिए। मेहरबानी करके कभी तो इस बात को भूलो और अपने जमाने को भी याद करो।

श्री बंसी लालः 14 स्टेटों में पुलिस वालों की ऐसोसिए ान है।

चौधरी भजन लालः जब आप चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उस वक्त भी 12 स्टेटों में पुलिस ऐसोसिए ान हुआ करती थी, तब आपने क्यों नहीं बनाई ? आपने पुलिस की तो क्या, टीचरों की एसोसिए ान नहीं बनने दी, आज पुलिस की बात करते हो। पुलिस और फौज में अगर यूनियनें होंगी तो इस मुल्क की कभी एकता कायम नहीं रहेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दे ा के हित में होती हैं और जिनको ठीक रखना होता है। हमारा पुलिस पर पूरा फेथ है। सिपाहियों को या किन्हीं अधिकारियों की कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो उनके लिए हर समय सरकार के दरवाजे खुले हैं। एक सिपाही तक भी भजन लाल से मिल सकता है। यह बंसी लाल नहीं है कि अगर डी0सी0 भी मिलने आ जाये

तो कहे कि मेरी इजाजत के बगैर कैसे आया है, सस्पैंड कर दो। भजन लाल ऐसा नहीं कहता। यह आपके जमाने की बात है। मुझे तो सिपाही भी मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने फरीदाबाद की माईन्ज में लीकेज के बारे में कही है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि यदि वहां पर कोई लीकेज है और किसी का कसूर है तो हम उसको पूरा चैक करेंगे और सख्ती करेंगे तथा दोशी के खिलाफ एक ान लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक चौधरी बंसी लाल जी ने यह कहा कि भजन लाल के साहबजादे पुलिस के काम में दखल देते हैं और पुलिस की भर्ती के लिए घर पर ही नाप तोल करते हैं। चौधरी बंसी लाल जी इस बारे में मैं आपको और क्या कहूं, साहबजादा तो इस हरियाणा में एक ही है और वह है सुरेन्द्र सिंह, चौधरी बंसीलाल का लडका। (विघ्न) और कोई साहबजादा है ही नहीं। इस बारे में मुझे ज्यादा कहने की आव यकता नहीं, इसी बात से सारे लोग समझ जाएंगे। मेरे लडकों का कही ंपर कोई दखल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सियासी आदमी हैं। चौधरी बंसी लाल जी आपको तो कभी कभी सप्पा लग जाता है, कभी कभी लोग आपकी नाक भी रगडवा देते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से हमारा हिसाब किताब हमेशा ही ठीक रहा है। मैं आज तक किसी इलैक ान में हारा नहीं हूं। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि पुलिस की भर्ती में कोई दखल मेरे लडकों का नहीं है। स्पीकर

साहब, जब पुलिस की भर्ती होती है तो सियासी आदमी के घर पर सैंकडों आदमी जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के यूथ, कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी हैं। अगर किसी के पास कोई आ जाए और हरेक आदमी को सियासी आदमी नौकरी दे नहीं सकता, वह उसको कैसे कहेगा कि तू फिट नहीं है। (विघ्न) जब लगा नहीं सकता तो वह यही कहेगा कि फीता पडा है, नाप ले। अगर कोई नाप भी दे तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई जिला ऐसा नहीं जिस हल्के से कोई पुलिस की भर्ती न हो, यह कोई बात नहीं। (विघ्न) चौधरी साहब, आप अपने जमाने की सारी बातें भूल जाते हैं। एक आपने पुलिस में बी–1 ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ हदि तक ठीक हो सकती है। मैं मानता हूं हो सकता है जो साथ रहेगा और ठीक काम करेगा, थोडा बहुत एक आध नम्बर उसको मिल सकता है, लेकिन आप अपने जमाने को क्यों भूल जाते हैं ? जो आपके साथ थे, आपने तो क्लर्क से सीधे एच0सी0एस0 बना रखे हैं। डी0आई0जी0, आई0जी0 और एस0पी0 का क्या दोश है, आप जरा अपने मामले को भी देखें, उस बारे में आप क्या कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे इन्होंने कहा था कि 35 करोड रूपए उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार से आ गया है, वह पैसा अभी केन्द्र सरकार से आया नहीं है, हमने पैसा मांग रखा है, जब मिलेगा तो इनको बता देंगे। यह पैसा उसी काम में लगाएंगे जिस काम के लिए लेंगे। (विघ्न)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने यह कहा था कि मैंने सुना है कि 35 करोड रूपया आया है। ये यह न कहें कि मैंने यह कहा है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हमने यह पैसा मांगा है। पुलिस फोर्स को पूरी जीपें हथियार और दूसरा सामान दिया हुआ है ताकि वे अपने काम में किसी तरह की कमी न आने दें और काम में कोई कोताही न होने दें। पुलिस का मनोबल हम किसी भी तरह से कम नहीं होने देना चाहते। इन्होंने नीमड़ी गांव और रिवासा गांव का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि रिवासा गांव में लडकी के साथ बलात्कार के संबंध में मुकद्दमा नंबर 46 दिनांक 15–2–1993 जेरे दफा 376 दर्ज हो चुका है।

श्री अमर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि यह बलात्कार किस दिन हुआ और मैडिकल किस दिन हुआ ?

चौधरी भजन लालः मैंने बताया है कि 15 तारीख को केस दर्ज हुआ और दो दिन के बाद ही 17 तारीख को उसको गिरफतार कर लिया गया।

श्री अमर सिंहः प्लेस औफ अक्रैंस कहां हुआ और उसके बाद पुलिस ने पर्चा कब दर्ज किया ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास ज्यों ही कोई ऐप्लीके ान आती है, एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाती है,

देरी का सवाल नहीं है। ज्यों ही उनके पास ऐप्लीके ान आई, 15 तारीख को केस दर्ज हो गया। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि रेप कौन सी डेट को हुआ। यह डेट इस समय मेरे पास नहीं है अगर आप जानना चाहेंगे तो हम कल आपको बता देंगे।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हमारा प्र न यह था कि डाक्टर और पुलिस ने उसको एवायड किया। ऐसे मामलों में टाईम का बडा खयाल होता है, क्योंकि केस जूडीि ायरी में जाता है। इसमें टाईम का पूरा ध्यान होना चाहिए। 2–3 घण्टे बाद ही मैडीकल हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट में ऐसे फैसले हुए हैं कि अगर 5 घण्टे डिले हो गई तो फिर कानून में फर्क पड जाता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप भी काबिल और पढे लिखे हैं और भाई अमर सिंह भी वकील हैं। यह टाईम बाउंड प्रोग्राम कैसे हो सकता है ? यह प्रोग्राम रोज थोडे ही चलता है ? इत्तफाक से कोई वाकया हो जाए, उसके ऊपर ऐक ान लेने की बात है। (विघ्न) ऐक ान लेने में सरकार किसी तरह की डिले नहीं करती, कार्यवाही तो बाद में ही होगी। बाकायदा डाक्टरी मुआयना करवाया जाता है, फिर उसकी ऐप्लीके ान होती है कि इस लडकी के साथ कहां तक कौन सी बात हुई है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि दफा 376 के केस में डायरैक्ट मैडीकल नहीं

होता। पहले पुलिस रिपोर्ट लिखती है, फिर पुलिस उसको मैडीकल के लिए लेकर जाती है। एम0एल0ए0 की इन्टरफियरेंस से यह पर्चा दर्ज हुआ।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 15 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ और दो दिन के अन्दर अन्दर 17 तारीख को गिरफतारी हो गई। दूसरे, इन्होंने नीमड़ी गांव की लडकी के बारे में कहा। नीमडी गांव की औरत ने अपनी बच्ची को पहले कुंए में डाल दिया और फिर बाद में खुद कुंए में कूद कर आत्महत्या कर ली। इस बारे जहां तक पुलिस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से वह आत्महत्या का केस पाया गया है। इसके अलावा, और कोई ि ाकायत नहीं आई है। अगर कोई ि ाकायत होगी तो जांच करवा ली जाएगी।

श्री बंसी लालः आज से करीब 7–8 दिन पहले, यहां पर मुझे भी कुछ लोग मिले थे और बाद में वे आपके डी0जी0पी0 को भी मिले थे। उन्होंने कहा कि या तो हमें इन्साफ दो, वरना हम धरना देंगे।

चौधरी भजन लालः बंसी लाल जी, आपके पास चाहे उन्होंने कुछ भी लिख कर दिया हो, वे हमें दे दें और कल ही हम केस दर्ज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बात कही है, ऐसी बात नहीं है। वह बात आत्म हत्या की थी, मां बेटी ने

आत्महत्या की है। पहले तो उसने अपनी बेटी को कुंए में फैंक दिया और बाद में अपने आप छलांग लगा दी।

श्री धर्मपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या भी कोई राजी खु ी नहीं करता।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमारे पास किसी की ि ाकातय नहीं है। अब आप ि ाकायत कर रहे हैं तो कार्यवाही हो जाएगी। आप माननीय सदस्य हैं, हम आपके इतना कहने पर ही जांच करवाएंगे। साथ ही चौधरी बंसी लाल जी ने, हवलदार तारा चन्द के बारे में बडी चिन्ता व्यक्त की है कि उसके बारे में क्या किया गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि तारा चन्द के पुत्र राजे वर कुमार को रोजगार विभाग में क्लर्क भर्ती कर दिया गया है क्योंकि वह पुलिस विभाग में भर्ती नहीं होना चाहता था।

श्री बंसी लालः उसको कोई एवार्ड दिया है कि उसने इतनी बहादुरी का काम किया है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले इस बारे में नहीं पूछा था। उसके बारे में जो कुछ भी हुआ है वह हम इनको कल बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए, अगर कोई मारा जाता है तो उसको एवार्ड बगैरह देने के लिए हमने बाकायदा नार्म्ज बनाए हुए हैं।

श्री अमर सिंहः वह स्कूल मैनेजमैंट को हैंड ओवर करने के लिए सै ान जज ने फैसला दिया हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो हम कोर्ट के फैसले के अनुसार दे देंगे।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, अगर ये कोर्ट का फैसला ही इम्पलीमैंट कर दें तो वही काफी है।

चौधरी भजन लालः ठीक है, हम इम्पलीमैंट करा देंगे। इसके अलावा, इन्होंने हवलदार का जिक्र किया कि उसकी मृत्यु हमारे समय में हुई है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि उसकी मृत्यु हमारे समय में नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, कल ओम प्रका ा चौटाला ने भिवानी में क्या कहा भाायद इनका पता नहीं हें ये पता कर लें कि क्या कहा ?

श्री बंसी लालः उन्होंने जो भी कहा है, लेकिन आप दोनों तो एक ही हो।

चौधरी भजन लालः आप उनके साथ हैं या मैं उनके साथ हूं, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। (विघ्न) ठीक है, कल बता देंगें कि उन्होंने क्या कहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे समय में उस हवलदार की मौत नहीं हुई। हमारे समय में तो उसके लडकी की नौकरी लगी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इन्होंने ला एण्ड आर्डर के बारे में कहा। इसके बारे में तो गुप्ता जी बता चुके हैं। इसी तरह से राम रतन जी ने नहरों

के बारे में कहा। इसी तरह से नारनौल में अनाज मंडी की बात है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें कि ि ाडयूल्ड कास्टस का जो बैकलाग है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं इसी तरह से एच0सी0एस0 की भी ि ाडयूल्ड कास्टस के लोगों में से भर्ती होनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः ठीक है, यह भी अभी बता देंगे। इसके अलावा, राम बिलास भार्मा जी ने पुलिस के बारे में कहा कि पुलिस का मनोबल नीचा नहीं होना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने हमे ाा पुलिस का मनोबल ऊंचा रखा है। अगर पुलिस के खिलाफ कहीं पर कार्यवाही कर दी गयी है तो हम उसका पता लगायेंगे। इसी तरह से इन्होंने नगरपालिका के बारे में जिक्र किया कि यमुना नगर और रोहतक में यह हो रहा है, वह हो रहा है। यह बात तो ये भी जानते हैं कि यह प्रजातंत्र है, जिसका बहुमत होगा और जिसको लोग चाहेंगे, वही रहेंगा। अगर बहुमत नहीं होगा तो हटना ही पडेगा। सरकार कोई भी गलत काम नहीं करती जिससे आपकी पार्टी को कोई ि ाकायत हो। इसके अलावा, इन्होंने कहा कि यह गांव उस ब्लाक में कर दिया, उस तहसील में कर दिया, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम भी यही चाहते हैं कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट एक ही होना चाहिए। इसके लिए अब फैसला भी हो चुका है लेकिन फिर भी इनको कहीं पर

ऐसी ि ाकायत है तो हमें यह लिख कर दे दें, हम ठीक करा देंगे। (विघ्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी अभी फरमाया कि लोग जिसे चाहते हैं और जो बहुमत में है, वही रहेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके एम0एल0ए0 और मंत्री ही उनके काम को ठीक तरह से नहीं चलने दे रहे हैं। जैसे मैंने अम्बाला छावनी का जिक्र किया, अम्बाला सिटी का जिक्र किया, वहां की नगरपालिका में कांग्रेस के प्रधान हैं और हमारी पार्टी के उप प्रधान हैं। वहां पर भी ये लोग उसकी प्रोसिडिंग को चलने नहीं दे रहे हैं। स्पीकर साहब, हमारी आपसे गुजारि ा है कि जिन दो तरह की इंक्वायरीज के बारे में मैंने कहा है उनमें से एक तरह की इंक्वायरी करवाने के लिए आप सरकार पर दबाव डालें और पब्लिक इंट्रस्ट में इनको डायरैक ान दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके।

वाक आउट

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते ? यह ज्यादती हुई है, यह जनविरोधी हुआ है। सरकार कोई तसल्लीबख्भा जवाब नहीं दे पाई, इसलिए मैं एज ऐ प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय माननीय सदस्य श्री राम बिलास भार्मा सदन से वाक आउट कर गए)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, जुडि ायल इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही, इसलिए एज ऐ प्रोटैस्ट मैं भी वाक आउट करती हूं।

(इस समय माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रावती सदन से वाक आउट कर गई।)

वक्तव्य–

मुख्य मंत्री द्वारा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः भार्मा जी, आपने वाक आउट करना ही था, ताकि आपका नाम अखबारों में आ जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन बातें और जोड दी और साथ में निसिंग कांड का भी जिक्र कर दिया। (विघ्न) वह आदमी भाराब पिये हुए था। (विघ्न) मैंने जो कहा था वह पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही कहा होगा। आप इस बारे में स्पीकर साहब, से अलग से पूछ लेना, या जो जानकार लोग हैं, उनसे पूछ लेना। वहां पर उस दिन क्या हालत थी ? कितने रूपये की भाराब उस दिन ठेके से बिकी ? मरने वाले आदमी ने भाराब पी रखी थी स्पीकर साहब, इन लोगों ने उनको बहकाने की बहुत कोि ा ा की लेकिन वे बेचारे समझ गए कि ये लोग उनको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। सारी यूनियन हमारे पास आई और हमसे बातचीत कर के कहा कि

उनकी कुछ मदद कीजिए। हमने उनकी मदद भी की थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, निसिंग वालों की कोई ि ाकायत नहीं। दूसरे इनहोंने रिलैक्से ान का जिक्र किया। रिलैक्से ान तो हालत को देख कर ही दी जाती है और अगर ऐसी कोई बात होगी तो रिलैक्से ान के बारे में भी विचार किया जा सकता है। जेसे उग्रवादियों से लडते हुए किसी का बाप भाहीद हो गया तो उसके बेटे या बेटी को नौकरी देना एक अलग बात है, इस किस्म के हालात में नौकरी देने की बात अलग हालात की बात है। कहां तक किस का क्या मामला है, कोई बहादुरी से भाहीद हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, सारी बात को देख कर ही रिलैक्से ान दी जाती है। (विघ्न) यह देखना पडेगा कि रिलैक्से ान किन किन हालात में दी जा सकती है और अगर दी जा सकती होगी तो जरूर देंगे। (विघ्न) अगर कोई आदमी किसी के घर डकैती करने जाए और कोई घरवाला आदमी उसको गोली मार दे तो क्या उसको भी दे देंगे ? (विघ्न) यह देखने के बाद कि यह बात कहां तक ठीक है, रिलैक्से ान देंगे। स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह और चौधरी सम्पत सिंह जी के पास सिंचाई का महकमा भी रहा है, इसलिए इस बारे में भाायद ये कुछ जानकारी भी रखते होंगे। स्पीकर साहब, मु ि कल यह है हमारे इधर के लोग उधर के लोगों को समझाने की बहुत कोि ा ा करते हैं लेकिन इनके दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं घुसती ? ये पढे लिखे प्रोफैसर रहे हैं, आदमी को कुछ तो समझ आनी चाहिए। स्पीकर साहब, ये भली भांति जानते

हैं कि नरवाना ब्रांच मेन भाखडा में से निकलती है जो पंजाब से गुजरती है। पंजाब के एरियामें 32 जगह कट कर दिया था बडी मुि कल से उनको भरवाया गया। (विघ्न) हम मान लेते हैं कि एस0वाई0एल0 भी चौधरी देवी लाल जी ने बनवाई, हम कमजोर हैं आप बहुत बहादुर हो। अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले मुख्य मंत्री था, हमने ही इसको ठीक करवाया था और 2800 से 3400–3500 तक ले गए थे। यह बात भी ठीक है कि यह 4000 तक जा सकती है इसमें मुि कल यह है कि इसको करने के लिए हमने पंजाब वालों को लिखा भी और उनको पैसा भी दिया ताकि हमारी नहर की कैपेसिटी को वे बढा दें लेकिन उन्होंने काम भाुरू नहीं किया, क्यों। इसके लिए नहर 3 महीने बंद करनी पडती है और पंजाब वाले 3 महीने के लिए बंद करने को तैयार नहीं हैं। सिरसा और हिसार में कोई फर्क नहीं है। राजस्थान कैनाल से लिंक कैनाल बनी हुई है उसे बने हुए 2 साल हो गये हैं और पंजाब की सरकार से 15 दिन बंद करवा कर वह नहर जोडी गई थी। बडी मुि कल से पंजाब वाले उसके लिए तैयार हुए थे। भारत सरकार ने इन्टरवीन किया तब कहीं जाकर वह जुडी। वे नहर बंद नहीं करते। कोईऐसा कानून नहीं है कि धक्के से उसे बंद करवाया जा सके, 15 दिन पहले नहर बंद करनी पडी थी, तब कहीं जाकर लिंक नहर जुड पाई थी। इसके लिए हम फिर कोि ा ा करेंगे कि नहर की डी सिल्टिंग हो जाए, बर्म्ज ऊंचे हो जाएं और जितना पानी ले सकते हैं, लें, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके लेकिन असली हल तो तभी होगा जब एस0वाई0एल0

की कैनाल बन जाएगी और उसका पानी हरियाणा में आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया है।

स्थगन प्रस्ताव को नियम 84 के अधीन प्रस्ताव में परिर्वतन करना– राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति संबंधी

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं। Hon'ble Members, I have received one adjournment motion from Sh. Om Parkash Beri, regarding the situtation arisen in the State on account of the drought. Besides this, one more adjournment motion has also been received from Sh. Sampat Singh and 14 other M.L.As on the same subject. इस बारे में मुख्य मंत्री आप कुछ कहना चाहते हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सूखे के बारे में और बाढ के बारे में कल साढे तीन घंटे बहस हो चुकी है और एक घंटा मैंने जवाब दिया था। इस बारे में डिसक ान करने की कोई आव यकता नहीं है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कल डिसक ान हो चुकी है। कल तो फ्लड के बारे में डिसक ान हुई थी और अब हम सूखे के बारे में कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फ्लड के बाद सूखा आया है। जैसे आप खुद मानते हैं काम रोको प्रस्ताव के बारे में आपने कहा कि फलड की बात पुरानी हो गई है। स्पीकर साहब, अगली सूखे की बात है।

पानी के लिए जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और औरतें घडें तोड रही हैं।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हाउस का काम पडा हुआ है पहले उसे खत्म कर लें और डेढ बजे के बाद फिर इस बारे में बात कर लेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही ओर यह बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में भी आयी थी। उसमें इनहोंने माना था कि पहले दिन फलड पर डिस्क ान कर लेंगे और बाद में सूखे पर कर लेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है हम आज के अजैंन्डे से फारिग हो कर इस पर बहस कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो भी उचित टाईम है वह तो हमें मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि आधा घण्टा और एक घण्टा प्लस करवा लेंगे, हम गुणा करने को नहीं कहेंगे। कल पीरचन्द जी ने गुणा करने को कहा था परन्तु हम तो प्लस करने को कह रहे हैं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सब मि ान है। सूखे के बारे में कल भी बात हुई थी कि आज डिसक ान कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपकी भी इजाजत होनी चाहिए और मुख्य मंत्री जी को भी मान लेना चाहिए कि पहले डिस्क ान हो। इस तरह हाउस का काम भी जो जाएगा और पहले डिस्क ान भी होनी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावतीः सर, कल भी इस पर काल अटैं ान थी और आज यह स्थान प्रस्ताव सूखे पर है। अगर ये सब इकटठी कर देंगे तो हम भी इस पर बोल सकेंगे। अगर नहीं तो मेरी भी एक काल अटैन ान है।

श्री अध्यक्षः ठीक है जी।

श्री लहरी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक काल अटैं ान मो ान है। गन्ने की फसल पर जो पैनल्टी डाल दी है, उसके बारे में है।

श्री अध्यक्षः यह अभी अंउर कंसीडरे ान है। Please take your seat.

Hon'ble members, keeping in view the importance of the subject and to save the time of the House, I have converted both these adjournment motions into motions undre Rule 84 and clubhed them for discussion. Hon'ble members, this motion will be discussed today after the business entered on the order paper is completed. (Interruptions).

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। कि इस बिजनैस के निकालने के बाद आप डाउट पर डिसक ान के लिए कितना टाईम रखेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कल सारी बातें सभी सदस्यों ने कह दी थी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, कल तो बाढ पर चर्चा हुई थी। लेकिन आज सूखे पर डिसक ान के लिए टाईम फिक्स होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बंसीलाल जी, प्रजैन्ट बिजनैस पूरा होने के बाद आपको टाईम बता देंगे।

वर्श 1987–88 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Hon'ble Members now discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1987-88 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, all the Excess Demands over Grants and appropriations on the order paper (Nos. 3, 4, 6, 9, 10, 15, 18 and 22 to 24) will be deemed to have been read and moved to gether. The Hon'ble Members can discuss any Demand but they are requested to indicate the Demand Number on which they wish to raise discussion while speaking.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2886721 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of HOME.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13052392 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of REVENUE.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97316090 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of FINANCE.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 70738312 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of EDUCATION.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 17732133 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of MEDICAL & PUBLIC HEALTH.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 101101449 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of IRRIGATION.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6366371 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of ANIMAL HUSBANDRY.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 54947 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of COOPERATION.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10024426 be made to regularise the charges already incurred in excess

of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of TRANSPORT.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 50795 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of TOURISM.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I shall put various Demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2886721 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of HOME.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 13052392 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of REVENUE.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 97316090 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of FINANCE.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 70738312 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of EDUCATION.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 17732133 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of MEDICAL & PUBLIC HEALTH.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 101101449 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of IRRIGATION.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6366371 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of ANIMAL HUSBANDRY.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 54947 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of COOPERATION.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10024426 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of TRANSPORT.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 50795 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1987-88 in respect of TOURISM.

The motion was carried.

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं 1987–88 की डिमांड पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह जी, अब तो डिमांडज पास हो चुकी हैं। यह तो पुरानी डिमांड हैं और पी0ए0सी0 ने भी इसको आलरेडी ऐप्रूव कर दिया है, जिसमें सभी पार्टियों के मैम्बर्ज होते हैं, it is all over now. Please take your seat.

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Sarvshri Om Parkash

Beri, Sampat Singh, Om Parkash, Dhir Pal Singh, Krishan Lal, Jaswinder Singh, Mani Ram Rupawas, Jai Pal Singh, Zile Singh, Mohan Lal Pipal, Suraj Bhan Kajal, Ram Kumar Katwal, Amar Singh, Dhanday, Balwant Singh, Ramesh Kumar and Satbir Singh Kadian, M.L.As, which is as under :-

"That the situation arisen in the State on account of drought, be discussed."

Sh. Om Parkash Beri: Sir, I beg to move-

"That the situation arisen in the State on account of drought, be discussed."

Mr. Speaker: Motion moved-

"That the situation arisen in the State on account of drought, be discussed."

चौधरी ओम प्रका ा बेरी (बेरी): अध्यक्ष महोदय, हरियाण के बहुत बडे हिस्से में जिसमें वि ोश रूप से महेन्द्रगढ, रिवाडी, रोहतक, भिवानी, गुडगांव, फरीदाबाद और हांसी सब डिवीजन का हिस्सा आता है, सूखे की गंभीर समस्या बनी हुई है। इसका एक कारण तो मानसून की कमी है और दूसरा सरकार की लापरवाही की वजह से है। उसका एक कारण यह भी है कि सिंचाई के लिए जितना नहरी पानी इन इलाकों को मिलना चाहिए। वह नहीं मिल रहा, उससे सरकार किसानों को वंचित करती आ रही है, यह एक डैफिनिट रिकार्ड की बात है। यमुना नदी का पानी सिरसा नहर में उस वक्त डाला जाता है, जब फलड

जैसी सिचुए ान हो जाती है। जिन इलाकों में पानी की कमी है और सूखे की सी स्थिति है उनको छोड कर जहां बाढ की स्थिति बनी हुई है, वहां पानी दिया जा रहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इनको इस तरह की गलत बात कह कर हाउस को गुमराह नहीं करना चाहिए। यमुना का पानी सिरसा ब्रांच में डाल रहे हैं, ऐसी बातों से हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अगर यह बात सच होगी तो मैं आज ही इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं सरकार को लास्ट सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने बडे वायदे भी किए हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इन्होंने जो वायदे किए हैं, उनके बारे में कुछ होना ही नहीं है, इसलिए एक वायदा और कर लें कि जिससे सारा क्ले ा ही खत्म हो जाएगा कि ये राम जी को फोन कर लें कि बारि ा कर दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने टेलीफोन परमात्मा को किया था और कहा था कि अब इस बाढ को बन्द करो और उन्होंने टेलीफोन सुन भी लिया था, लेकि अब उनका टेलीफोन खराब हो रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं भाब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे। अब आप जवाब सुनें। आपने सुनना न हो तो दूसरी बात है। चौ0 अमर सिंह जी, आप बैठिए। कल आपको टाइम देंगे। कल और परसों दो दिन अभी और बहस होनी है।

वित्त मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आपके आदे ा के अनुसार 2 मार्च को मैंने सदन में 1993–94 का बजट पे ा किया। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी आपको कह दिया कि आज टाइम नहीं मिलेगा। चौधरी अमर सिंह जी कृपया बैठ जाईए। इंसिस्ट न करें। (ाोर)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने ट्रेजरी बैंचिज के भाईयों ने जहां बजट की सराहना की वहां ..... (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादयान साहब आपको और आपकी पार्टी को कम्परेटिवली सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है। अब तक जो मैंबर साहिबान बजट पर बोले हैं उनमें श्री सतबीर सिंह कादयान 64 मिनट, श्रीमती चन्द्रावती 27 मिनट, डा0 राम प्रका ा 16 मिनट, श्री अमर सिंह 49 मिनट, श्री लहरी सिंह 25 मिनट, श्री कर्ण सिंह दलाल 27 मिनट, श्री सूरजभान 23 मिनट, श्री कृश्ण लाल 21 मिनट, श्री किताब सिंह मलिक 29 मिनट, श्री मनीराम केहरवाला विद इंट्र ांज 51 मिनट, श्री राम बिलास 67 मिनट हैं। अब आप

खुद ही देखें कि इसमें अपोजी ान के ज्यादा मैंबर साहिबान बोले हैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया है और ट्रेजरी बैंचिज के माननीय सदस्यों ने बजट की सराहना की है। अध्यक्ष महोदय, बजट से पहले इस सदन में गवर्नर महोदय के अभिभाशण पर चर्चा हुई। विरोधी पक्ष के भाईयों ने गवर्नर महोदय के अभिभाशण पर जो कुछ कहा, वही बातें इनहोंने इस बजट पर कहीं हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी आप अपने मैम्बर्ज को डिसिप्लिन में रखें। ऐसी कोई बात नहीं सुनी जायेगी।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जो बात आप कर रहे हैं वही होगी। ये लोग आपसे रिकवैस्ट कर रहे हैं कि आज हमारी पार्टी का मैम्बर नहीं बोला।

श्री दरियाओं सिंह रजोराः आप हाउस को एक्सटैंड कर दें। मैं तो बोला ही नहीं हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आज टाईम ऐक्सटैंड नहीं होगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने वर्श 1993–94 के बजट पर बोलते हुए कहा

कि यह बजट नीरस है और दि ाहीन है। इन सदस्यों ने कहा कि यह बजट दि ाहीन है इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है और हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने अपने मन के गुबार निकालने के लिए और अपने हल्के के लोगों को खु ा करने के लिए कुछ बातें यहां पर रखी हैं। (ाोर एवं व्यवधान) । स्पीकर साहब, मैं एक बात आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। मैं फाइनैंस के मामले में कोई बहंत बडा अर्थ ाास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। इन नब्बे के हाउस में आप पहले भी आते रहे हैं और अब की बारे भी बन कर आए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आप हाउस का समय बढा दीजिए और हरेक मैम्बर को पांच पांच मिनट दे दीजिए। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठ जाएं।

श्री सतबीर सिंह कादियानः हमारा कहना तो यह है कि आप थोडा सा टाईम बढा दें जिससे कि सभी मैम्बर्ज अपनी समस्याएं सदन में रख सकें। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं इसलिए आप लोग बैठ जाएं। अब किसी और को टाईम नहीं मिलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि यह हाउस 90 का है। इस हाउस में दो मुख्यमंत्री इस समय ऐसे हैं जो दो तीन बार पहले भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं और कई ऐसे सदस्य भी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं और कई ऐसे सदस्य भी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह जो उठकर गए हैं वे भी काफी सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी जो चले गए हैं वे भी बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। स्पीकर साहब मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस 90 के हाउस में मुख्य मंत्री तो दूसरी बार और तीसर बार बनकर आए हैं और कई विधायक जो पहले मंत्री थी वे भी दूसरी और तीसरी बार बन कर आए हैं लेकिन हरियाणा में जो फाइनैंस मिनिस्टर रहा है, वह दूसरी बार बनकर नहीं आया। चौधरी बंसी लाल जब मुख्य मंत्री थी तो इन्हौंने बहुत सारे महकमे सम्भाले हुए थे और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल के पास भी काफी विभाग रहे हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह बहुत सीनियर मंत्री रहे और वकील भी रहे यह सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर चले। उन्होंने महकमें छांटे पावर एण्ड इरीगे ान, होम डिपार्टमैंट और ऐजुके ान लेकिन फाइनैंस के वे बिल्कुल नजदीक नहीं लगे। इसी तरह से चौधरी सम्पत सिंह जी ने जितने इम्पोर्टैंट विभाग थे, होम, पावर एण्ड इरीगे ान, वे संभाले। जिन विभागों पर बजट का 50 प्रति ात खर्चा होता है वे विभाग चौधरी सम्पत सिंह जी ने अपने पास रखे लेकिन फाइनैंस का विभाग किसी ने भी अपने पास नहीं रखा क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जिसको संभालने में बहुत

बडी कठिनाई आती है और जिससे हमारे विरोधी पक्ष के भाईयों ने हर बार नाराजगी जाहिर करनी ही है। मैं तो यह सब कुछ प्रैक्टीकल बता रहा हूं कि फाईनैंस मिनिस्टर से तो सभी नाराज रहते हैं। सारे अधिकारी नाराज, सभी कर्मचारी नाराज, और जनता भी नाराज फिर जनता को ये लोग खु ा करने के लिये कहते हैं कि फलां फलां स्कीमज हमने मनवा ली हैं। अब की बार तो हमने यह स्कीमें मनवा ली हैं लेकिन फाइनैंस मिनिस्टर बिल्कुल नहीं मानते। काम बन जाए तो साथियों को खु ा कर लो और अगर न बने तो लोगों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की कोई नाराजगी हो तो वह फाइनैंस मिनिस्टर के जिम्मे लगा दो। ये तो मेरे इन विरोधी पक्ष के भाईयों का कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि इन्होंने यहां पर बोलते हुए जीभ की बात कही। इनको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो जीभ है, यह बहुत बडी कीमती चीज है। इसी जीभ के कारण ही सम्पत सिंह जी ने एक बात हाउस में कही थी कि मेरी गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। लेकिन आपको पता ही है कि वह गर्दन झुकी भी ओर उन्होंने हाउस के अंदर माफी भी मांगी। (ाोर) यह फैक्टस की बात है सबके सामने की बात है। मैं फैक्टस पर आधारित बातें हाउस में कह रहा हूं, किसी पर ऐलीगे ान नहीं लगा रहा। न ही मैं किसी के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरफीरैंस ही करना चाहता हूं। मैं तो फैक्टस बता रहा था। (ाोर)

श्री अध्यक्षः मांगे राम जी, यह तो चिढाने वाली बातें हैं जिनका सबको पता है कि उसको बार बार कुरेदने की कोि ा ा न की जाए। (ाोर)

श्री मांगेराम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फाइनैंस विभाग ऐसा विभाग है जिसके पास स्टेट के सारे रिसोर्सिज होते हैं और उन्हीं रिसोर्सिज के अनुसार वह हर विभाग को फण्डज ऐलोकेट करता है और उन फण्डज को विभाग अपने लैवल पर अलग अलग खर्चा करता है। फाइनैंस विभाग के पास कोई जादू की छडी नहीं है कि चाहे कोई डिपार्टमैंट जितना पैसा मांगे, वह उतना ही उसे दे दे। कोई भी मांग जो एम0एल0एज0 उठाएं वह फाइनैंस डिपार्टमैंट दे दे और बजट में प्रावधान कर दे, यह बात फाइनैंस विभाग के बस की नहीं है। जो कुछ ये लोग बोलते हैं कहते हैं मैं उनकी हर बात नोट करता हूं और उनका सही सही उत्तर भी देता हूं। मैं इनको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि स्टेट के अपने निि चत रिसोर्सिज होते हं लेकिन मेरे जितने भी बैठने वाले माननीय व आदरणीय तजुर्बेकार सदस्य हैं, उनमें से किसी ने भी यहां पर यह नहीं कहा कि स्टेट के अंदर विकास के कार्यों के लिये फलां फलां रिसोर्सिज पैदा किये जाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मांग की कि बिजली के रेट न बढाए जाएं, सेल्ज टैक्स और मार्किट फीस नहीं लगनी चाहिए, वह खत्म कर दी जाए। माननीय सदस्यों ने कहा कि भाराब के ठेके नहीं बिकने चाहिए, दवाईयों मुफ्त मिलनी चाहिए।

और ि ाक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए तथा खाद तथा बीज पर भारी सबसिडी रखनी चाहिए। हर गांव में स्कूल अपग्रेड होने चाहिएं कोई स्कूल बगैर टीचर के नहीं रहन चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी होनी चाहिएं, सडकें बढिया बढिया होनी चाहिए। हस्पताल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। पीने का पानी इतना चाहिए कि भााम तक टूटियां चलती रहें और कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। किसान के खेत में जितना पानी चाहिए उतना देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये जितने काम लोगौं के हित के हैं, इनके लिए साधन जुटाने पडेंगे। सभी कामों के लिए आर्थिक व्यवस्था करनी पडेगी। अगर सरकार सभी माननीय सदस्यों की एक भी मांग पूरी मान लें जैसे ि ाक्षा के संबंध में कोई मांग है, तो अगर उस पर वर्श 1993–94 का पूरा बजट भी खर्च कर दे तो भी वह मांग सारी स्टेट में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए माननीय सदस्यों को सोच समझ कर ही सुझाव देने चाहिए। सभी साथी सरकार की नुक्ताचीनी अकेले चौधरी भजन लाल की ही नहीं है और न ही फाइनैंस मिनिस्टर की है। लोगों ने यहां पर 90 प्रतिनिधि चुन कर भेजे हैं, इन सबकी बराबर जिम्मेदारी है। बजट पर तो लोगौं की भलाई के बारे में बोला जाता है, इसीलिए लोगों ने आपको यहां पर चुन कर भेजा है। आप अपने हल्के के लोगों की और प्रदे ा के लोगौं की मांग के लिए सुझाव देते लेकिन इन्होंने कोई अच्छा सुझाव नहीं दिया।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। फायनैंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने कोई सुझाव नहीं दिए। यहां पर बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। खुद फाईनैंस मिनिस्टर ने सुझाव दिया था और अपोजी ान के मैंबरों ने उसकी ताइद की थी कि कैबिनेट के साईज को कम कर लो तो खजाने पर अपने आप भार कम पडेगा। (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कोई खास वजह हो या किसी ने कोई खास बात कह दी हो तब तो माननीय सदस्यों को बीच में उठ कर प्वायंट आफ आर्डर करना चाहिए लेकिन अब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही ये तो अपना जवाब दे रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके माननीय सदस्य बीच में टोकने की कृपा न करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हमनें जो 1993–94 का बजट पे ा किया है इस बारे में मेरे साथी कादयान साहब ने कहा कि इस बजट का प्लान बहुत कम है इन्होंने इस बारे में कोई आंकडे तो बताए नहीं, वैसे ही नुक्ताचीनी के नाते कह दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्लान है उसके अनुसार हमने पिछले साल 820 करोड रूपए खर्च किए जबकि इस साल यानि 1993–94 में हम 910 करोड रूपए खर्च करेंगे यानि 90 करोड रूपए ज्यादा खर्च करेंगे। मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों के समय में प्लान 529 करोड रूपए के लगभग था। हमने 15 परसैंट के करीब बढौतरी की है। हमारे पास प्रदे ा के विकास के लिए जितने

रिसोर्सिज थे उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा करके खर्च किए हैं। पिछले साल 1991–92 के बजट में 87.34 करोड रूपए का घाटा था। हमने उस घाटे को अपने खर्च कम करके रिडयूस किया है और यह बजट ईयर 7.16 करोड रूपऐ के घाटे में समाप्त हुआ। पिछले साल 119.84 करोए का घाटा था लेकिन हमने अपने खर्चे कम करके पिछले बजट ईयर को 79.87 करोड रूपऐ के घाटे के साथ समाप्त किया और जो 40 करोड रूपया हमने बचाया, वह हरियाणा प्रदे ा के लोगों के विकास के लिए खर्च किया। इस तरह हमने अपने खर्चे में कमी की है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय हमारे माननीय सदस्य सतबीर सिंह कादियान ने कहा कि बिजली में लाईन लौसिज 39 परसैंट हो गए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके राज में वर्श 1990–91 में बिजली में 26.4 परसैंट लाइन लौसिज थे, 1991–92 में 24.2 परसैंट थे, 1992–93 में 23.2 परसैंट रह गए और 1993–94 में 22.5 परसैंट रह जाएंगे। आपने कैसे कह दिया कि 39 परसैंट बिजली में लाइन लौसिज हैं ? अध्यक्ष महोदय बिजली तैयार करने का जो खर्चा है वह 1 रूपया 25 पैसे या 30 पैसे प्रति यूनिट है। इन्होंने एक बात यह कही कि किसानों के साथ बहुत भारी अन्याय किया गया है। सरकार ने बिजली का रेट 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया, सारे दे ा में बिजली का इतना रेट कहीं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सारे दे ा में हरियाणा प्रदे ा एक ऐसा प्रदे ा है जो किसानों को एग्रीकल्चर सैक्टर में 59.2 परसैंट यानि 60 परसैंट बिजली दे रहा है जिस पर 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से नुक्सान होने की

वजह से हर साल बिजली बोर्ड को 300 करोड रूपए का नुकसान हो जाता है। दूसरे किसी भी प्रदे ा में एग्रीकल्चर सैक्टर में इतनी बिजली नहीं दी जा रही। मेरे विरोधी पक्ष के भाई इस बात को ले कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि आप बिजली के बिल न भरो। अगर किसान बिजली के बिल नहीं भरेंगे तो आज बिजली की जो मांग बढ रही है, यह अगले पांच साल में भी पूरी नहीं होगी। आज बिजली जिस रेट के हिसाब से मिल रही है वह दो रूपए यूनिट के हिसाब से भी नहीं मिल सकेगी और बिजली के नए प्रोजेक्ट नहीं लगेंगें। मैं यह कहूंगा कि इन भाईयें को चाहिए कि वे प्रदे ा के लोगौं को, किसानों को सही स्थिति की जानकारी दें, गुमराह न करें। मैं फिर कहूंगा कि यदि ये प्रदे ा के सच्चे हितैशी हैं तो इनको सही बात कहनी चाहिए। अरग ये गलत जानकारी दैंगे तो प्रदे ा का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए इनको लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कादियान जी ने उद्योग कुंज के बारे में कहा है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कीम पर चार जिलों में काम हो रहा है। सोनीपत, रोहतक, गुडगांव में तो साईट ले ली गई जबकि हिसार जिले में साईट की तला ा की जा रही है। ज्योंही जमीन मिल जायेगी हिसार में भी इस स्कीम पर काम भुरू कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कादियान जी ने यह कही कि पानीपत की एच0एफ0सी0 में किसी अधिकारी/कर्मचारी ने 3 लाख

रूपए का गबन किया है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने यह गबन किया था उनको सस्पैंड कर दिया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कानून के अनुसार उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाएगी, चाहे कोई कितना ही बडा अधिकारी क्यों न हो।

अध्यक्ष महोदय एक बात चन्द्रावती जी ने जे0पी0 गुप्ता जी के बारे में कही। इस बात की इंकवायरी हुई है। उन दिनों गुन्ता जी छुटटी पर थे पूरी इंकवायरी हुई। आपको भी पता है कि जो इंकवायरी में दोशी पाया जाता है उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जाती है और उसको परमोट नहीं किया जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी दोशी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कादियान साहब ने यह कही कि पानीपत के थर्मल प्लांट में प्रदूशण बहुत अधिक है। यह बात सही है इसे मैं मानता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रदूशण को कम करने के लिए काफी पग सरकार उठा रही है। इस पर भारी खर्च होने की संभावना है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सजग है, जल्दी ही इसको कोई न कोई समाधान ढूंढ लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह इन्होंने यह कहा कि स्टेट वाटर एंड एयर पोल्यू ान बोर्ड के जो पहले चेयरमैन मि0 आर0ए0 गोयल थे, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह एस0पी0 ग्रोवर को चेयरमैन लगा दिया गया। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि सैंट्रल एन्वायरमैंट बोर्ड की सलाह पर ही हरियाणा स्टेट पोल्यू ान बोर्ड को खत्म किया गया है और दोबारा गठन किया गया है। चेयरमैन मि0 आर0 ए0 गोंचल ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट की है। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया है। अब श्री आर0ए0गोयल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पे ान याचिका डाली है। यह मामला अब सब जूडिस है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता।

श्री सतबीर सिंह कादियानः पहले बोर्ड को तोड दिया, फिर बना दिया और आर0ए0 गोयल से कम क्वालिफिके ान के आदमी को चेयरमैंन लगा दिया गया।

श्री अध्यक्षः गवर्नमैंट की अपनी कम्पीटैंसी है, जिसको वह चाहे, चेयरमैन लगाये।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने पानी के बारे में चर्चा की और यह भी कहा कि एस0वाई0एल0 पानी की नहर की तरफ सरकार का वि ोश ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं हाउस में एक बात कहना चाहता हूं ..... (विघ्न)

एस0वाई0एल0 पानी के बारे में हर विधायक और सरकार बहुत ही चिन्तित हैं कोई भी व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, हर विधायक यह मांग करता है कि जिन माईनरों के फाउन्डे ान स्टोन रखे गये हैं उनका काम जल्दी पूरा किया जाए और यह कहा गया है कि माईनरज के लिए पैसा नहीं रखा गया हैं अध्यक्ष महोदय, अगर पानी नहीं आया तो नई माईनरज बना कर क्या करेंगे ? माईनरज बन जाएं और उनमें पानी न आए तो उनको कोई फायदा नहीं है। टेल पर पानी पहुंचाने के लिए एक करोड रूपया खर्च किया गया। हरियाणा के 75–80 प्रति ात लोग यह मानते हैं कि टेल पर पानी पहुंच रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में नहीं आएगा, तब तक माईनरज पर ज्यादा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। एस0वाई0एल0 के बारे में विरोधी पक्ष के भाई चाहे कुछ भी कहें, सरदार बेअन्त सिंह की पंजाब की जनता को खु ा करने के लिए चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन हरियाणा की यह वर्तमान सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा के किसानों को देगी, जिससे किसान के खेत को पानी मिलेगा, हरियाणा की एक एक एकड जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय वित्त मंत्री जी फरमा रहे हैं कि यह सरकार एस0वाई0एल0 का पानी लाकर हरियाणा को देगी। बजट

में इसके लिए इन्होंने कोई खास पैसे का प्रावधान नहीं रखा है। यह एस0वाई0एल0 का पानी कब और कैसे लाएंगे, यह भी जरा बताने की कृपा करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने अभी 18 महीने का अर्सा ही हुआ है। 4 साल इनकी सरकार रही जिसमें भार्मा जी खुद मंत्री रहे और बाद में मंत्रिमंडल से निकाल दिए गए थे। (विघ्न) अमर सिंह जी भी कह रहे थे कि चौधरी बंसी लाल जी ला सके और नही यह लोग ला सके। हालांकि हर कोई इस पानी को हरियाणा में लाना चाहता है। लेकिन केवल चाहने से ही तो कोई काम नहीं हो जाता है। एस0वाई0एल0 का पानी हरियाणा में लाना केवल हमारे हथ की ही बात नहीं है, आज हम ही चिन्तित नहीं हैं केन्द्रीय सरकार भी चिन्ि'तत है। पंजाब में उग्रवाद हावी होने के कारण जब भी इस नहर को बनाने का काम भ्ाुय होता था तो उग्रवादियों ने कभी इंजीनियरों को मार दिया, कभी वर्करज को मार दिया कभी लेबर को मार दिया और भारत सरकार जो भी फैसला करती थी वह सिरे नहीं चढ पाता था। लेकिन अब दे ा के प्रधानमंत्री, इरीगे ान मंत्री और हरियाणा सरकार इस बारे में कई मीटिंगे कर चुके हैं। इस काम में कुछ टाईम तो लगैगा ही एक दो दिन में यह काम होने वाला नहीं है। मुझे पूरा वि वास है कि हरियाणा की जनता ने जिस वि वास के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, यह सरकार अपने कार्यकाल में ही हरियाणा की

जनता को एस0वाई0एल0 का पानी उपलब्ध करवाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथियों से यह कहना चाहूंगा कि अभी वे माईनरज के लिए ज्यादा पैसे की तरफ ध्यान न दें। जहां तक एस0वाई0एल0 के लिए 20 करोड रूपये का ताल्लुक है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही इस बारे में कोई फैसला हो जाएगा, नहर खुदनी भाुरू हो जाएगी हम सप्लीमैंटरी बजट मंजूर करवा सकते हैं और इस सप्लीमैंटरी डिमांड के लिए कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। 20 करोड रूपया हमने इसलिए रखा है कि कभी भी एमरजैंसी में एस0वाई0एल0 का काम भाुरू करना पड सकता है तो पैसा कम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, हमैं चाहे कितना ही पैसा क्यों न रखना पडे हम एस0वाई0एल0 का काम करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, यह पैसा तो सैंटर से आता है ?

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है गुप्ता जी अभी जिक्र कर रहे थे कि माईनर्ज तब खुदवायेंगे जब एस0वाई0एल0 का पानी आएगा गुडगांव में एस0वाई0एल0 का पानी नहीं पडेगा तो क्या वहों पर अटवाल माईनर को खुदवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्षः यह क्वे चन आवर नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अभी रामबिलास भार्मा जी कह रहे थे कि बजट में एस0वाई0एल0 के लिए पैसा नहीं रखा है। हम यह कहते हैं कि जब भी एस0वाई0एल0 का काम भ्रारू होगा तो उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी और न ही हम आने देंगे।।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ये इररेलवेन्ट बात कर रहे हैं कि पैसा हम लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह पैसा तो पंजाब गवर्नमैंट ने खर्च करना है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि पैसा इन्होंने लगाना है। इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाना है लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि बेअन्त सिंह कुछ भी कहें। .....

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी यह बात तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही क्लीयर कर दी है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, नहर को बनाना तो पंजाब सरकार के हाथ में है। साथ ही पंजाब सरकार कह रही है कि वे पानी के ई ाुज को रीओपन करके फिर काम भ्रारू करेंगे। तो मुख्य मंत्री जी इस बारे मं हाउस को ऐ योर करें कि इसका निर्माण बी0आर0ओ0 करेगी।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात हाउस मं बार बार आई है और केन्द्रीय सरकार भी इस बारे में चितिंत है। मैं हाऊस को ऐ योर करता हूं कि बी0आर0ओ0 ही इस नहर को

बनाएगी। जहां तक पैसे का सवाल है इस बारे में विरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि पैसा भारत सरकार से आता है। तो इन्हें याद होगा जब चौधरी देवी लाल जी हरियाणा स्टेट के मुख्य मंत्री थी तो उस वक्त दो करोड रूपया पंजाब सरकार को दिया गया था। लेकिन जब बाद में हम आए तो हमने यह फैसला किया कि भारत सरकार ही एस0वाई0एल0 के लिए पैसा देगी और इसको सैंट्रल गवर्नमैंट ही कम्पलीट करवाएगी। यह फैसला हमारा है इनका नहीं है और इसको भारत सरकार ही पूरा करेगी।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि आपने कितना पैसा रखा हुआ है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 495 लग चुका है और यह पहले का है।

श्री अमर सिंहः यह तो चौ0 बंसी लाल जी के टाईम का है।

श्री अध्यक्षः लेकिन बाद में 150 करोड रूपए और भी दिए थे।

चौ0 भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस नहर को हम कम्पलीट करवाने की जल्दी से जल्दी कोि ा ा करेंगे।

श्री अध्यक्षः हरियाणा का जो पैसा इस पर खर्च हुआ था, उस समय श्री राजीव गांधी ने भी यह कहा था कि यह पैसा

हरियाणा को वापिस दे दिया जाएगा। इसलिए आप यह बता दें कि यह पैसा कौन सी सरकार को मिला है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह पैसा नहीं आया है। गलत बात कहने में कोई फायदा नहीं है लेकिन उसके बाद टोटल पैसा भारत सरकार ने इस पर लगाया है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने ऐजुके ान की तरफ ध्यान दिलाया है कि इस सरकार ने स्कूलों की अपग्रेडिंग में ज्यादती की है और बहुत से स्कूली टीचर्ज के बगैर चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि पहली बार छः साल के बाद स्कूलों में कालेजों में टीचर्ज और लैक्चर्ज की जो पोस्टें खाली थीं हमने तकरीबन उन सभी को भरने का पूरा प्रयास किया है। सभी पोस्टों की सैंक ान दे दी है और इनके लिए अब इन्टरव्यू भी हो गये हैं। भाायद अब कोई स्कूल ही ऐसा बचा होगा जहां टीचर्ज की कमी होगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कुछ भी इस बारे में नहीं सोचा था। हमने 181 स्कूलों की अपग्रेडिंग की बात एक साल मैं करने के बारे में कहा है। इनके समय में तो 20 या 25 स्कूल भी अपग्रेड नहीं हुए थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ि ाक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो लोगों को खु ा करने के लिए 350 स्कूलों को अपग्रेड करने की लिस्ट ही बनायी थी किन्तु स्कूल अपग्रेड नहीं किये थे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ि ाक्षा के मामले में तहेदिल से यह चाहती है कि हमारे

हरियाणा का कोई भी बच्चा अनपढ न रहे। इसलिए हमारी सरकार ने ि ाक्षा के लिए हर सुविधा जुटाने की कोि ा ा की है। गरीब और बैकवर्ड क्लासिज के बच्चे जो फीस नहीं सकते, वर्दी नहीं ले सकते, किताबें नहीं ले सकते हैं, ऐसे बच्चों की हमारी सरकार ने फीस मुफ्त कर दी है और वर्दी का इंतजाम किया है, किताबों का इंतजाम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने लडकियों की ि ाक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने पहले ही लडकियों की ि ाक्षा को बी0ए0 तक मुफ्त कर दिया था लेकिन अब सरकार ने महसूस किया है कि लडकियों को टैक्नीकल ऐजुके ान भी फ्री दी जाये। हमने लडकियों के लिए टैक्नीकल ऐजुके ान को अब फ्री कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ हमने यह भी फैसला किया है कि पहले जो लोग अपने बच्चों को पढाया नहीं करते थे लेकिन अब साक्षरता अभियान के तहत हमने यह फैसला किया है कि हरियाणा का कोई भी नागरिक अनपढ नहीं रहेगा। जो अंगूठा टेक लोग पहले हुआ करते थे अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। अब हरियाणा का हर व्यक्ति पढा हुआ होगा ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई व्यक्ति धोखा न कर सके। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने ला एंड आर्डर की बात भी की। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ला एण्ड आर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। पिछली सरकार के समय में लोग बहुत ही दुखी थे, यह हम ही नहीं कहते हैं बल्कि सारे हरियाणे के लोग कहते हैं। अगर हम यह बात कहें कि उस समय विकास

के कार्य नहीं हुए थे तो भाायद लोग बर्दा त भी कर लें लेकिन इनके समय में तो लोगों का जीना ही दूभर हो गया था, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिये गये थे, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जाता था। इस तरह इनके समय में लोग बहुत दुखी हो गये थे और कहते थे कि उनसे कौन सा ऐसा जुल्म हो गया है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। वे कहते थे कि जल्दी से जल्दी उन्हें इस सरकार से छुटकारा मिलना चाहिए। इस तरह से उन सभी गरीब लोगों की आवाजें भगवान के घर गयीं और लगभग साढे तीन साल के बाद ही प्रदे ा में इलैक ान हुआ और उस इलैक ान में हरियाणा की जनता ने इनके खिलाफ फतवा दिया। स्पीकर साहब, यह फतवा ला एंड आर्डर खराब होने की वजह से प्रदे ा की जनता ने दिया था हो सकता था कोई छोटी मोटी घटना घट जाती और वह इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रदे ा में बडे बडे डैकैत पैदा कर दिये थे, बडे बडे चारे पैदा कर दिये थे, बडे बडे ग्रीन बिग्रेड के सिपाही पैदा कर दिये थे। अब सरकार इन सभी को तला ा कर रही है। आज कोई नहीं कह सकता कि जमीनों पर कब्जे होते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला जाता है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी सौदा खरीद कर ताऊ के खाते में डाले।

श्री सतबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री जी बजट परी न बोलकर पर्सनल ऐलीगे ान लगा रहे हैं, गरीबों की जमीन पर कब्जे का जिक्र कर रहे हैं। एक

भी कब्जा ऐसा नहीं जो इन्होंने छुडाया हो। मौजूदा सरकार ने पलवल में म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर कब्जा किया है। होडल में जमीन पर कब्जा किया है। इस तरह के जो ऐलीगे ान लगाए गए हैं इन्हें एक्सपंज किया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सरकार के प्रयास से हरियाणा मैं आज लोग अमन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई आदमी किसी के सहारे तो नहीं बैठ सकता। श्री कृश्ण लाल ने दो तीन घटनाओं का जिक्र किया। इसी तरह से करनाल जिले में सालवना गांव का भी जिक्र किया और साथ में मेरे हल्के में भााहपुर एक गांव है उसमें हरिजन बाल्मिकी के कत्ल का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, इन तीनों केसों में पूरी कार्यवही हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाल्मिकी का कत्ल हुआ लेकिन किसने किया, कैसे किया इसका इन्होंनें जिक्र करने की कोि ा ा नहीं की। कत्ल करने वाले लोगों के बारे में तो इन्होंने बताया ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह कत्ल किया है वे इन्हीं के आदमी थे। वे यह समझते थे कि अब भी देवी लाल जी जैसा ही राज है वे इन्हीं के आदमी थे। वे यह समझते थे कि अब भी देवी लाल जी जैसा ही राह है किसी को कोई परवाह नहीं। अब वो पकडे गए हैं, एक मुलजिम को तो हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किय है, दो फरार होकर दूसरी स्टेट में भाग गए। उनमें से एक भी मुलजिम आज बाकी नहीं है सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री कृश्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। 30 अक्तूबर को उसका कत्ल हुआ था और 20 दिसंबर 1992 को पूरे प्रान्त की तरफ से बाल्मिकी समुदाय की तरफ से जींद के अंदर मांगे राम गुप्ता जी की कोठी के सामने प्रद र्ान किया था। अगर उस टाईम कातिल गिरफ्तार होते तो बाल्मीकी समुदाय की तरफ से धरना क्यों दिया जाता ?

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, श्री कृश्ण लाल ने फिर वही बात कह दी। वे मुलजिम उसी रात को फरार हो गए, रात का वाकया था। (ाोर)

श्री कृश्ण लालः हां, अध्यक्ष महोदय, वे इनके लोग थे उनको पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, इन्होंनें उन लोगों के नाम नहीं बताए। मैं नाम भी बता देता हूं। राहमेर, फूल सिंह एव चतरू ये तीनों जाट क्म्यूनिटी से संबंध रखते हैं और मैं पूरे एफीडेविट के साथ सदन में कह रहा हूं जो बाल्मीकी मरा है वह मेरा इलैक ानों में सपोर्टर और वोटर रहा जबकि यह तीनों मुलजिम हमे ाा मेरे खिलाफ रहे, कभी मेरे हक में नहीं रहे और मैंने अपने हल्के में कभी किसी बदमा ा चोर को पनाह नहीं दी और आज मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे हल्के में किसी की कब्जा करने की हिम्मत नहीं है न किसी बहू बेटी की

इज्जत पर हाथ उठाने की हिम्मत पड सकती है। मैं वो गुप्ता नहीं हूं जिसका हरियाणा भवन में पीट कर इस्तीफा ले लिया था।

सम्पत सिंह जी, मैं वह गुप्ता नहीं हूं जिससे नोट भी लेते हैं और वोट भी लेते हैं और फिर पीटकर उससे इस्तीफा ले लेते हैं। मैं वह गुप्ता हूं जिसकी रगों मैं भोरे पंजाब लाला लाजपतराय का खून दौडता है, जिसके भारीर के अंदर महात्मा गांधी का खून है। मैं आपके दबाव से चलने वाला नहीं हूं। मैने तो हमे ाा आपका मुकाबला किया है और आगे भी जैसा चाहूं कर सकता हूं। स्पीकर साहब, अमर सिंह ने हरिजनों की चर्चा की। उन्होंने चौपालों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार ने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों का वि ोश ध्यान रखा है। सर्विसिज के अंदर इनकी सरकार ने जो बैकलोग छोड दिया था उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। यह बैकलोग चाहे पुलिस में था, चाहे किसी नौकरियों में था, हमने उस बैकलोग को पूरा किया है। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लडकों को नौकरी दी जा रही हैं। इनके राज में जो कमी रह गई थी उसको पूरा किया जा रहा है। चौपालों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चौपालों के लिए पचास हजार रूपया कर दिया है जो पहले पच्चीस हजार होता था और मुरम्मत के लिए हमारी सरकार ने पच्चीस हजार रूपए किया है। हरियाणा सरकार सभी चौपालों को, चाहे वह धानकों की है चाहे चमारों की है और चाहे वह खटीकों की चौपाल है सबको

पूरा करेगी। कोई चौपाल अधूरी नहीं रहेगी सबको पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा गांवों में सेनीटे ान के लिए एक नई स्कीम के द्वारा एक लाख भौचालय हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। मल उठाने की जो पुरानी प्रथा थी, उसको जल्दी ही खत्म किया जा रहा है। बाल्मीकी जो पहले मैला उठाते थे, अब भविश्य में मैला नहीं उठाएंगे।

श्री राम कुमार कटवालः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने कहा है कि जींद में किसी प्लाट पर कब्जा नहीं है और न ही वहां पर कोई गुण्डागर्दी है। मैंने इस हाउस में वित्त मंत्री के बारे में एक फाईल रखी थी जिसमें प्लाटों के कब्जे का जिक्र था। प्लाटों का जो घपला था उसमें इस बात का जिक्र है। दूसरी बात यह है कि जींद के एस0पी0 श्री सिन्हा ने एक छापा मारा था जिसमें इनका लडका भी भाामिल था और उस लडको को थाने में बिठाया गया था। ये आज कैसे कहते हैं कि जींद में कोई गुण्डागर्दी नहीं है। आप इनके लडके के बारे में मिस्टर सिन्हा से पूछ सकते हैं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हो गई जैसे आपने भी यह मिसाल सुनी होगी "तेली ए तेली तेरे सिर पर कोल्हू।" तेली ने कहा कि तेल तो मिला नहीं तो जाट ने कहा कि बोझ से तो मरेगा। इसी तरह से इन्होंने अपने मुंह से बात निकाल दी। स्पीकर साहब, मेरा हाउस के अंदर चैलेंज है कि कोई भी ऐलीगै न चरित्रहीनता का या बेईमानी का लगा दें, अगर वह साबित हो जाए तो हमें इस कुर्सी से कोई प्यार नहीं है, हम इस

कुर्सी को छोड कर चले जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि हरियाणा के किसान को खेत में पूरा पानी मिले, लोगों को पूरा पीने का पानी मिले, हरियाणा के अस्पतालों में दवाईयां अच्छी मिलें, लोगों के लिए अच्छे साधन जुटाए जाएं जिससे कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे और जनता के हित के जितने काम हैं उनको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार पूरा प्रयास कर रही हे। हमारी पूरी कोि ा ा है कि आय के साधन बढाएं जाएं जिनसे जनता की भलाई के जितने काम हैं उनको पूरा किया जा सके। स्पीकर साहब, हरियाणा की जनता ने हरियाणा सरकार और कांग्रेस पार्टी में जो वि वास व्यक्त किया है, उसको यह सरकार पूरा करेगी और अगले चुनाव में इन लोगों की जमानत जब्त होगी। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा मेें सिविल वार की तरह सिचुऐ ान हो जाएगी, लोग सडकों पर आ जाएंगे और इनकी नींद हराम कर देंगे। इसलिए ऐसे हालत इनको नहीं करने चाहिएं। अगर ऐसा हो गया तो इनका दफतरों से निकलना बन्द हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए इनको लोगौं की नब्ज को समझना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बंसी लाल (तो ाम): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी मानते हैं और सरकार भी मानती है कि स्टेट में सूखे की स्थिति है। उससे निपटने के लिए सुझाव चाहिएं ताकि फौरी तौर पर सरकार जो सहायता कर सकती है, करे। सहायता यह कर सकती है कि भाखडा नहर का कुछ पानी, कुरूक्षेत्र जिले की तरफ,

करनाल और पानीपत तथा नरवाना सब डिवीजन को छोडकर जीन्द, सोनीपत, रोहतक और हिसार जिले का हांसी सब डिवीजन और फरीदाबाद, गुडगांव, भिवानी, रिवाडी, महेन्द्रगढ के इलाकों को, जहां सूखे की बहुत भयंकर स्थिति है, तथा जहां पर चारे का कोई प्रबन्ध नहीं है और मवेि ायों के मरने के पूरे आसार हैं, पहले प ु बाढ से मारे गये थे और अब भी सूखे के कारण मरेंगे, के लिए फौरी तौर से कुछ पानी भेजा जाना चाहिए ताकि लोग चारा पैदा कर सकें और रबी की फसल ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज तूडा का भाव 150 रूपये है। कल भी मैंने इसका भाव 150 रूपये बताया था लेकिन जब कल भााम को एक आदमी मुझसे मिला तो उसने कहा कि आपने तूडा का भाव 150 रूपये क्यों कह दिया ? इसका भाव तो 165 रूपये है। उपाध्यक्ष महोदय, एक रूपये 65 पैसे किलो के हिसाब से प ुओं को चारा खिलाना किसानों के लिए गरीब आदमी के लिए कोई आसान बात नहीं है। सरकार को फौरी तौर से सबसिडी देकर चारे का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके अलावा, दूसरी चीज यह है कि किसानों को जो कर्जा दिया हुआ है और जिसकी वसूली तेजी से चल रही है, उस वसूली को रोका जाये। जब किसान की अगली फसल यानी रबी की फसल अच्छी हो जाए तो यह वसूली आप कर सकते हैं। अगर रबी की फसल भी अच्छी नह हो तो उससे अगली खरीफ की फसल अच्छी होने पर इसकी वसूली कर सकते हैं, उससे पहले इसकी वसूली न की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा किसानों को अच्छी बिजली देनी चहिए, चाहे इसके लिए इंडस्ट्रीज

को पूरी तरह से बन्द क्यों ने करना पडे। स्टेट में आज भी कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं, भाायद मुख्य मंत्रजी को भी इसका पता होगा और आपको भी इसका अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए उन सब इंडस्ट्रीज की बिजली बन्द करके एग्रीकल्चर सैक्टर को देनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा लीडर आफ अपोजी ान ने बताया कि चौधरी अतर सिंह के पास ऐफेडैविट भी है लेनिक वह इस समय सदन में नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई ऐफेडेविट ऐसे हैं जिनमें बिजली के महकमें के लोग बगैर रि वत लिए बिजली के कनैक ान नहीं देते। हमारे जिले में आज बिजली की हालत यह है कि अगर कोई आदमी बिजली के कनैक ान के लिए आता है, तो उससे कहा जाता है कि पहले कमि नर के पिता के पास जाकर पैसा दो, तब जाकर उसको बिजली का कनैक ान दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। इसके अलावा पीने के पानी की सब जगह दिक्कत है, कमी है। मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र किया था कि सूखे के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए नारनौल, गुडगांव, भिवानी और फरीदाबाद आदि सब जगहों पर सरकार को पीने का पानी भेजना चाहिए तथा बाढ की वजह से जितने वाटर वर्क्स खराब हो गये हैं, जितने बैड खराब हो गये हैं, जो पानी के फिल्टर बैड ठीक नहीं हैं उनको सरकार को ठीक करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि जो लौंग टर्म पोलिसी है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जो स्टेट में वाटर लेवल नीचे चला गया

उसको ठीक किया जाये। मेरा ख्याल है कि 50–60 फुट से 100 फुट तक वाटर टेबल नीचे चला गया है, उसे ठीक करने का एक रास्ता यह है, सरकार को फौरी तौर से यह काम करना चाहिए कि वेस्टर्न यमुना कैनाल की कैपेसिटी बढाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, माईनर्ज, सब माईनर्ज की कैपेसिटी बढाएं और उनकी मुरम्मत कराएं। मानसून के दिनों मं करीब ढाई पौने तीन महीने यमुना नदी में खास पानी चलता है, वह पानी उन इलाकों में दिया जाये। इससे लोगों की फसल ठीक होगी, वाटर टेबल भी ऊपर आएगा और पानी भी री चार्ज होगा। इसके साथ साथ एक काम जो सरकार अगले साल तक पूरा कर सकती है, वह यह है कि दादुपुर नलवी नहर चलाई जाए इससे खरीब की फसल भी अच्छी होगी। आने वाली रबी की फसल का त करवा देने से लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसके साथ साथ भााहबाद मारकंडा, टांगडी दरिया है, इनको भी टेम करना चाहिए। ि ावालिक पहाडियों से आने वाले नदी नालों को टेम करना चाहिए। जिस समय मैं मुख्य मंत्री था उस समय राजस्थान में बरकतुल्ला खां साहब मुख्यमंत्री थे। हरीके से पानी पाकिस्तान को जाता है। मेरे और राजस्थान के मुख्य मंत्री के और दोनों स्टेटौं के सिंचाई मंत्रियों के दस्तखत हो गए थे कि पाकिस्तान को जो पानी जाता है वह हम हरीके के स्थान पर राजस्थान कैनाल में डाल देंगे। राजस्थान कैनाल से वह पानी हम सिरसा जिले में ले लें और सिरसा जिले में, जितने दिन वह पानी सरप्लस हो, उसे वैस्टर्न यमुना कैनाल के इलाकों को दे दें इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सिरसा जिले की ओटू झील

के ऊपर दस या पन्द्रह करोड रूपये खर्च करके, रेलवे लाइन से ऊपर ले जाकर, पूरी तरह से डीसिल्ट किया जाए तो उसमें से काफी इलाकों को पानी दिया जा सकता है। अब उसमें सिल्ट भर गई है, बाढ आई है, जिससे सिरसा जिले का बडा नुकसान हुआ है, भाहर को नुक्सान हुआ है, रतिया के इलाकों को नुक्सान हुआ है। मेरा सुझाव है कि ओटू झील के बारे में पूरा प्रोग्राम बनाकर 10–20 करोड रूपया खर्च करके उन इलाकों को सैराब किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि मैंने हरिद्वार से आगे गंगा नदी के पास भीमगौडा से करनाल तक, की नहर बनाने के लिए प्रौजेक्ट बनाकर भेजा था। इससे यह होगा कि जो पानी करनाल से नीचे जाता है, वह अम्बाला में, कुरूक्षेत्र के इलाकों में, यमुनानगर के इलाकों में इस्तेमाल हो सकता है, गंगा का पानी उसके नीचे के इलाकों में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से एस0वाई0एल0 के बारे में मुख्य मंत्री जी का स्टैंड कुछ और है, पंजाब के मुख्य मंत्री जी कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं कि एस0वाई0एल0 बनने का सवाल ही नहीं है। लीडर आफ दि अपोजी ान अभी इसके बारे में कह रहे थे। मुझे नहीं मालूम है कि सही स्थिति क्या है ? लेकिन किसी ने किसी तरह से कोि ा ा करके एस0वाई0एल0 बनवाई जानी चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें 2 मिलियन एकड फुट पानी हमारा है। स्पीकर सर, पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ है, मुख्य मंत्री जी पता कर लें कि यह बात कहां तक सही है ? यू0पी0 में एक भाारदा रिवर है, उस रिवर से भारत सरकार एक प्रोजैक्ट बना रही है, जिसका पानी

भाारदा नदी से लेकर पानीपत और सोनीपत के बीच यमुना नहीं में डालेंगे। दिल्ली को पीने का पानी देने के लिये मथुरा और आगरा जिलों की आबपा ाी के लिये वह प्रोजैक्ट बनेगा। मैं हरियाणा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आप भारत सरकार को चिटठी लिखें कि अगर ऐसा कोई प्रोजैक्अ हो तो उस प्रोजैक्ट में सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांवा जिलों को भी भाामिल कर लिया जाये। उस प्रोजैक्ट के खर्चे में जो भी हिस्सा हमारा आता हो, वह हम दे दें या फिर उसको सैंट्रल प्रोजैक्ट बनवा दें। उससे क्या होगा, सोनीपत, फरीदाबाद और गुडगांवा जिलों का काम चल जायेगा। इसके अलावा, वैस्टर्न यमुना कैनाल के पूरे सिस्टम की कैपेसिटी हम जितनी जल्दी बढा लेंगे, उतना ही हमें फायदा होगा। इससे पानी रिचार्ज होगा और वाटर टेबल भी ऊपर आयेगा। इससे लोगों को फायदा होगा। जवाहर लाल नेहरू कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बी0एन0 चक्रवर्ती कैनाल, जुई लिफट स्कीम तथा झज्जर लिफट स्कीम्ज ऐसी हैं जिनकी बहुत सी डिस्ट्रिब्यूटरीज, माईनर्ज और सब माईनर्ज बननी अभी बाकी हैं। वे हमे ाा सूखाग्रस्त इलाके होते हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में जहां डिस्ट्रिब्यूटरीज माईनर्ज और सब माईनर्ज बननी बाकी हैं, उनको बनायें ताकि लोगों को पानी का फायदा हो। मैं समझता हूं बारि ा के दिनों में अकेली वैस्टर्न यमुना से ही पूरी स्टेट को दो अढाई महीने तक आराम से पानी दिया जा सकता है। इसलिए जो लिफट इरीगे ान स्कीम्ज हैं, इन सब के लिये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनायें। जवाहर लाल नेहरू कैनाल

इरीगे ान की सबसे बडी लिफट स्कीम है। इसी तरह से इंदिरा गांधी कैनाल और बी0एन0 चक्रवर्ती कैनाल है। जुई लिफट स्कीम सबसे छोटी लिफट स्कीम है। इनके अलावा एक बात का मैंने मुख्य मंत्री जी से पहले भी अनुरोध किया था और अब भी करूंगा। कम से कम आजकल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम तो ठीक नहीं चल रहा है। मैं चेयरमैन को पर्सनली नहीं जानता नाम से तो जानता हूं लेकिन मैं उसको भाक्ल से नहीं जानता। मैं अभी इस बारे में आपसे यह अनुरोध करूंगा कि किसी फाइनैं ि ायल कमि नर को उस बोर्ड का चेयरमैन बना दें ताकि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम ठीक तरीके से चलने लगे। इस ढंग से चलने से क्या फायदा है ? इस बार तो ऐसे हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, राईस सूटस भी लोगों को अब तक नहीं दिये गये हैं। धान कटन पर आ गया है लेकिन स्अेट में लोगौं को राईस सूटस अभी तक नहीं दिये गये। इसलिये मेरा इस बारे में एक सुझाव है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि इरीगे ान के जो प्रोजैक्अस मैंने बताये हैं जैसे भीमगोडा, करनाल, हरीके से पानी लाना, एस0वाई0एल0 वाला, भाारदा रिवर वाला और ओटू झील वाले प्रोजैक्अस की तरफ सरकार ध्यान दे और सरकार को चाहिये कि वह जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने की कोि ा ा करके प्रोजैक्ट बनाये। प ाुओं के लिये जितनी जल्दी चारे का प्रबन्ध कर देंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर चारे का प्रबन्ध नहीं होगा तो मवे ाी मरने भाुरू हो जायेंगे। मवे ाी धन एक बहुत बडा धन होता है। इन भाब्दों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): यह जो इ ा आज हमारे सामने है मैंने इसके बारे में काल अटैं ान मो ान भी दियाथा। इस साल एक विचित्र बात यह हुई है कि बाढ भी आ गई और सूखा भी आया। वैसे तो यह सूखा सारे हरियाणा मे ंहै लेकिन हमारी तरफ ज्यादा है। जहां चावल बोया है, वहां पर भी सूखा पडा हुआ है। कहत की वजह से पानी की कमी है। मेरा लोहारू हलका थोडा सा तो भिवानी जिलें में है और कुछ महेन्द्रगढ जिले मे ंभी पडता है। मैं अभी 50–60 गांवों में जाकर आयी हूं। इन गांवों में एक ही बात सब जगह सामने आती है कि बिजली और पानी की कमी है। जब मैं बोल रही थी तो मैंने डिगवा पावर हाउस के ट्रांसफारमर के जलने की बात कही थी। मुझे खुद मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि पहले जो ट्रांसफारमर जल गया था, वह अब लग गया है लेकिन अब दूसरा एक और जल गया है। इस तरह बात तो वहीं की वहीं खडी रह गयी है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह हाउस की सैंस है कि हाउस का समय आधे घंटे के लिये और बढा दिया जाये ?

आवाजें: जी हां। बढा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: बैठक का समय आधा घण्टा बढाया जाता है।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, टाईम तो आधा घंटा ही बढायें लेकिन करीब आधा घंटे बोलने के लिये मुझे भी चाहिये। बाकी जितनी माननीय सदस्यों ने बातें कहीं हैं वह लगभग सारी बातें पहले आ चुकी हैं। उसका रैपीटी ान ही है। चन्द्रावती जी के 5 मिनट बोलने के बाद मेहरबानी करके आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है!

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात तो कहनी पडैगी कि आज सूखे की हालत प्रदे ा के अंदर है। प ाुओं के लिए चारा नहीं है उनके लिए चारा चाहिए। लोगों की मदद के लिए राहत कार्य फौरन भाुरू किए जाने चाहिएं। जोहडों की खुदाई होनी चाहिए, नहरों की डिसिल्टिंग होनी चाहिए, नहरों की मुरम्मत होनी चाहिए और स्कूलों की बिल्डिंग्ज जो लोगों ने बनाई थीं, उनकी हालत खस्ता है, उनको ठीक किया जाना चाहिए। आज खेतीहर मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि दांती डालने के लिए घास भी नहीं रही। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के बिना कुछ नहीं होगा। बिजली की हालत यह है कि पंजाब में और हमारे पास दो दो पावर हाउस थे। हमारे पास एक थर्मल प्लांट पानीपत में है और दूसरा

फरीदाबाद में है। हमारी हालत यह है कि फरीदाबाद में जो आधा थर्मल प्लांट है, उसको भी हम पूरा नहीं कर पाए। पंजाब में दो पूरे हो गए और दो और बन रहे हैं। भाायद वे भी पूरे हो गए हैं और एक और बन रहा है। इस तरह से वे पांच पर आ गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली की कंजम्प ान बढ रही है और टयूबवैल्ज की गिनती भी बढी है लेकिन बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं बढा है। यह नहीं होना चाहिए। यमुनानगर में प्रधान मंत्री जी ने रिमोट कंट्रोल से पावर हाउस की नींव तो रख दी लेकिन सचमुच में पावर हाउस बनेगा या नहीं यह ई वर जानता है। उपाध्यक्ष महोदय नकीपुर जो लोहारू में है के लिए पावर हाउस की प्रोपोजल है। बाढडी जो सतनाली के पास है के लिए भी पावर हाउस की प्रोपोजल है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सतनाल का पावर हाउस 33 के0वी0 से 132 के0वी0 का किया जाए। यह बैल्ट मीठे पानी का है इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस एरिया में पावर हाउसिज बनाए जाएं ताकि बिजली की समस्या हल हो सके। आज बिजली की बहुत बुरी हालते हैं आज अगर बिजली की चोरी रूक जाए तो किसानों को ज्यादा बिजली मिल सकती है। अगर करप ान रूक जाए तो सारे काम ठीक ढंग से हो सकते हैं और जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। आज करप ान और इनऐफी ैंसी हैंड इन ग्लोव है। पैसा लिए वगैर आज फाइल ही नहीं निकलती। अफसर लोग इसी इंतजार मे ंरहते हैं कि पैसा आए तो फाइल निकाली जाए। गुडगांव में अंग्रेजों के वक्त नौ बांध थे आज उनका बुरा हाल है। कुछ पर लोगों ने कब्जा कर

लिया। भी ावाल पिचापा और बादल गांवों में बांध होते थे वे सब डैमेज हो गए हैं। हमारे यहां बाढडा में बांध होते थे लेकिन वे सब खत्म हो गए। मेरा कहना यह है कि उन अफसरों के खिलाफ ऐक ान लिया जाना चाहिए जिन्होनें इन्हें खुर्दबुर्द होने दिया। उन अफसरों को सजा देनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बोरिंग टयूबवैल्ज की बुरी हालत है। पता नहीं सरकार ने कितने बौर्ड बना दिए। एम0आई0टी0सी0 बना दिया और कहीं कोई और बोर्ड बना दिया। फाइल पर बोर्ड बना हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। (ाोर एवं व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप इस प्रदे ा के मुख्य मंत्री हैं आपको दिल्ली के दौरे कम रखने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके किनारे पर और जमुना के किनारे पर सब जगह पेड लगाने चाहिए। अगर पेड लगेंगे तो पानी कम सूखेगा। जहां झील है उनके चारों तरफ पेड लगने चाहिए ताकि पानी कम सूखे। चकबन्दी के समय मुरब्बा बन्दी हुई थी, लेकिन जोहडों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। गांव में जोहड छोडने चाहिए। वहां से प ाु पानी पीते हैं लेकिन जोहड न होने के कारण अब सारा प्रै ार नहरों पर आ गया है। अगर मेरे इन सुझावों पर सरकार अमल करे तो जनता की बहुत भलाई हो सकती है।

प्रो0 राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने यह तो स्पीकार किया है कि हरियाणा के अन्दर

बिजली की कमी और अकाल से गम्भीर स्थिति पैदा हुई है। 40 करोड रूपया इसके लिये एलोकेट किया है। आज एक सवाल के जवाब में यह बताया गया कि 464747 हैक्टेयर भूमि इससे प्रभावित हुई है और पूरे चार पांच जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल सुजै ान्ज देना चाहता हूं कि इस सारी स्थिति से निपटने के लिये बिजली के जनरे ान का बढाया जाना बहुत ही जरूरी है। हम जिन इलाकों से आते हैं वहां सिंचाई की समस्या नहीं है, वहां पीने के पानी की भी समस्या है। जब तक पावर जनरे ान नहीं बढेगी तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। मुख्य मंत्री महोदय ने खुद माना है कि स्थिति चिन्ताजनक हैं पावर जनरे ान बढ नहीं रही और मांग ज्यादा बढ रही है। आज से तीन चार साल पहले लोगों की जितनी डिमांड थी, अब उससे ज्यादा हो गई है। प ाुओं के लिए चारा काटने वाला टोका है, वह भी आज बिजली से चलता है और भाानी बनाई जाती है। आटा बिजली पीसती है। लिफ्ट इरीगे ान सिस्टम जो हमारे तीन चार जिलों में है वह तब चलते हैं जब पूरी बिजली दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के पडौसी राज्यों में कहीं पर भी बिजली की कोई कट नहीं है। कल इस सदन में इस मसले पर चर्चा हुई थी कि किसी भी जगह पर बिजली की कटौती नहीं है। हिमाचल में बिजली की भाार्टेज नहीं है। हिमाचल, सरप्लस इलैक्ट्रीसिटी स्टेट है और समय सयम पर प्र ाासन ने ईमानदार

तरीके से पावर जनरे ान को बढाने के प्रयास किये हैं और बिजली का प्राइवेटाईजे ान किया है। जिस तरह राजस्थान में भैरां सिंह सरकार ने किया उसी तरह से हिमाचल में श्री भाान्ता कुमार की सरकार ने प्रयास किये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हरियाणा के अन्दर भी पावर जनरे ान को बढाने के प्रयास किये जाने चाहिए। अभी हरियाणा के अन्दर श्री राजपाल जी को इलैकट्रीसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। ठीक किया, वे टैक्नीकल आदमी हैं, उनको इसकी ज्यादा नालिज है। परन्तु अब तक जितने पावर मिनिस्टर बने हैं, उनमें सबसे बढिया चौधरी वीरेन्द्र सिंह रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी की सरकार में वे मिनिस्टर रहे हैं और लोगों ने यह माना है कि हरियाणा के अन्दर बिजली अगर सबसे ज्यादा मिली है तोउसी समय में मिली है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को यह विभाग दे दिया जाए ताकि इस समय हरियाणा जो बिजली के संकट से गुजर रहा है, वह दूर हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें आज किसान के हितों की पूरी चिन्ता है। और उनके बारे में जो कुछ हम ईमानदारी से महसूस करते हैं वहीं सुझाव हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं ए0सी0 चौधरी जी का विरोध किसी और कारण से नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनको अभी पावर जनरे ान का अनुभव नहीं है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने यह विभाग बहुत देर तक, बहुत वर्शों तक देखा है और उन्होंने कुछ उपलब्धियां भी

करके दिखायीं हैं। यदि मुख्य मंत्री जी की पावर जनरे ान बढाने की सचमुच में कुछ इच्छा है, तो जो जो सुझाव यहां सदन में आए हैं उनकी तरफ अव य ध्यान देवें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो इलाका है वह टेल का इलाका है। वहां पर नारनौल, महेन्द्रगढ, नागंल सिरोई में 36 एम0वी0, 66 एम0वी0 ट्रांसफामर्ज था उस को उठाकर सरकार ने डबवाली भेज दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हमारे इलाके में बिजली पहले ही कम आ रही है और इसके बावजूद भी सरकार ने ऐसा कर दिया। नांगल सिरोई का जो पावर स्टे ान है, वहां लोग आते जाते हैं और कर्मचारी बेचारे डर के मारे आते जाते नहीं हैं। (ाोर)

श्री मनी राम केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (ाोर)

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, किस बात का प्वायंट आफ आर्डर ये उठा रहे हैं ? मुख्य मंत्री महोदय मेरी सारी बातों का जवाब देंगे। डबवाली मैंने कह दिया और इनको चिढ लग गई। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मनीराम जी ही सारी जानकारी रखते हैं और हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। (ाोर)

श्री मनीराम केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, पंडित जी अभी कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर एक जगह से उठा कर दूसरी जगह दे दिया। जहां से उठाया है वह भी जगह हरियाणा में है

और जहां ले जाया गया है, वह भी हरियाणा में है। यहां तो ऐसा भी देखने में आया था कि जिन लोगों पर हरियाणा के लोगों ने वि वास किया था, उनहोंने हरियाणा के ट्रांसफार्मर यू0पी0 में भेज दिये थे। अब वह बात तो नहीं हो रही।

प्रो0 राम बिलास भार्मा : ऐसी बात नहीं है कि मैं डबवाली के बारे में बुरा सोचता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि यह इलाका टेल पर है। पीछे एक योजना चली थी कि कनीना और महेन्द्रगढ के पावर हाउस दिल्ली से जोड दिये जाएं। परन्तु उसके लिए भाायद पैसा नहीं दिया गया क्योंकि उसके साथ इनफरास्ट्रकचर की बात आई। कनीना, महेन्द्रगढ और रेवाडी के 40 हजार के लगभग तो पुराने टयूबवैल्ज हैं और इन सालों में जो नए लगे हैं, उनकी संख्या अलग है। तो जो भाखडा की लाइन यहां से जाती है, वह दादरी तक जाते जाते क्रिपल डाउन हो जाती है, इसलिए वहां के पावर हाउसिज को दिल्ली के साथ जोडा जाए।

वक्फ राज्य मंत्री (चौधरी भाकरूल्ला खां): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो मेवात का नाम नहीं लिया और न ही मेवात के मन्दिरों को तोडने की बात कही है तो भाई भाकरूल्ला जी परे ाान किसलिए हो रहे हैं ?

चौधरी भाकरूल्ला खां: अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी मेरे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। अब ये बी0जे0पी0 के प्रैजीडैंट नहीं रहे, इसलिए भाोक प्रस्ताव पास किया जाए। (हंसी)

प्रो0 राम बिलास भार्मा : मैं चौधरी भाकरूल्ला खां का आभार मानता हूं कि वे मेरी इतनी चिन्ता करते हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि मैं सर्व सम्मति से प्रदे ा का दो बार अध्यक्ष बना हूं। प्रदे ा की राजनीति की बात को लेकर मैंने स्वयं त्याग पत्र दिया है। आप चिन्ता न करें इससे कोई फर्क नहीं पडता।

Mr. Deputy Speaker: Ram Bilas Ji, you will have to concede or point that he is very considerate to you.

प्रो0 राम बिलास भार्मा : ये मेरा ख्याल रखते हैं इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। मैं कह रहा था कि यह जो टेल का इलाका है, इसको दिल्ली के साथ जोडने की बात है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे को दोबारा भजन लाल जी ने प्रधान नहीं बनने दिया और राम बिलास जी को इसलिए हटाया गया कि ये भजन लाल जी से मिले हुए थे। (हंसी)

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो चौधरी भजन लाल से चौधरी बीरेन्द्र सिंह का दर्द है, मुझे कोई इस कारण से नहीं हटाया गया, मैंने तो स्वयं त्याग पत्र दिया है।

इनको भजन लाल से ि ाकायत हो सकती है, मुझे अपने लीडर से कोई ि ाकायत नहीं है। तो मैं गुजारि ा कर रहा था कि मेरा इलाका टेल का है। उस इलाके के लोगौं से रिप्रजैंटे ान आई थी और उसके आधार पर एक योजना विचाराधीन हुई थी। इस बार बारि ा नहीं हुई है और नहरों का पानी नहीं आ रहा है। अगर वह योजना अशाढी की फसल से पहले चालू न की गई तो दो जिलों के लोग परे ाान हो जाएंगे। वहां के पावर हाउसिज को दिल्ली के साथ जोडने का काम पूरा हो चुका था। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर बजट की कोई नई एलोके ान करके, इन दो जिलों को बचाने की तरफ ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ भिवानी और रिवाडी जिले का वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। भाायद दूसरे जिलों के लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि दूसरे जिलों में यह समस्या कम है, लेकिन खास तौर से महेन्द्रगढ जिले का, रिवाडी जिले का और भिवानी जिले की लोहारू तहसील का वाटर लैवल, 300–400 फुट नीचे चला गया है। एक योजना 1979 में बनी थी कि साइफन से नहर का पानी नीचे उतार सकते हैं। जो पुरानी नदियां आती थी, दोहान नदी और कृश्णावती नदी, उनमें बरसात के दिनों में नहरों का सरप्लस पानी डैरोली जाट गांव के क्षेत्र में छोडा गया था वह योजना अब बंद हो गई है। उस पानी से, उस क्षेत्र मे ंपानी छोडने से बडी मात्रा में किसानों के टयूबवैलों का पानी ऊपर आया था। मैं निवेदन करूंगा कि अब भी उन नदियों में पानी छोडा जाए ताकि उससे 20–25 गांवों के किसानों को राहत मिल सके क्योंकि

पानी छोडने से उस क्षेत्र के किसानों के टयूबवैलों का पानी ऊपर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं चारे से संबंतिध बात कहना चाहूंगा। यह सरकार पता नहीं किसानों से संवेदन भून्य क्यों है। सिरसा में हम गए। सिरसा की मंडी में लगभग 50 गोडाउन थे, जिनमे ंखल थी, गेहूं थी और सरसों थी, वह सारे का सारा अनाज बाढ के पानी के कारण सड गया। व्यापारियों ने उस सडे हुए अनाज को बाहर डाल दिया। उस सडे हुए खल अनाज को खाकर 100 गऊएं मर गईं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच का विशय है।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा): आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई।

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है और वहांपर 100 गाएं मरने की बात है। मैं यह बात बडे कांफीडैंस के साथ कह रहा हूं। मैं वहां 23 जुलाई को गया था। मैंने ला ाों को देखा है और लोगों से मिला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर अरोडा साहब यह कहते हैं कि मेरी बात असत्य है, तो आप इनके साथ अपोजी ान पार्टी का एक विधायक, वहां पर भेज दें, वह वहां जाकर पता कर लेंगे कि वहां पर 100 गाएं मरी थी या नहीं।

श्री लछमन दास अरोडा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को चेलेंज करता हूं वहां पर कोई गाय नहीं मरी।

प्रो0 राम बिलास भार्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे कांफीडैंस के साथ यह बात कह रहा हूं। कोई भी इस बारे में जांच कर लें। जहां जहां पर बाढ का पानी आया, वहां वहां पर प ाुओं में बीमारी फैली है। प ाुओं में गल घोटू की बीमारी खराब पानी पीने से और कम चारा खाने से फैली है। उन ईलाकों में एनीमल हसबैंडरी की मोबाइल टीम तुरंत जाकर प ाुओं में जो बीमारी फैली है, उसका उपचार करे। जिन ईलाकों में बाढ है, जिन ईलाकों में सूखा पडा है वहां पर सरकार सबसीडाइज्ड रेट पर चारा उपलब्ध कराए।

चौधरी जिले सिंह (साल्हावास) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रदे ा में सूखे की भयंकर स्थिति बनी हुई है, जब कि पिछले दिनों बाढ से भी काफी नुकसान हुआ। बारि ा होने की वजह से जहां बाढ आई, वहां हमारी तहसील झज्जर की जमीन रेतीली होने के कारण मुंह बन्द कर गई इसलिए वहांपर अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले दिनों कोसली के प ाु मेले में पानी का एक एक मटका 6–6 रूपये में बिका, दूसरी तरफ सारी फसल तबाह हो गई। जहां एक ओर ज्वार बाजारा और ग्वार सूख गया उनके लिए पानी नहीं है वहीं दूसरीतरफ पीने के पानी की बडी भारी समस्या बनी हुई है। अगर सरकार ने जल्दी ही झज्जर, रिवाडी और महेन्द्रगढ की ओर ध्यान नहीं दिया तो वहां पीने का पानी नहीं मिलेगा। उस इलाके में वाटर लेबल कम से कम 100

फुट नीचे चला गया है। वाटर को रीचार्ज करने के लिए जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने भी कहा कि डब्ल्यू0जे0सी0 का पानी वहां बरसात के दिनों में दिया जाए और यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे अपने जिले में 30 दिन में से सिर्फ 3 दिन नहर चलती है। पिछले दिनों 25 तारीख को नहर आई थी और 28 तारीख को बन्द हो गई थी। एक महीने में अगर 3 दिन पानी चलेगा तो उससे सिंचाई तो क्या होगी पीने का पानी भी पूरा नहीं हो सकेगा। एक ओर पीने के पानी की समस्या है, वहीं दूसरी ओर, पानी न होने की वजह से फसलों का भी नुकसान हो रहा है। झज्जर सब ब्रांच नहर की डी सिल्टिंग नहीं हुई है, उसके दो पम्प हाउस अखेडी मदनपुर और लाडैन बन्द पडे हैं ओर इसके आगे झांसवा वाटर सप्लाई और जमालपुर वाटर सप्लाई है उनमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उस नहर की डीसिल्टिंग कब करवाएंगे और जो पम्प हाउस हैं इनको कब तक चालू करेंगे। इसके साथ ही साथ जे0एल0एन0 कैनाल से 3–4 माईनर्ज निकलती हैं निका 90 प्रति ात से ज्यादा काम हो चुका है। झांसवा माईनर पर चार छोटे छोटे पुल बनने हैं। अगर वे पुल बन जाएं तो कम से कम 6 गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मोहन बाडी में, पिछल बार मोर मर गए थे। पानी के बिना प ाुपक्षी पागल हो रहे हैं और लोग 4–4 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हो गये हैं। अगर झासंवा माईनर के 3–4 पुल बन जाते हजैं तो 5–6 गांवों के पीने

के पानी की समस्या हल हो सकती है। इन गांवों का सारे का सारा पानी खारा है। इसी तरह से खाचरोली माईनर है उस पर सिर्फ 2 पुल बनने हैं अगर इनको बना दिया जाए तो 3–4 गांवों को पीने का पानी मिल सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, सिंचाई तो बहुत दूर की बात है हमारे यहां तो पीने के पानी की भी भारी समस्या है इसतिलए सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। साल्हावास माईनर का भी 80 प्रति ात काम हो चुका है, इसको जल्दी पूरा करवाया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक बिजली का सवाल है, वहां पर बिजली का अन डिवलेयरड कट है। 5 बजे से 7 बजे तक तो डिक्लेयरड कट है लेकिन उसके बाद रात के 11–12 बजे तक बिजली नहीं आती अगर आती भी है तो बहुत ही डिम आती है। किसान यह समझता है कि बिजली पूरी आ रही होगी। जब वह टयूबवैल चलाता है तो उसकी मोटर जल जाती है क्योंकि दिन में लाईट आती नहीं और रात को आती भी है तो डिम आती है जिसकी वजह से खेतों में टयूबवैलों की मोटरें जल जाती हैं और किसान का बहुत नुकसान होता है। मेरे हल्के में पिछले दिनों 20 मोटरें जल गई जिससे किसानों का बहुत नुक्सान हुआ। बिजली की चोरियां भी होती हैं। लोगों को तंग भी किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सैक्टर में विजिलैंस के छापों से लोगों को परे ाान किया जा रहा है। किसी के घर पर थरै ार खडा है, मोटर पडी है तो उसको उठा लिया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, सेलंगा

गांव की बात है, किसान के पास आटा पीसने की चक्की भी थी और अपना थरै ार भी था, उसकी मोटर को उठा ले गए और कहने लगे कि तुम यहां पर थरै ार चलाते हो, जबकि थरै ार वह अपने खेत में चलाता था। मेरे हल्के में कई नाजायज केस पकडे हुए हैं और कई जगहौं पर लोगों को हरास और परे ाान किया गया है। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इण्डस्ट्रियल सैक्टर में ऐसी चोरियों को डिटैक्ट करने के लिए छापे मरवाए गए हैं ? हमारी सरकार के टाईम में फरीदाबाद और गुडगांव जिलों में इण्डस्ट्रियल एरिया की 100 करोड रूपये की चोरियों को पकडा गया था परन्तु इनकी सरकार ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करके, उनको छोड दिया। इसी प्रकार से डिप्टी स्पीकर साहब ट्रांसफारमर बगैर पेसे लिए और बगैर लालच के 2 महीने से पहले बदला नहीं जाता है। 2 महीने में भी तब बदला जाता है जब कन्ज्यूमर या टूयबवैल्ज वाले या गांव वाले एस0डी0ओ0 या जे0ई0 को पैसा दें, तब वह ट्रांसफारमर बदला जाएगा और उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट अपनी ले जानी पडती है। अपने वहीकल्ज ट्रांसफारमार्ज लाने के लिए इस्तेमाल करनी पडती है जबकि सरकार कहती है कि रूल्ज में प्रोवीजन है कि वे ट्रांसफारमर्ज सरकार खर्चे पर ले जाकर वहां लगाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। कंज्यूमर्ज चंदा इकटठा करके ट्रांसफामर्ज लगवाते हैं। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, अब पब्लिक हैल्थ विभाग द्वारा वाटर सप्लाई का सवाल है। आज न तो बिजली है और न ही पानी है। यह सब न

होने की वजह से जो पब्लिक वाटर वर्कस हैं उनके लिए बिजली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के कई गांव हैं जैसे साल्हावास, नीलोखेडी और वीरोहड इनके अन्दर छोटे छोटे वाल्व दो दो महीने से नहीं हैं। अगर वह डेढ दो सौ रूपए का वालव लग जाए तो टंकी में पानी चढ सकता है। मैंने एक्सियन से कहा कि टंकी भर के पानी चलाया करें, वह बोला कि वालव नहीं है। मैंने कहा कि परचेज कर लो तो उसने कहा कि पैसे नहीं हैं। डेढ दो सौ रूपये के लिए हजारों लोग परे ाान हों, यह बहुत ही भार्म की बात है। इसलिए वे जो बाल्ज हैं वे बदले जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, वाल्ज न होने की वजह से जो बिजली रात में आती है उससे टंकी मे ंपानी नहीं चढ पाता और दिन में बिजली आती नहीं है जिसके कारण नलके बन्द पडे रहते हैं, इसलिए यह सुधार करवाया जाए। साथ ही जहां जहां पर पब्लिक हैल्थ वालों की मोटरें जली पडी हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। पानी की समस्या एक अहम समस्या है। पीने का पानी बहुत ही आव यक है। मेरा हल्का झज्जर तहसील में है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग ट्रैक्टर में गाडियों में पानी की टंकियां भर के लाते हैं। अब भी यह हाल है कि कोसली की मण्डी में दो रूपए का मटका बिक रहा है। यह बडे ही भार्म की बात है। मैंने जब एस0डी0ओ0, पी0एच0 कोसली से पूछा कि कम से कम पीने का पानी तो मुहैया करवाओ, तो कहने लगे कि बिजली नहीं आती। मैंने कहा कि तुम्हारे यहां नांगल में तो इंजन भी लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इंजनों के लिए तेल के पैसे नहीं हैं। उपाध्यक्ष

महोदय, बिजली तो है नहीं और इंजन लगे हैं लेकिन तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है।। इससे भार्म नाक और क्या बात हो सकती है ? यह मौजूदा सरकार आम जनता को पानी नहीं दे सकती। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव और इस सरकार को देना चाहूंगा कि कुछ इलाके पानी में डूबे हुएहैं लेकिनर वहां पर लोग फसल नहीं बीज सकते। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाएिह कि जहां पर फलड है वहां से उस पानी को निकालैं और नहरों के जरिए जहां पर सूखा है, वहां उस पानी को पहुंचाया जाए। ऐसा करने से दोनों जगह फसल हो सकती है। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और जलदी सख्त कदम उठा कर यह कार्य करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली 28 तारीख को श्री के0सी0 भार्मा, कमि नर साहब जमालपुर में गए और लोगों ने उन्हें कहा कि यहां पर पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं, आप यहां पर पानी का अरेंजमैंट करवाएं। के0सी0 भार्मा जी ने लख्मी चन्द रागनियों की कई कैसेटस बनवा रखी हैं। इसका नाम है– 'लख्मीचन्द की प्रेमधारा', 'ज्याति सतबीर का प्रेम'। मैं यह बात सच कह रहा हूं। वे कैसेटस लोगों को, बी0डी0ओज कोआप्रेटिव बैंक को, तहसीलदार को और सरपंच को देते हैं। और उन्हें कहते हैं कि कम से कम सौ सौ कैसेटस तो आप हमारी बिकवा दो। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इनके अधिकारी ही व्यापार करेंगे तो

जनता का क्या सुधार करेंगे ? इस बात में अगर कोई संदेह हो तो आप इस मामले की इन्क्वायरी करवा सकते हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः अगर हाउस के सदस्य सहमत हों तो हाउस का समय आधे घंटे के लिये और बढा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी, बढा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः हाऊस का समय आधा घण्टा और बढाया जाता है।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी जिले सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा सरकार को यह बताना चाहता हूं कि मेरे हल्के में पांच गांव ऐसे हैं जिन्हें वाटर सप्लाई नहीं किया गया जबकि पिछले सै ान से सरकार दावा करती रही है कि हरियाणा सरकार ने 6735 गांवों में पानी दे दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, साल्हावास, बिहरोड, लूलाहेडी, जमालपुर, ढालनवास, गोरिया और एक गांव लूखी जो जाटूसाना हल्के का है, इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर इन गांवों में आज तक पानी गया हो या वहां पर कोई पब्लिक हैलि का पाईप दबा रखे हों तो ये मुझे बता दें। ये ऐसे ही कह रहे हैं

कि 6735 गांवों को पानी मुहैया करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसे ही कह देते हैं कि इन्होंने इतने गांवों को पीने का पानी दे दिया है। इसके साथ ही एक तरफ आज टिडडी दल का खतरा भी प्रदे ा में बना हुआ है दूसरी तरफ सूखे के लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। इससे पहले फल्ड के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फल्ड से कितने मकान ढह गये और कितने लोग बह गये सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि टिडडी दल कहीं प्रदे ा में न आ जाए और इससे किसान न मारे जाएं। किसान तो पहले ही फल्ड के कारण मारे गये, और अब वे सूखे के कारण मर रहे हैं। उनकी फसलें बर्बाद हो गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। (इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खडे हो गये)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी बैठिये। सभी पार्टीज के सदस्येां के प्वायंटस आ गए हैं, इसलिए अब मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री कृश्ण लालः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने के लिए पांच मिनट चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो कल सै ान चलना है ये कल बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सूखे की स्थिति को लेकर चिन्ता व्यक्त की है। (ाोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको

बैठाईये। ये कल बोल सकते हैं तथा कल ही अपने हल्के की बातों के साथ साथ यह बात भी कह सकते हैं। ये सारी बातें तो कल ही आ गयी हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिये। चन्द्रावती जी, क्या आप बोल चूकीं ?

श्रीमती चन्द्रावतीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सभी सदस्यों को अपने हल्के की बातें कहनी हैं। जिन लोगों ने कालिंग अटैं ान मो ांज दे रखे हैं, उनको तो अंडर रूल आपको बोलने के लिए समय देना ही चाहिए, चाहे इसके लिए आपको और समय क्यों न बढाना पडे।

श्री अध्यक्षः सभी पार्टियों के काफी सदस्य बोल चुके हैं, इसलिए अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, यह बडा गंभीर मुददा था जिस पर चर्चा हो रही है और अब यह फलड के बाद आया हुआ सूखा है। दोनों तरफ गंभीर संकट है। इस पर हाऊस में पिछले दो घंटे से डिस्क ान चल रही है लेकिन ट्रैजरी बैंचिज के लोग थपथपी पीट रहे थे, यह बडी भार्म की बात है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने सूखे के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की है और यह चिन्ता का विशय है भी। इस बात से सारे प्रदे ा के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के अधिकाररी चिंतित हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल तो यह है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता दी गई है या नहीं।

वाक आउट्स

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे हं, अतः मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए।)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहले तो भयंकर बाढ आ गई। कल बाढ के बारे में साढे तीन घंटे चर्चा हुई और उस चर्चा में ढाई घंटे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं और एक घंटा मैंने जवाब दिया। बात तो लगभग उसी से मिलती जुलती है क्योंकि बरसात हुए डेढ महीना हो गया है, उसके बाद बरसात नहीं आई। जब बरसात नहीं आती तो प्रदे ा के सामने बडी भारी दिककत आ जाती है चाहे वह प ाुओं के चारे की हो . ..... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अमर सिंह जी, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर सर, आपने आदे ा दिया था कि जो इस बार में एडजर्नमैंट मो ान थी उसे काल अटैं ान मो ान में कनवर्ट कर दिया गया है और पार्टी के हरेक मैम्बर को ज्यादा से ज्यादा समय बोलने के लिए मिलेगा। हमारी पार्टी की तरफ से सिर्फ चौधरी बंसी लाल जी 10 मिनट बोल कर गए हैं, और किसी मैम्बर को टाइम नहीं मिला है। हमारी पार्टी के एक सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गए हैं अतः एज ऐ प्रोटैस्ट हम भी सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय श्री अमर सिंह, श्री राम भजन अग्रवाल, प्रो0 छतर सिंह चौहान, श्री पीर चन्द और श्री ओम प्रका ा जिन्दल सदन से वाक आउट कर गए।)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, अभी चौधरी अमर सिंह जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी की तरफ से सिर्फ चौधरी बंसी लाल जी 10 मिनट बोले हैं, बाकी किसी और सदस्य को समय नहीं मिला। असल में चौधरी बंसी लाल ही बचेंगे। बाकी तो सारे कांग्रेस में आना चाहते हैं।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः बंसी लाल जी कैसे बचेंगे, उनका तो सारा परिवार ही कांग्रैस में है। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि बरसात न होने की वजह से प्रदे ा में बिजली का भी संकट है। किसान भी बडा परे ाान हो जाता है जब 6 महीने बाद भी कोई फसल न आए। बेचारा कहीं से उधार लेकर काम चलाता है बैंक लोन लेता है, पता नहीं कितने ही मसले किसानों के सामने होते हैं। बरसात न हो तो कितना भी नहर का पानी हो, उसमें कमी आ जाती है, कितना भी पानी हो, बरसात न होने से फसल आधी हो जाती है। प्रदे ा में वाकई सूख पडा हुआ है। सरकार की तरफ से जो बात हम कर सकते हैं उसमें हम कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे। पहले माननीय सदस्यो ंने कई बातें कहीं हैं जैसे श्री ओम प्रका ा बेरी ने बिजली के कनैक ान और ट्रांसफार्मर के बारे में कहा है। जहां तक तूडे के भाव का संबंध है, हम इस संबंध में अनाउंसमैंट करने जा रहे हैं। लोन की वसूली की चर्चा मैं बाद में करूंगा। सम्पत सिंह जी ने नहरी पानी और बिजली की बात कही है। एक बात उन्होंने यह कही कि बिजली के मामले को लेकर डिमांस्ट्रे ान हो रहे हैं, घेराव हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि कई जगह ऐसा है। लोग भाायद यह समझते हैं कि बिजली भाायद दफतर में होगी जहां से वे ले लेंगे। भाायद वे यह समझते हैं कि बिजली यह दे सकते हैं। बिजली की समस्या अकेले हरियाणा प्रदे ा में ही नहीं है बल्कि सारे मुल्क में है। सारे दे ा में कट हे, 8–8 घंटे का कट लग रहा है। कोई भी ऐसा प्रदे ा नहीं है

जहां बिजली का कोई कट न हो। हमने किसानों को बिजली देने के लिये जितने भी फरनेसिज चलते हैं, उनको बंद कर दिया हैं इस तरह से जो हमें 30–35 लाख यूनिटस बिजली मिली है, वह किसानों को दी है। अभी कल ही मैंने बिजली की सप्लाई के मामले में पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितनी ज्यादा बिजली दी गयी है, इस बारे में आंकडें दिये हैं। इस बात को सारा सदन जानता है कि हमने ज्यादा बिजली देने की पूरी कोि ा ा की है लेकिन सूखा पडने की वजह से दिक्कत ज्यादा आ रही हैं। अगर बारि ा हो जाती तो वन फोर्थ बिजली से भी काम चल सकता था, क्योंकि तब जमीन गीली होती हैं जब जमीन गीली हो तो थोडी बिजली से भी काम चल जाता है लेकिन जब जमीन बिल्कुल सूखी पडी हो तो उसे गीला करने के लिए चार गुना ज्यादा पानी लगता है। जिस जमीन को एक टयूबवैल दो घंटे में 4 एकड में पानी भर पाता है वहीं पर सूखी जमीन में वही टयूबैवल मुि कल से 4 घंटे में एक एकड में पानी भर पाता है। सूखी जमीन पानी ज्यादा लेती है। स्पीकर साहब, आप तो किसान हैं, आपको तो बहुत ज्यादा पता है। एग्रीकल्चर के मामले में अगर मैं आपको डाक्टर कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। यह जो डिमांस्ट्रे ान्ज होते हैं उनमें अगर मैं यह कहूं कि हमारे लोगों का हाथ भी रहता है तो कोई गलत नहीं होगा। सियासी आदमी अपने स्वार्थ सिद्धी के लिये लोगों को बहकाने की बात करते रहते हैं। लोगों को यह समझना चाहिये कि असलीयत में बात क्या है, सरकार की नीयत ठीक है या नहीं। हमारे माननीय सदस्यों को

इस तरह के सुझाव देने चाहियें ताकि हम इस समस्या को हल कर सकें।

प्रो0 सम्पत सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि हमें सुझाव देने चाहिये। तो मैं सुझाव ही दे रहा हूं। इनहोंने यहां पर कहा कि सियासी लोग ही ऐसी बातें करते हैं। इनको भाायद याद हो या न हो, इनके खुद के पावर मिनिस्टर ने जब यह महकमा संभाला तो संभालते ही फरीदाबाद में इनका जब स्वागत हुआ, तो इन्होंनै कहा कि वे 5 मिनट में बिजली की समस्या हल कर सकते हं, अगर दिल्ली को बिजली देनी बन्द कर दी जाये तो .....

श्री ए0सी0 चौधरीः मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। (व्यवधान व भाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः फिर आपको कन्ट्राडिक्ट करना चाहिये था ?

चौधरी भजन लालः आप क्या बात करते हो। क्या बिजली हरियाणा दिल्ली को देता है ? आप भी इस महकमे के वजीर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार से हम बिजली लेते हैं। एन0टी0पी0सी0 से हम बिजली संगरोली के माध्यम से लेते हैं पता नहीं ये लोगों को क्यों गुमराह करते हैं ?

प्रो0 सम्पत सिंहः 29 तारीख के दैनिक जागरण में यह बयान छपा है।

श्री ए0सी0 चौधरीः इन्होंने छपवा दिया होगा। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लालः पानी के बारे में तो ये कह सकते हैं क्योंकि पीने के लिये हम उनको पानी देते हैं लेकिन बिजली के बारे में यह कैसे कह सकते हैं, जबकि हम दिल्ली की सरकार से बिजली लेते हैं ? उनको देते नहीं हैं (व्यवधान व भाोर)

श्री सतबीर सिंह कादियानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। प्रो0 सम्पत सिंह ने जो दिल्ली को बिजली देने की बात कही। जो आरोप उन्हौंने लगाया है वह इस तरह से हो सकता है कि एन0टी0पी0सी0 से और भाखडा से अपना भोयर ही हरियाणा न ले और उस भोयर को वह दिल्ली को दे दे। गर्मियों में हरियाणा अपना भोयर दे दे और सर्दियों में अपना हिस्सा ले ले।

चौधरी भजन लालः कादियान साहब, आदमी को जिस लाइन की जानकारी न हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। जिस चीज की जानकारी हो उसी की बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, हमारे भोयर से ज्यादा बिजली लेते हैं और बिजली उनसे खरीदते भी हैं। पैसा उनको देते हैं और खरीदने पर भी हमको बिजली नहीं मिलती; और वह इसलिए कि आप जैसे लोग किसानों को बहकाते हैं कि बिल का पैमैंट मत करो। स्पीकर साहब, पैसे दिए बगैर बिजली मिलती नहीं है। सम्पत सिंह ने कहा कि पेहवा में लोगों को गिरफतार किया गया। स्पीकर साहब, कोई भी

आदमी यदि कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जहां तक बिजली की चोरी का सवाल है यह बात बिलकुल सही है। कल हमारी पार्टी मिटिंग में भी यह मामला डिस्कस हुआ था। कल डेढ घंटा तक बिजली का मामला डिस्कस हुआ था कि बिजली के मसले का कोई हल निकाला जाए। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की मीटिंग आज चार बजे बुलाई है। उसमें यह डिस्कस होगा कि बिजली की चौरी कैसे रोकी जा सकती है और बिजली बोर्ड जो आंकडे देता है, वह सही हैं या नहीं ?

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, पावर की कमेटी बनी है और इरीगे ान की कमेटी भी बनी है। उसमें टोटल मिनिस्टर और एम0एल0एज0 रूलिंग पार्टी के हैं। आप उस कमेटी में अपोजी ान के एम0एल0एज0 को भी भाामिल करें और उनके सुझाव प्राप्त करें। जो डिपार्टमैंट के मिनिस्टर हैं वे उन कमेटीज के चेयरमैन हैं। इन कमेटीज में चार पांच मिनिस्टर हो गए और एक दो एम0एल0एज0 हैं अगर आप अपोजी ान के मैमबर भी भाामिल कर लें तो आपको अच्छे सुझाव मिल सकते हैं।

चौधरी भजन लालः हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जो अच्छे सुझाव होंगे, उनको माना जाएगा। हम कमेटी में एक दो मैम्बर आपके भाामिल कर सकते हैं। स्पीकर साहब, यहां यह कहा गया कि चोरी की वजह से कनैक ान काट दिए जाते हैं। अध्यक्ष

महोदय, अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसका कनैक् ान तो काटा ही जाएगा .....

प्रो0 सम्पत सिंहः मैं तो गांव के कनैक् ान काटने की बात कह रहा था।

चौधरी भजन लालः इसका भी कोई कारण हो सकता हैं स्पीकर साहब, यहां पर ट्रांसफारमर्ज रिप्लेस करने की बात आई और कहा गया कि चीफ इंजीनियर के यहां से दिए जाते हैं स्पीकर साहब ट्रांसफारमर्ज के बारे में नीचे लैवल पर एक्स0सी0ए0 को अधिकार है वह चेंज कर सकता है। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि एक आदमी से पांच हजार रूपया लिया गया .....

प्रो0 सम्पत सिंहः भोर सिंह फ्रीडम फाइटर हैं जिससे पांच हजार रूपया लिया गया, उसने ऐफीडेविट भी दिया है।

चौधरी भजन लालः आप मेहरबानी करके लिखकर दें। ऐफीडेविट मुझे नहीं मिला है। अगर आपके पास है, तो मुझे दे दें।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः चौधरी साहब, ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में वह ऐफीडेविट डिप्टी कमि नर की मौजूदगी में श्री ए0सी0 चौधरी को दिया था।

श्री ए0सी0 चौधरीः वह 13 अगस्त को दिया था। उसकी इंक्वायरी के आर्डर्ज किए हुए हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः प्रोफेसर साहब, आपको ऐफीडेविट देने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही कागज पर लिख कर दे दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे। अगर सही बात होगी तो हम अव य ही कार्यवाही करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान) दूसरा प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने कह दिय कि यमुना नगर के अंदर कब काम होगा, क्या होगा ? अगर मैं कुछ कहूंगा तो इनको तकलीफ होगी। बिजली बोर्ड का प्रोग्राम था यमुना नग्र के अंदर थर्मल प्लांट लगाने का लेकिन जब इनका राज आया इनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि इनहोंने वह प्रोजैक्ट ही एन0टी0पी0सी0 के हवाले कर दिया।

श्री अध्यक्षः वह जमीन किसने ऐक्वायर की थी ?

चौधरी भजन लालः जमीन हमने ऐक्वायर की थी। हमने वह प्रोजैक्ट बनाया था और हमारा बना बनाया प्रोजैक्ट इनहोंने एन0टी0पी0सी0 के हवाले कर दिया। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, चार साल इनका राज रहा लेकिन जो प्रोजैक्ट बनने जा रहा था, उसको इन्होंने कुएं में धकेल दिया। हमने आने पर एन0टी0पी0सी0 से बात की और जब वे नहीं माने, यह मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूं फिर हमने उनको चिटठी लिखी कि या तो आप 15 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला कीजियेगा नहीं तो हम अपना प्रोजैक्ट अपने हाथ में ले लेंगे। तो इना करने पर वे जरा तेज हुए और उसके बाद बाहर की कंपनियों के साथ नेगोि ाऐ ान हुआ, कुछ कंडी ांज के साथ नेगो ीिऐ ान चला। काम भुरू हो रहा है, एग्रीमैंट हो रहा है। (ाोर) अध्यक्ष महोदय, यह काम जल्दी

भाुरू होने वाला है, पत्थर रखा गया है। एक इन्होंने हिसार व फरीदाबाद के बारे में भी कहा। उसका बाकायदा एम0ओ0यू0 साईन हो गया है। उस पर भी एग्रीमैंट बहुत जल्द होने वाला है। इसी तरह से इन्होंने फरीदाबाद गैस बेस्ड प्रोजैक्ट का भी जिकर किया इसको जापान गवर्नमैंट बनाएगी तकरीबन सारा मामला तय हो चुका है और काम भाुरू होने जा रहा है। साथ में इन्होंने एस0वाई0एल0 के बारे में भी कहा है कि 1986 में कितना काम हुआ, 1987 में 1988 में कितना हुआ, 1990 में कितना हुआ और 1991 में कितना काम हुआ। इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ मेरे वक्त में काम हुआ था, जो काम हम भाुरू करवा के गये थे, उतना ही रहा। जितना पैसा हम देकर के गये थे उससे ज्यादा पैसा नहीं दिया गया इनके राज में। यह सब कुछ इनके राज में नहीं हुआ। जब भजन लाल चीफ मिनिस्टर था तब यह सारा काम भाुरू हुआ था और वही काम चलता रहा। (ाोर) इसके लिए पैसा भी हमने ही भारत सरकार से तय करवाया था। हमारे जाने के बाद इनकी सरकार ने एस0वाई0एल0 का कुछ काम नहीं किया। भारत सरकार ने करवाया और 95 परसैंट काम इस नहर पर हम करवा के गये थे (ाोर) अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह से भाोर नहीं करना चाहिए जरा इत्मिनान से सुनना चाहिए। हम इनके बीच में कभी नहीं बोले। बहुत दिन हो गए हैं इनको हाउस में बैठे। इनको जरा यहां बैठने की सभ्यता भी सीखनी चाहिए। इनको हिमाकत समझनी चाहिए। (ाोर) इनको यहां बैठकर कुछ सीखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बात

होती है तो इनके मैम्बर और ये खुद बीच में उठ कर बोलने लगते हैं (ाोर) अध्यक्ष्ज्ञ महोदय, मैंने पहले भी कहा कि 95 परसैंट नहर का काम हम कर गये थे। भोश काम के लिए भारत सरकार से बातचीत चल रही है और बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर वह नहर बन जाएगी, देर का सवाल नहीं है। बात नजदीक लगी हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बात का और जिकर कर दिया कि चूंगा गांव के अंदर पीने के पानी की जो पाईप लाईन जाती थी। वह उखाड दी गई। मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह लाईन बीच में से खराब हो गई थी उसकी मुरम्मत करवा दी गई है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसको पहले हमने भाुरू किया और फिर बाद में उसको उठा दें। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने तो बीच में ऐसे ही बातें करनी हैं इसलिए इनकी बातों का जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। चौधरी बंसी लाल जी ने कुछ बातों के बारें में बहुत अच्छे सुझाव दिए और मैं इनके अच्छे सुझावों की ताईद करता हूं। इन्होंने बिजली और इंडस्ट्री के बारे में कहा और वाटर लैवल नीचे चले जाने के बारे में कहा। यह बात कुछ हद तक ठीक है। नहरों में पानी डाल कर कुछ कर सकते हैं और इस पर भी विचार किया जा सकता है। दादुपुर नलवी नहर की स्कीम बाकायदा बन चुकी है लेकिन इस नहर का काम तभी भाुरू करेंगे जब एस0वाई0एल0 कैनाल पर काम भाुरू हो जाएगा। क्योंकि एस0वाई0एल0 नहर का पानी जिस एरिया में जाएगा, अब उस एरिया को जो पानी यमुना

का जाता है, उसको काट कर वह पानी वहां देंगे, तब जाकर दादुपुर नलवी कैनाल में वैस्टर्न यमुना कैनाल का पानी जा सकता है। इसलिए वह नहर बनती जरूरी है। जयों ही वह बनेगी, उस इलाके में नीचे का पानी दे देंगे और ऊपर पानी रोक कर यमुना का इस इलाके में दे देंगें। इन्होंने हरिके ा से राजस्थान की बात कही है। हमने ओटू झील को भी ठीक किया और उसका बांध भी ऊंचा किया लेकिन उसमें सिलट इतनी आती है कि वह एक साल में भर जाती है। एक इन्होंने भारदा रिवर से पानी आ सकने की बात कही। भीम गोडा का भी जिक्र किया। ये स्कीमें कुछ समय पहले बनी थी लेकिन बाद में कह दिया गया कि इसका लैवल ठीक नहीं है, फिर कही लिफट लगानी पडेगी। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं इनको भी हम दिखाएंगे। जो भी उचित बातें इन्हौंने कहीं हैं उनको हम जरूर करने की कोि ा ा करेंगे। हम इनके अच्छे सुझावों को मानते हैं। चन्द्रावती जी ने पावर हाउस की बात कही थी कि उसकी कैपेसिटी बढाई जाए। मैं बाढडा के बारे में बहिन जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर 132 के0वी0 के सब स्टे ान पर काम चल रहा है और वह तीन चार महीने मैं चालू हो जाएगा। राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि नारनौल से पावर उठा कर डबवाली में ले गए .....

श्रीमती चन्द्रावतीः नकीपुर पहाडी पर एक स्टोन रखा गया था उसके बारे में क्या कर रहे हैं ?

चौधरी भजन लालः इसको भी दिखाएंगे। जो बात होने वाली है उसको हम करेंगे। राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि उनका टेल का एरिया है और वहांपर वाटर लैवल नीचे चला गया है, यह भी ठीक बात है।

एक आवाजः ट्रांसफार्मर उठाने वाली बात तो बता दो।

चौधरी भजन लालः कहीं से उठा कर लाने का सवाल नहीं है। या तो कहीं पर बडा लगाना हो या वह छोटा पड गया होगा, इसलिए कोई चेंज करने की बात हो सकती है।

श्री कृश्ण लालः पानीपत में एक किसान को टयूबवैल का अभी कनैक ान नहीं मिला है, लेकिन बिजली का 17 हजार रूपए का बिल आ गया है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः कोई इंडीविजयुल बात है तो वह मन्त्री जी को अलग से बताएं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, पंजाब में तो पावर हाउस 5–6 बन गए हैं जबकि हमारे यहां केवल दो ही हैं, इसक क्या कारण है ?

चौधरी भजन लालः आपकी बात ठीक है लेकिन बात पैसे की है। हरियाणा प्रदे ा सारे दे ा में अकेला प्रदे ा है जो किसान को ज्यादा बिजली देता है। पांजब किसानों को 45

प्रति ात बिजली देता है और हम 62 प्रति ात देते हैं। इस तरह हर यूनिट के पीछे एक रूपए का हमें नुकसान होता है।

श्री धीरपाल सिंहः इसके बावजूद भी गांवों में बिजली का बहुत अभाव है ?

चौधरी भजन लालः मैं खुद मानता हूं कि अभाव है, लेकिन अभाव का असली ईलाज तो तब होता है जब परमात्मा साथ देता है। लेकिन हमें यह देखना पडेगा कि किसान अपने बिल दें। अगर वे बिल नहीं देंगे और बिजली की मांग करेंगे तो बिजली कहां से बनेगी, अगर नए प्रोजैक्ट नहीं लगेंगे। नए प्रोजैक्ट पैसे से बनते हैं। आपने तो उनको बहुत बहकाया कि बिल मत दो।

श्री धीरपाल सिंहः वे किसान आपके मित्र हैं। एस0जे0पी0 ने कभी भी किसानों को नहीं कहा कि बिल मत भरो।

चौधरी भजन लालः चलो, ठीक है। चौधरी जिले सिंह ने जे0एल0एन0 के बारे मैं कहा कि इसमें तीन चार माईनर्ज का काम 95 प्रति ात हो चुका है। (विघ्न)

(इस समय श्री कृश्ण लाल सदन के वैल में जाकर एक बिजली का बिल दिखाने लगे और उन्होंने बतायाकि पानीपत के एक किसान को अभी बिजली का कनैक ान नहीं मिला है लेकिन उसका 17 हजार रूपए का यह बिल आया है।)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य के कहने का मतलब यह है कि उसको बिजली का कनैक ान नहीं मिला है और बिजली का बिल आ गया। (ाोर)

चौधरी भजन लालः माननीय सदस्य मंत्री जी से मिल लें और उनको बता दें, इसमें क्या दिक्कत है ?

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सहमत हों तो हाउस का समय 10 मिनट के लिये और बढा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी, हाउस का टाईम 10 मिनट और बढा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः हाऊस का टाईम 10 मिनट बढाया जाता है।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महहोदय, तीन चार माइनर्ज का 95 परसैंट काम हो गया है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, जहां पर पीने का पानी कुओं से सप्लाई करते हैं जिनको वाटर लैवल नीचे चला गया है उनका बिजली का खर्च बेहद आता है। उनका खर्चा आम

टयूबवैलों के खर्चे के अनुसार आना चाहिए। उनकी कन्जम्प ान भी आम टयूबवैल के अनुसार होनी चाहिए डोमैस्टिक कन्जम्प ान के हिसाब से नहीं होनी चाहिए।

चौधरी भजन लालः ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जिन माइनर्ज का 95 परसैंट काम हो चुका है, उनका बाकी काम जल्दी ही पूरा करवाएंगे। इसके अलावा तीन चार पुलौं के बारे मे ंबात कही है कि उन पुलों को बनाने से पांच छः गांवों में पीने का पानी चला जाएगा। हम उन पुलों को भी जल्दी ही पूरा करेंगे। इसके अलावा, बिजली की चोरी रोकने के लिए और ट्रांसफारमर्ज के बारे में मैंने बता दिया है। इस बारे में हमने आज भााम को भी एक मीटिंग रखी है। माननीय सदस्यों ने टिडडी दल का भी जिक्र किया है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने एक बात कमि नर रोहतक के बारे में कही कि कमि नर रोहतक श्री के0सी0 भार्मा ने लखमीचन्द की रागनियों की कैसेटस बेचने के लिए अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियेां को दी हैं। इन्होंने यहां पर भी वह कैसेट दिखाई हैं। अध्यक्ष महोदय, लखमी चन्द कोई मामली आदमी नहीं थे, मैं कहूंगा कि वे बहुत भाानदार कवि थे। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जिनके कारण इस प्रदे ा के लोग उनका सम्मान करते हैं। टी0वी0 वगैरह तो अब आए हैं, उन दिनों लोग नाच गाने देखा सुना करते थे। मैं यह कहता हूं कि नार्दन इंडिया में लख्मी चन्द एक टाप के इन्सान थे, यह गलत बात नहीं है। कमि नर रोहतक के बारे में यह बात कहना कि वह बी0डी0ओ0,

एस0डी0ओ0 तहसीलदार या किसी दूसरे को यह कहता है कि आपको कैसैटस आकर लेनी हौंगी। यह बात उनको भाोभा नहीं देता। जो औफिसर यहां हाउस में अपने आपको डिफैंड नहीं कर सकता, उस औफिसर पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिएं। (ाोर)

श्री जिले सिंह जाखड़: मैं जानना चाहूंगा कि श्री के0सी0 भार्मा ने ये कैसेटस किस खु ाी में बंटवाई हैं ? अगर इन कैसेटस को उनका बेचने का इरादा नहीं था तहसीलदार को या मिनि बैंाकें से पैसा नहीं लेना है, तो क्यों बंटवाई ? अगर कैसेटस बंटवानी थी तो आम पब्लिक में बंटवा देते, लेकिन यह हार्ड फैक्ट है कि उन्होंने कैसेटस बेचने के लिए सरकारी कर्मचारियों के जिम्मे काम लगाया है कि आपको इतनी कैसेटस देनी हैं, आपको इतनी कैसेटस देनी हैं अगर उन्होंने कैसेटस नहीं बेचनी थी तो किस लिए बनवाई हैं ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसको दिखवा लेंगे। अगर यह सही बात है तो इसको हम चैक करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कमि नर का यह काम नहीं है। हम सारी बातें देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, बाढ के बारे में मैंने कल बता दिया था और आज भी एक क्वै चन था, उसका हमने जवाब दिय है, इसलिए इस बारे में दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। सूखे की जो दिक्त है उसमें 3–4 बातें आती हैं। सबसे पहली जो दिक्कत आती है, वह प ाुओं के पीने के पानी की दिक्कत है। हमने बाकायदा सारी स्टेट के अन्दर यह आदे ा दे दिए हैं कि प ाुओं

के पानी पीने के जितने भी तालाब हैं वे भरवा दिए जाएं। कहीं पर भी कोई ऐसा तालाब न हो जो भरा हुआ न हो। गांव की पंचायतें, अगर कहीं पर इस काम में दिलचस्पी न लें तो अधिकारी, खुद दिलचस्पी ले कर हर हालत में तालाबों को पानी से भरवाएं ताकि प ाुओं को पीने के पानी की कोई दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है प ाुओं के चारे की। हमने यह फैसला किया है कि चारा चाहे कहीं से मिले, वहीं सें लाया जाए। तूडी जहां से मिले, लोग ला सकते हैं। उस पर 50 परसैंट सबसिडी देंगे और ट्रक पर लाने में जो किराया भाडा लगेगा, उस पर भी 50 परसैंट सबसिडी देंगे। बाकी का 50 फीसदी जो पैसा है, वह तकावी की भाक्ल में जब फसल आएगी, तब उनसे वसूल किया जाएगा। यह फैसला हमने किसानों और गरीबों के हित में किया है। हमने बाकायदा हिदायतें जारी कर दी हैं कि डी0सी0 चारा वगैरा खरीदने में लोगौं को मदद दें। इसके साथ साथ ऐग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायरिटी दे कर बिजली दी जाएगी। हमारे पास जितनी बिजली अवेलेबल है वह हम कृशि सैक्टर को देंगे, चाहे उसके लिए हमें 15 दिन के लिए इंडस्ट्रीज को बंद ही क्यों न करना पडे, हम बंद करेंगे। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें लेबर काम करती है और खाने पीने की चीजें बनती हैं या आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें बनती हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा ताकि आम आदमी को कोई दिक्कत न हो। बाकी की जो बडी इंडस्ट्रीज हैं अगर वे सारी बन्द करनी पडी तो वह भी करेंगे ताकि किसान को पूरी बिजली मिल सके।

श्री अध्यक्षः बंद करने की तो अब जरूरत है, अगर अब बंद नहीं करेंगे तो फिर कब बंद करेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आज भााम को ही हमने इसके बारे में एक बैठक बुलाई है।

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आने वाले हर सम्मानित सदस्य को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और चेयर की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सही तथ्य जनता के सामने भी आने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं यह तो मानकर चलता हूं कि यह नैचुरल कैलेमिटी है इनकी वजह से नहीं हुई। सरकार ने अखबार में लम्बा चौडा इ तहार दिया है, वह कितना सच है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। मुख्य मंत्री जी आंकडे भी बता रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं आन ए प्वायंट आफ आर्डर पर खडा हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी के सामने तथ्य गलत आए हों, इनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर तथ्य सही नहीं है तो उनको बोलते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि असत्य न बोला जाए। स्पीकर सर, आपके आसन के ऊपर खम्बे पर और मुख्य मंत्री जी के सामने लिखा है– इस हाउस में आकर सत्य बोला जाए। स्पीकर साहब कल भी चर्चा हुई थी ओर आज भी चर्चा चल रही है। जो आंकडे दिए गए हैं, उनमें हरियाणा की सरकार सच बोलती या केन्द्र की सरकार सच बोलती है उसका

निर्णय स्पीकर साहब, आप स्वयं करेंगे। मैंने कल भी यह बात कही थी आज फिर पढ कर सुना रहा हूं। राज्य सभा के सम्मानित सदस्य श्री दलीप सिंह दूबे ने प्र न पूछा था, मैं इसकी डिटेल में न जाते हुए जो सरकार की तरफ से जवाब मिला है कि किन किन स्टेटस में इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को घाटा है, उसमें आता हूं। हरियाणा प्रदे ा के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1225 करोड 21 लाख रूपए का घाटा बताया गया है, जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी कल भी इस बात पर वजिद थे कि 720 करोड रूपए का घाटा हैं इन्होंने कल कहा था कि झूठ बोल रहे हैं वैसे भी 'झूठ' भाब्द अन पार्लियामैंटरी है लेकिन यह असत्य है। मैं आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि क्या असत्य कह कर हाउस को गुमराह किया जा सकता है ? स्पीकर साहब, अब दोनों बातें आपके सामने हैं आप स्पयं इस बात की पडताल कर लें कि हरियाणा सरकार असत्य कहती है या केन्द्रीय सरकार असत्य कहती है ? अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी इस पर भी रो ान डालें और इसकी इन्क्वायरी करके बताने की कृपा करें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस के सदस्य सहमत हों तो हाउस का समय दस मिनट के लिये और बढा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाऊस का समय दस मिनट के लिए बढाया जाता है।

राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति से संबंधित नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आंकडें दिए थे वे सही हैं और उनमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरे ये 1225 करोड रूपये का जिक्र कररहे हैं इसमें कई चीजें हैं– लोन पुराना भी इसमें है, कुछ दूसरी चीजें भी हैं और लौसिज भी हैं टयूबवैल्ज की बोरिंग के जो लोन लेते हैं उसका हिसाब किताब अलग है। कोई आदमी अगर लोन लेकर काम करना चाहे तो वह इस घाटे में भाामिल नहीं होगा। घाटे में वह भाामिल होता है कि कोई चीज किस भाव में बनती है और किस भाव में बिकती है। इसमें जो घाटा होता है, वह रकम घाटे में भाामिल होती है। वह घाटा 735 करोड रूपए का है। अध्यक्ष महोदय, इन्हें थोडा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बोरिंग की बात अलग है और घाटे की बात अलग है।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह घाटा 12 सौ करोड रूपए है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमैंट से इन्फर्मे ान ली जाती है और स्टेट गवर्नमैंट इन्फर्मे ान देती भी है। जितने भी बिजली बोर्ड हैं उनमें कितना कितना घाटा है ? यह सवाल कलीयर कट घाटे का है, लौजिस का है। लोसिज की

बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और लौसिज की ही बात चौटाला साहब कर रहे हैं। कल मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि घाटा सात सौ कुछ है और पार्लियामैंट में इन्हीं की सरकार ने जो जवाब दिया है, वह 12 सौ करोड रूपए का है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं। वह जो बता रहे हैं बोरिंग को मिला कर के है। मैं लोन की बात कर रहा हूं।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, लोन अलग चीज है यह सवाल तो लौसिज का है।

श्री अध्यक्षः चौटाला साहब ने तो क्वै चन पढ कर नहीं बताया था, सिर्फ जवाब ही पढ कर बता दिया। जो भी इन्फर्मे ान है, वह बिजली बोर्ड की दी हुई होगी।

चौधरी ओम प्रका ा चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं क्वै चन भी पढ सकता था परन्तु मैंने हाऊस का समय बचाने की कोि ाश की है। साथ ही यह क्वै चन अंग्रेजी में था। अगर मैं पढ देता तो मुख्य मंत्री जी समझ नहीं सकते थे, इसलिए भी मैंने यह रियायत करने की कोि ा ा की थी। अब आप ही यह पढकर सुना दें, और अध्यक्ष महोदय, सुना ही ने दें बल्कि इन्हें समझा भी दें कि प्र न क्या था और उसका क्या जवाब है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रका ा चौटाला तो डबल एम0ए0 और पी0एच0डी0 हैं, इस बारे

मैं तो मैं ज्यादा जानता नहीं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जिस भजन लाल ने दोनों बाप बेटे को पढा रखा हो, वे आदमी यहां आकर भजन लाल को ऐसा कहें ? अध्यक्ष महोदय, इन्हें कुछ तो भार्म करनी चाहिए। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, फलड वाले एरिया पर, जहां जहां पर जरूरत है वहां के लोगों को हम जे0आर0वाई0 के तहत रोजगार दैगें, काम देंगे। उसके लिए हम पैसे सी0आर0एफ0 से लिफ्ट करने जा रहे हैं ताकि लोगों की तकलीफ दूर की जा सके और रोजगार दिया जा सके। जहां तक वसूली का ताल्लुक है उस बारे में हम आज ही फैसला करने जा रहे हैं कि हम इस बार वसूली को मुलतवी कर देंगे और उससे अगली फसल में वसूली करेंगे।

श्री धीर पाल सिंहः क्या आने वाली फसल के बारे में कह रहे हैं ?

चौधरी भजन लालः जी हां, मैं आने वाली फसल के बारे में ही कह रहा हूं।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं सरकार को लास्ट सुझाव देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने बडे वायदे भी किए हैं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इन्होंने जो वायदे किए हैं, उनके बारे में कुछ होना ही नहीं है, इसलिए एक वायदा और कर लें कि जिससे सारा क्ले ा ही खत्म हो जाएगा कि ये राम जी को फोन कर लें कि बारि ा कर दें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने टेलीफोन परमात्मा को किया था और कहा था कि अब इस बाढ को बन्द करो और उन्होंने टेलीफोन सुन भी लिया था, लेकि अब उनका टेलीफोन खराब हो रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं भाब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

***2.46*P.M.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. Wednesday, the 1st September, 1993).

ANNEXURE – 'A'

Illegal possessionof Panchayat Land of Village Dhani Jatan

***587. Sh. Mani Ram Keharwala:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether the panchayat land of village Dhani Jatan of District Sirsa is under illegal possession of some one; and

(b) if so, the total acreage of land thereof ?

विकास तथा पंचायत मंत्री (राव बंसी सिंह):

(क) ग्राम पंचायत धानी जाटान की कोई भाामलात भूमि अवैध कब्जे में नहीं है। परन्तु ग्राम पंचातय धानी जाटान की 155 एकड 2 कनाल 2 मरले भाामलात भूमि जो कृशि योग्य नहीं है, में से भूमि खसरा नं0 269, 279/1, 286, 303, 310/20 जिसका रकबा 36 कनाल 18 मरले है अधिसूचना दिनांक 23–12–1988 द्वारा नगरपालिका ऐलनाबाद को स्थानान्तरित की गई थी। खसरा नं0 310/20 व 286 मिन की भूमि जो अब नगरपालिका ऐलनाबाद की मलकियत है पर 6 व्यत्यिों को अवैध कब्जा है।

(ख) खसरा नं0 310/20 व 286 मिन जो कि नगरपालिका ऐलनाबाद की मलकियत है और निम्न 6 व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है, का रकबा 5 कनाल 15 मरले है :–

क्रमांक	अवैध कब्जे किये गये	खसरा नं0	रकबा

	व्यक्तियों के नाम		कनाल	मरले
	सर्व श्री–			
1	भोपाल सिंह पुत्र राम जी लाल –यथोपरि–	310/20 मिन 286 मिन	1 1	05 13
2	साधू राम जरनैल सिंह पुत्र रामू राम	310/20	0	18
3	ओम प्रका ा पुत्र उदमी राम	उक्त	0	10
4	राजा राम पुत्र चन्दा राम	उक्त	0	06
5	जगदी ा पुत्र मालू राम	उक्त	0	08
6	गूगन, मदन लाल पुत्र ज ाहरा	286 मिन	1	05